हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

अच्छे बजट की ओर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से अनेक संभावनाएं जाग उठी हैं। कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सुखद तस्वीर यह सर्वेक्षण पेश कर रहा है। ऐसा लगता है, हम 1 फरवरी, अर्थात आगामी रविवार को विकासोन्मुख बजट की उम्मीद कर सकते हैं। तमाम विकराल चुनौतियों के बावजूद बीतता हुआ वित्त वर्ष भारत के लिए ठीक-ठाक रहा है और आगामी वित्त वर्ष में भी उम्मीद की किरणें प्रबल रहेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक, सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। जैसे बाहरी व आंतरिक तनावों से यह अर्थव्यवस्था गुजर रही है, उसमें करीब सात प्रतिशत विकास दर बहुत उत्साहजनक है। इससे निवेशकों का मनोबल बढ़ेगा। हम कैसे भुला दें कि भारत के बड़े व्यापार साझीदार अमेरिका ने लगभग दुश्मनी भरा रवैया अख्तियार कर रखा है? इसके बावजूद भारत की तरक्की का पहला इशारा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने अनावश्यक रूप से झुकने की जरूरत नहीं है।

यह दर्ज करने लायक बात है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात (वस्तु और सेवाएं) रिकॉर्ड 825.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया और वित्त वर्ष 2026 में भी यही गति रहेगी। भारी अमेरिकी टैरिफ के बावजूद अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान उत्पाद निर्यात में 2.4 प्रतिशत और सेवा निर्यात में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज दुनिया और खासकर अमेरिकी विशेषज्ञों को यह देखना चाहिए कि भारत की तरक्की पर लगाम लगाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। भारत एक आर्थिक ताकत बनने की ओर लगातार कदम बढ़ा रहा है। हां, यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि अगर दुनिया में युद्ध नहीं चल रहे होते, अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं होता, तो भारत के विकास की रफ्तार दस प्रतिशत से भी ज्यादा रहती।

बाहरी व आंतरिक तनावों से भारतीय अर्थव्यवस्था गुजर रही है, उसमें करीब सात प्रतिशत विकास दर उत्साहजनक है। इससे निवेशकों का मनोबल बढ़ेगा।

ताजा आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि विभिन्न सरकारी प्रयासों और मौद्रिक उपायों के चलते खुदरा महंगाई में कमी का क्रम बना हुआ है। लगे हाथ यह भी गौर करने की बात है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि आई है।

आर्थिक सर्वेक्षण भविष्य संवारने को भी उत्सुक दिख रहा है। इसका संकेत साफ है, भारत की विकास योजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की जरूरत है। यह भी संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार अपने बजट में निवेश, रोजगार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर ज्यादा गौर करेगी। उद्योग जगत को बल देने के प्रयास बजट में नजर आएं, तो आश्चर्य नहीं। निवेश और रोजगार बढ़ाना हर तरह से जरूरी है, ताकि भारत में केवल आर्थिक तरक्की ही न हो, वास्तविक खुशहाली भी बढ़े। बेशक, आर्थिक उदारीकरण को तेज करने की जरूरत है, ताकि भारत में उद्योग करना या कारखाने लगाना ज्यादा आसान हो जाए। भारत से प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए भी यह पहल जरूरी है। भारत के आर्थिक आकर्षण को बढ़ाना समय की मांग है। यह खुशखबरी से कम नहीं है कि भारत सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2022 के 5.93 ट्रिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 के बजट अनुमानों में 11.21 ट्रिलियन हो गया है। बढ़ते पूंजीगत व्यय की वजह से भी विकास दर को बल मिल रहा है। समग्रता में देखें, तो एक आम भारतीय नागरिक एक अच्छे बजट की आशा रख सकता है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 30 जनवरी, 1951

बापू की पावन स्मृति

बापू की पावन स्मृति हमारे हृदय-पट पर अमिट रूप से अंकित है, किन्तु बापू के जीवन से संबंध रखने वाली कुछ तिथियां उनकी स्मृति को और भी साकार रूप में हमारी आंखों के सामने खड़ी कर देती हैं। 30 जनवरी भी ऐसी ही एक तिथि है, जिसे मानव जाति कभी नहीं भूल सकेगी। ईसा के बलिदान की भांति बापू का बलिदान भी मानव जाति के इतिहास में एक अमर घटना बन चुका है। वह 30 जनवरी की संध्या, जब सदा की भांति बापू प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे और एक पागल प्राणी ने पिस्तोल की गोलियों के निष्ठुर प्रहार से उनके प्राणों का अन्त कर दिया था, क्या कभी भुलायी जा सकेगी? बापू ने तो हमेशा गीता की इस शिक्षा पर जोर दिया था कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न पवन सुखा सकता है। बापू इसी आत्मिक शक्ति के प्रतीक थे।...

इस देश के जीवन में बापू ने जो महान क्रान्ति कर दिखाई, उसे एक चमत्कार ही कहना होगा। आज से 35 वर्ष पहले उस जमाने की हम कल्पना करें, जब बापू भारतीय मंच पर प्रकट नहीं हुए थे। उस समय राष्ट्र प्रायः चेतनाशून्य और निर्बल था। एक प्रबल विदेशी सत्ता ने देश की आत्मा को नागपाश में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। कोई विरले ही उस सत्ता को चुनौती देने का साहस करते थे। राजनीतिक चेतनायुक्त एक छोटा सा वर्ग था, जिसे केवल एक ही मार्ग ज्ञात था। वह विदेशी सत्ताधीशों से अनुनय- विनय मात्र कर सकता था।

बापू ने भारतीयों के शरीर में एक नयी रूह फूंक दी। देश का सोया हुआ मानस एक सिरे से दूसरे सिरे तक खलबला उठा। बूढ़े, नौजवान और बच्चे; मर्द और औरतें सभी निर्भय होकर स्वतन्त्रता के संग्राम में कूद पड़े। बापू ने लड़ाई का बिल्कुल अनोखा तरीका ईजाद किया, जिसने शासकों के समस्त पाशविक बल को- तोप-तलवार और संगीनों को कुण्ठित कर दिया।...

देश आज राजनीतिक स्वतन्त्रता के जिस अनमोल वरदान का उपभोग कर रहा है, वह बापू की देन है और उसके लिए इस देश की कोटि-कोटि जनता चिरकाल तक कृतज्ञ रहेगी। उन्हें अपने उद्धारकर्ता और पथ-प्रदर्शक के रूप में हमेशा स्मरण करेगी।

और न्यायपूर्ण हों यूजीसी के नए नियम

यहां स्कैन करें
सुखदेव थोराट | पूर्व अध्यक्ष, यूजीसी

यूजीसी के जातिगत समानता संबंधी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और यह समय है, जब इन नियमों की कमियों को दूर किया जाए, ताकि शिकायत न रहे।

उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नए नियम 'प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन' का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत ने यूजीसी की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए इसकी सुनवाई की नई तारीख मुकर्रर की है। जरूरत यह समझने की है कि आखिर यह नियम क्यों बनाया गया और अब इसके विरोध के बिंदु क्या हैं?

दरअसल, नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठत मेडिकल कॉलेज एम्स (2008 में) समेत देश के कई उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की दुखद घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से भेदभाव के खिलाफ नियम बनाने को कहा था। इसके बाद यूजीसी (प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस) रेगुलेशंस-2012 बना था।

इस बीच हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला और मुंबई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की छात्रा पायल तड़वी द्वारा खुदकुशी करने के बाद इनकी माओं ने 2012 के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने यूजीसी से इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। इसके जवाब में यूजीसी ने बताया कि अन्य बातों के अलावा, वह अपने प्रावधानों को और बेहतर बनाने के लिए 2012 के नियमों में संशोधन कर रहा है। उसने जनवरी 2025 में अपने संशोधित नियमों पर 'फीडबैक' मांगा और इस महीने उसे अधिसूचित कर दिया। यूजीसी ने संशोधित नियमों में शिक्षण परिसरों में भेदभाव के खिलाफ जागरूकता के तंत्र में कुछ सुधार किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसने कई महत्वपूर्ण कमियां छोड़ दीं, जिनको दुरुस्त करने की जरूरत थी।

सबसे पहली कमी तो यही है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की इसकी परिभाषा भ्रमित करने वाली है। एक तरफ, यूजीसी सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करता है, लेकिन जब परिभाषा की बात आती है, तो यह कहता है कि 'वही विश्वविद्यालय और कॉलेज उच्च शिक्षण संस्थान के दायरे में आते हैं, जो यूजीसी कानून-1956 की धारा-3 के तहत आते हैं।' यानी, लगभग 1,168 विश्वविद्यालय और 45,473 कॉलेज। इसका मतलब है कि यह 23 आईआईटी, 21 आईआईएम और लगभग 12,002 स्वायत्त शिक्षण संस्थानों को वह अपनी परिभाषा से बाहर कर देता है। आईआईटी और आईआईएम, दोनों राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। आईआईटी जहां 'इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐक्ट-1961' के तहत स्थापित किए गए हैं, तो आईआईएम 2017 के 'आईआईएम ऐक्ट' द्वारा शासित होते हैं।

इसी तरह, पॉलिटेक्निक, शिक्षक प्रशिक्षण व नर्सिंग संस्थान एआईसीटीई, एनसीटीई और आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्त निकाय हैं। इन संस्थानों को यूजीसी अधिनियम की धारा-3 के तहत मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सीधे मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इसका मतलब है कि संशोधित नियम से संभवतः उच्च शिक्षण संस्थानों का बड़ा हिस्सा अप्रभावित रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि देश के सभी शिक्षण संस्थानों को मंत्रालय के नियमों के तहत लाया जाए।

प्रस्तावित नियमों में दूसरी गंभीर खामी यह है कि साल 2012 के नियमों के उलट ये भेदभाव के रूपों का वर्गीकरण नहीं करते हैं। 2012 के नियम में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम-1955 और अत्याचार अधिनियम-1989 की तर्ज पर नामांकन, मूल्यांकन, शिक्षण, खेल, सामाजिक जीवन, हॉस्टल और डाइनिंग हॉल से संबंधित 28 प्रकार के भेदभाव की सूची दी गई है। अस्पृश्यता की जड़ों को देखते हुए, 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम-1955' ने लगभग 17 और 'अत्याचार अधिनियम-1989' ने लगभग 40 प्रकार के भेदभाव की पहचान की थी। मौजूदा प्रस्तावित नियम 2012 के नियमों की भावना के खिलाफ जाकर यह काम इक्विटी कमेटी पर छोड़ देता है। इसमें कहा गया है कि इक्विटी कमेटी को भेदभाव वाले कृत्यों की उदाहरण वाली सूची बनानी व प्रसारित करनी होगी। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इक्विटी कमेटी को अस्पृश्यता की गहराई और भेदभाव की पर्याप्त समझ होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अत्याचार अधिनियम-1989 के संदर्भ में इसकी जटिलता का जिक्र करते हुए कहा था, 'ऐसे अपराध अनुसूचित जाति और जनजातियों को अपमानित करने और दबाने के लिए किए जाते हैं, ताकि उन्हें दमित जा सके। इसमें गहरी घृणा, अपमानजनक व नीच व्यवहार शामिल हैं। इसलिए, वे विशिष्ट किस्म के अपराध हैं, जिनकी तुलना भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) के तहत आने वाले अपराधों से नहीं की जा सकती।' आईआईटी मुंबई की एक घटना जातिवादी बीमार मानसिकता के उदाहरण के लिए सटीक होगा। दलित लड़कियों से अगड़ी जाति के एक छात्र ने पूछा, 'कोटा से आई हो या कोठे से आई हो?'

अपने घिनौने स्वभाव के कारण, भेदभाव के रूपों को सरकार ने दोनों अधिनियमों में वर्गीकृत किया है। शिक्षण संस्थान में इक्विटी कमेटी भेदभाव के कई रूपों के वर्गीकरण में सक्षम नहीं है। इसके अलावा, अगर पहचान का काम अलग-अलग शिक्षण संस्थानों पर छोड़ दिया जाता है, तो भेदभाव के रूप अलग-अलग होंगे और कानूनी भ्रम पैदा होगा। इसलिए, यूजीसी को 2012 के नियमों में अपनाई गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और भेदभाव के रूपों का साफ तौर पर वर्गीकरण करना चाहिए, जो देश के सभी शिक्षण संस्थानों पर समान रूप से लागू हों।

साल 2026 के नियमों की एक और कमी इक्विटी कमेटी के गठन से जुड़ी है। हैरानी की बात है कि संस्थान के प्रमुख को इस कमेटी का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह, संस्थान का मुखिया दोनों तरफ बैठेगा- एक तरफ, सिफारिश करने वालों के साथ, तो दूसरी तरफ इन सिफारिशों के आधार पर फैसला लेने वाले व्यक्ति के तौर पर। इससे हितों का टकराव होगा। अंतिम फैसला लेने वाले संस्थान के प्रमुख को सिफारिश करने वाली इक्विटी कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आखिर में, इक्विटी कमेटी में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का जिक्र किया गया है, जो गलत है। फैसला लेने में उन्हें प्रभावी भूमिका निभाने के लिए कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए था।

यूजीसी को शैक्षिक संस्थानों में समानता को सही मायने में बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव की बुराई के कारण अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता को न्याय दिलाने के लिए इन कमियों को दूर करना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

महात्मा गांधी की वह तीर्थयात्रा कभी न भुलाई जाएगी

यहां स्कैन करें
विवेक शुक्ला | वरिष्ठ पत्रकार

आज महात्मा गांधी का बलिदान दिवस है। देश उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। आज के दिन उनकी उन कोशिशों को खास तौर पर याद करने की जरूरत है, जिनके लिए उनकी हत्या कर दी गई। 30 जनवरी, 1948 को अपनी हत्या से मात्र तीन दिन पहले गांधी जी ने दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह का दौरा किया था। यह दौरा सांप्रदायिक सद्भाव और शांति-स्थापना की दिशा में उनकी अंतिम कोशिश थी।

देश के बंटवारे के बाद हुई हिंसा में भारत-पाकिस्तान के लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा की आग पूरे उप-महाद्वीप में फैल गई। हिंदू और सिख शरणार्थी पाकिस्तान से आकर दिल्ली में बस रहे थे, जबकि मुसलमानों को असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा था। मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों व अन्य धार्मिक स्थलों पर हमले हुए। महरौली की प्रसिद्ध दरगाह हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी दंगों में क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह दरगाह दिल्ली की सबसे पुराने सूफी स्थलों में से एक है, जहां सदियों से सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करते थे। दंगों ने इस सद्भावना को चोट पहुंचाई थी।

गांधीजी इस हिंसा से काफी आहत थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपना जीवन उन्होंने सांप्रदायिक एकता को समर्पित कर दिया था। जनवरी 1948 में शांति बहाली के लिए उन्होंने अनिश्चितकालीन उपवास रखा था। इस उपवास में विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक नेताओं ने उनसे मिलकर शांति की प्रतिज्ञा ली। उपवास समाप्त होने के बाद भी गांधीजी सक्रिय रहे। उनका 27 जनवरी को दरगाह का दौरा इसी शांति अभियान का हिस्सा था। दिल्ली में उस दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। इसके बावजूद गांधीजी सुबह ही दरगाह में पहुंच गए। उनके साथ प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर थीं। यह दौरा उनकी बहुलवादी सोच का प्रतीक था। वे सूफी परंपरा को सम्मान देते हुए हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर देना चाहते थे। बापू ने इस दरगाह पर जाकर संदेश दिया था कि सूफीवाद की भावना भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है।

हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह का वह दौरा सांप्रदायिक सद्भाव की दिशा में बापू की अंतिम कोशिश थी।

उपवास के कारण बापू शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे, फिर भी वह बिड़ला हाउस से महरौली पहुंचे। दरगाह पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने क्षतिग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने एक प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। उस सभा में उनके शब्द थे, 'मैं यहां तीर्थयात्रा पर आया हूं। मैं मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों से अनुरोध करता हूं कि वे यहां प्रतिज्ञा लें कि दिल्ली और पूरे भारत में शांति रहेगी।'

गांधीजी ने शरणार्थियों से अपील की कि वे क्षतिग्रस्त इलाकों का पुनर्निर्माण करें और एक-दूसरे के साथ मिलकर रहें। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से भी कहा कि दरगाह की मरम्मत के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाए। यह दौरा उनकी अंतिम सार्वजनिक सभाओं में से एक था। उनका यह दौरा सबक था हिंसा से कुछ नहीं मिलता, प्रेम और समझ से ही कोई समाज मजबूत होता है। गांधीजी महरौली 33 साल बाद गए थे। पहली बार वह 12 अप्रैल, 1915 को जब वह तीन दिनों के लिए दिल्ली आए थे, तब कांग्रेस के नेता हकीम अजमल खान के साथ महरौली में कुतुब मीनार और दूसरी इमारतों को देखने के लिए गए थे।

27 जनवरी, 1948 का वह दरगाह-दौरा प्रमाण है कि गांधीजी का अहिंसा का सिद्धांत केवल राजनीतिक नहीं था, धार्मिक और सामाजिक स्तरों पर भी लागू होता था। भारत की आत्मा गांवों और धार्मिक सद्भावना में बसती है। महरौली की प्रार्थना सभा में उन्होंने पूछा, कितने मुसलमान इस सभा में हैं? केवल एक हाथ उठने पर उन्होंने निराशा व्यक्त की। गांधीजी ने इस अवसर पर सभी को एकजुट होने का आह्वान किया।

आज जब देश में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं, तब गांधीजी का यह दौरा एक प्रेरणा है। उसके जरिये उन्होंने यही संदेश दिया कि क्षति की मरम्मत करना और एक-दूसरे के दर्द को समझना ही सच्ची मानवता है। अफसोस! यहां के मुलाजिमों को यह जानकारी नहीं है कि गांधीजी यहां एक खास मकसद से पधारे थे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

रैदास ने दिखाई राह

संभव है कि यह शीर्षक पढ़कर आप चौंक गए हों कि कहां रैदास बानी और कहां संविधान। हमारे संविधान को लेकर पहला और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि भारतीय संविधान यूरोप व अमेरिका के संविधानों की अनुकृति है। ऐसा इसलिए भी है कि संविधान आधुनिक भाषा में लिखा गया है, किंतु ध्यान से देखें, तो हमारे संविधान की भाषा भले आधुनिक शब्दावली से गढ़ी गई हो, उसका सारतत्व भारतीय मनीषा से उपजा नवनीत है।

जब हम स्वाधीनता, समता और बंधुत्व की बात सुनते हैं, तो हमारा ध्यान फ्रांसीसी क्रांति की ओर चला जाता है, लेकिन इस स्वाधीनता, समता और बंधुत्व का स्रोत हमारी संत कविता, खास तौर से रैदास की कविता में मौजूद है। इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। यूं तो रैदास बहुत विनम्र, विनयशील और साधु हैं, लेकिन पराधीनता की पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं। इस कदर समझते हैं कि उनके लिए पराधीनता सबसे बड़ा पाप घोषित है- *पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत।/ रैदास दास पराधीन सौं, कौन करै है प्रीत।* पराधीनता पाप है, इतना बड़ा पाप कि पराधीन से कोई प्रेम नहीं करता।

हम सब जानते हैं कि रैदास जिस संत भक्ति कविता के अग्रदूत थे, उसकी सबसे बड़ी कामना प्रेम ही है। रैदास यह जानते हैं कि पराधीन व्यक्ति के लिए प्रेम असंभव है। इसलिए पराधीनता रूपी पाप से मुक्ति पाना संत का पहला काम है। पराधीनता का बोध और पराधीनता से मुक्ति की आकांक्षा ही स्वाधीनता का स्रोत है। यह बोध रैदास के यहां भरपूर है।

रैदास के लिए पराधीनता का स्रोत कहीं और नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना में मौजूद था। जिस सामाजिक संरचना में अस्पृश्यता जैसी चीज मौजूद रही हो, शूद्र के लिए गहरी घृणा मौजूद रही हो, वहां पराधीनता का स्रोत अलग से खोजने की जरूरत नहीं है। सामाजिक संरचना में मौजूद विषमता ही पराधीनता का मूल स्रोत है। इसलिए सच्ची स्वाधीनता तब तक नहीं संभव, जब तक कि समता न स्थापित हो जाए।

अमूमन सत्ताएं ईश्वर से हमारे संबंध को भय से परिभाषित करती रही हैं। रैदास ईश्वर से अपने संबंधों को बड़ी सहजता से परिभाषित करते हैं, सिर्फ तीन शब्दों में-

पराधीनता का बोध और पराधीनता से मुक्ति की आकांक्षा ही स्वाधीनता का स्रोत है। यह बोध रैदास के यहां भरपूर है। इसलिए वह पराधीनता को सबसे बड़ा पाप घोषित करते हैं।

जैसे चंदन पानी। चंदन पानी में विलीन हो जाता है, भेद मिट जाता है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, ऐसा ही है ईश्वर से हमारा संबंध। वास्तव में, यहां कोई भेद है ही नहीं। केवल समझ का भेद है। वह सवाल करते हैं- जब सब उसी ईश्वर के जन हैं, तो प्रेम से क्यों नहीं रह सकते? क्या भेदभाव, क्या छुआछूत, क्या ऊंच-नीच और क्या धनी-गरीब? इसीलिए रैदास एक मानवीय और समुन्नत संसार की कल्पना करते हैं, जिसका नियम और धर्म सिर्फ और सिर्फ प्रेम है।

सदानंद शाही

ऋषि सुनक | पूर्व प्रधानमंत्री, ब्रिटेन

हम पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। ये हमले समुद्र, आकाश या जमीन से नहीं, बल्कि हमारी स्क्रीन के जरिये हो रहे हैं। साल 2026 के बारे में हम एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस वर्ष साइबर हमलों की संख्या में भारी वृद्धि होगी।

अनुलोम-विलोम
यूरोपीय संघ

एक-दूसरे के हितों को साधने वाला मंच

भारत के साथ व्यापार समझौते से इन दिनों यूरोपीय संघ खूब चर्चा में है। यूरोपीय संघ केवल 27 देशों का समूह नहीं है, वह इतिहास की प्रयोगशाला है, जहां सदियों की लड़ाइयों, साम्राज्यों के उत्थान-पतन और खून से खिंचे नक्शों के बाद यह तय किया गया कि अब तलवारें नहीं चलेंगी, समझौते चलेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के मलबे से उठकर यूरोप ने यह माना कि राष्ट्रवाद की अति अंततः राष्ट्रों को ही लहूलुहान करती है। इस स्वीकारोक्ति से यूरोपीय संघ का जन्म हुआ, जो आज दुनिया की सबसे संगठित और जटिल बहुराष्ट्रीय संरचनाओं में से एक है।

वर्तमान यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं। जर्मनी और फ्रांस इसकी धुरी माने जाते हैं, तो इटली और स्पेन इसकी ऐतिहासिक आत्मा हैं। नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग जैसे छोटे देश इसके प्रशासनिक संतुलन को साधते हैं। पूर्वी यूरोप से पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश इसके विस्तार का प्रतीक हैं। बाल्टिक क्षेत्र से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इसकी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करते हैं। साइप्रस और माल्टा भूमध्य सागर की आवाज हैं, जबकि स्कैंडिनेवियाई स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क इसकी सामाजिक चेतना को आकार देते हैं। ब्रिटेन कभी इसका हिस्सा था, पर ब्रेग्जिट ने यह सिखा दिया कि किसी संघ में रहना राजनीतिक धैर्य की मांग करता है।

यूरोपीय संघ की कोई एक राजधानी नहीं है और यही उसकी खासियत भी है। यह सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे फैलाकर संतुलित करता है। ब्रसेल्स इसका प्रशासनिक चेहरा है, जहां से नीतियां बनती हैं और फाइलें चलती हैं। स्ट्रासबर्ग लोकतांत्रिक मंच है, जहां यूरोपीय संसद की बहसें गूंजती हैं। लक्जमबर्ग न्यायिक विवेक का केंद्र है, जहां कानूनों की आत्मा को परखा जाता है। यह बिखराव दरअसल शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रतीक है, जो यूरोपीय संघ की मूल भावना से मेल खाता है। लोकतंत्र की दृष्टि से यूरोपीय संघ एक दिलचस्प संरचना है। यहां नागरिक केवल अपने देश की सरकार नहीं चुनते, बल्कि एक महाद्वीपीय संसद के प्रतिनिधि भी चुनते हैं। हर पांच वर्ष में होने वाले यूरोपीय संसद के चुनाव इस बात का संकेत हैं कि नागरिकों की आवाज राष्ट्रीय सीमाओं से आगे जाकर सुनी जाती है।

अंततः यूरोपीय संघ एक राजनीतिक व्यवस्था से अधिक एक विचार है। इसने दुनिया को दिखाया है कि शक्ति केवल सैन्य या आर्थिक नहीं, बल्कि सहयोग और सहमति से भी हो सकती है।

विवेक रंजन श्रीवास्तव, टिप्पणीकार

नीतिगत मतभेदों से सुस्ती का मारा संघ

यूरोप के विकसित देशों की हालत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार खराब होती गई। सैन्य रूप से ये देश अमेरिका और रूस पर निर्भर हो गए थे, अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी उनकी पहले वाली स्थिति नहीं रही। रही सही कोर कसर एशिया और अफ्रीका में उनके उपनिवेशों में आजाद होने की भावना और इसके लिए चले संघर्षों के बाद उनकी आजादी ने पूरी कर दी। इसके बाद यूरोपीय देशों के पास एकमात्र चारा यही बचा कि वे आपस में मिलकर कोई रास्ता निकालें, अन्यथा उनका विनाश निश्चित है।

इसी ऊहापोह की स्थिति में यूरोप के 28 देशों ने मिल-जुलकर एक ढीला-ढाला संघ बनाया, जिसे दुनिया में यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनकी साम्राज्यवादी मानसिकता ही थी कि यूरोपीय संघ के गठन में भी गहन जटिलता रखी गई। इस कारण इनके बीच के विमर्श, निर्णय लेने की प्रक्रिया इतनी सुस्त है कि फैसले बेकार हो जाते हैं। यूरोपीय संघ की जटिलता और दुरूह नीतिगत प्रक्रिया ही वह वजह है कि सबसे प्रभावशाली और संपन्न देशों में से एक ब्रिटेन ने खुद को अलग कर लिया।

यूरोपीय संघ की प्रमुख नाकामियों में 27 सदस्य देशों के बीच नीतिगत मतभेद, अत्यधिक नौकरशाही के कारण धीमी निर्णय प्रक्रिया (जैसे सीमा शुल्क संहिता में 10 वर्ष लगना) और ब्रेग्जिट जैसी घटनाएं शामिल हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध पर मतभेद, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) से संबंधित व्यापारिक चुनौतियां और सदस्य देशों के बीच मतभेद इनकी प्रमुख कमजोरी है।

यूरोपीय संघ के विशाल आकार और विविधता के कारण, आम सहमति बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। ब्रेग्जिट संघ की एकता के लिए एक बड़ा झटका था। कई और देशों में भी इस संघ से अलग होने की वकालत करने वाली ताकतें मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त रूस-यूक्रेन युद्ध पर यूरोप का रुख अक्सर विभाजित और पाखंडी माना गया है, जिससे यह भारत जैसे देशों के साथ कूटनीतिक रूप से अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाया।

मुक्त व्यापार समझौते के स्तर पर भी यूरोपीय संघ बहुत फायदेमंद नहीं रहा है। भारत के साथ यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौता सीबीएएम जैसे कड़े नियमों के कारण भारतीय स्टील और एल्युमिनियम जैसे निर्यातकों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, संघ भारत के साथ एफटीए जैसी नई पहल के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। इसमें कितना सफल होता है, यह तो समय ही बताएगा।

मृत्युंजय कुमार सिंह, टिप्पणीकार

छोटी पथरी न बने बड़ी परेशानी

पथरी की समस्या अब युवाओं और बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है। पानी कम पीना, गलत खानपान और लगातार बैठे रहना इसके बड़े कारण हैं। हालांकि, पथरी के हर मामले में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, पर लंबे समय तक सही उपचार की अनदेखी करना समस्या बढ़ा देता है। बचाव के उपाय बता रही हैं रूपाली चतुर्वेदी

10 में से 1 व्यक्ति को कभी-न-कभी गुर्दे की पथरी होती है

20 लाख से ज्यादा पथरी के मामले हर साल देश में सामने आते हैं।

रोजाना सिर्फ एक लीटर से कम पानी पीना पथरी के जोखिम को 30 से 40 प्रतिशत बढ़ा सकता है।

एक अनुमान के अनुसार बीते सालों में भारत में 20-40 साल की उम्र के लोगों में पथरी के मामले 30-40% तक बढ़े हैं। इतना ही नहीं गलत खानपान और आधुनिक जीवनशैली के कारण अब बच्चों में भी पथरी (पीडियाट्रिक नेफ्रो-लिथियासिस) के मामले लगातार बढ़े हैं। मोटापा, जंक फूड अधिक खाना, पानी कम पीना, कोल्ड ड्रिंक्स अधिक लेना व लंबे समय तक स्क्रीन टाइम के कारण शारीरिक सक्रियता की कमी इसका बड़ा कारण है।

क्या है ये बीमारी ?

जैसे पानी सूखने पर बर्तन में सफेद परत जम जाती है, ठीक वैसे ही किडनी में कुछ मिनरल और नमक जमा होकर छोटे–छोटे पत्थर के कण बन जाते हैं। इनको ही पथरी कहते हैं। ये आकार में रेत के दाने जितने छोटे या चने-मटर जितने बड़े हो सकते हैं। पथरी के चार प्रकार हैं-

1. **कैल्शियम स्टोन:** यह पथरी कैल्शियम और ऑक्सलेट के जमने से बनती है। 70-80% लोगों में इसी तरह की पथरी बनती है।
2. **यूरिक एसिड स्टोन:** शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से इस तरह की पथरी होती है। मोटे और पानी कम पीने वालों में इसकी ज्यादा आशंका होती है।
3. **स्ट्रूवाइट स्टोन:** यह पथरी बार-बार होने वाले पेशाब संक्रमण से बनती है। इस पथरी का आकार तेजी से बढ़ता है।
4. **सिस्टीन स्टोन:** यह पथरी एक जेनेटिक (वंशानुगत) बीमारी में बनती है। हालांकि, ऐसे मामले बहुत ही दुर्लभ हैं।

अक्सर लोग गुर्दे और पित्त की थैली की पथरी को एक मान लेते हैं। किडनी की पथरी का असर पेशाब की नलियों पर पड़ता है। दूसरी ओर, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में बनने वाली पथरी पित्त के बहाव में रुकावट आने से बनती है। इसका किडनी या पेशाब से कोई संबंध नहीं होता। यदि एक बार गुर्दे की पथरी हो चुकी है, तो दोबारा पथरी की आशंका 50% बढ़ जाती है।

कम पानी पीना एक बड़ा कारण

कम पानी पीने से पेशाब गाढ़ा हो जाता है और मिनरल एक-दूसरे से चिपककर छोटे-छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। अन्य कारण हैं-

- ज्यादा नमक, तली-भुनी चीजें, चाय-कॉफी, रेड मीट अधिक खाना।
- आनुवंशिक कारण, मोटापा और बार-बार होने वाला मूत्र मार्ग का संक्रमण।
- कुछ दवाएं व समस्याएं जैसे थायरॉएड और यूरिक एसिड का बढ़ना भी खतरा बढ़ाती हैं।
- लंबे समय तक बिना विशेषज्ञों से सलाह किए कैल्शियम, विटामिन डी और उच्च प्रोटीन उत्पादों का सेवन करना

कब सर्जरी की जरूरत

4 मिमी. से छोटी पथरी:	80 प्रतिशत मामलों में ये कण अपने आप निकल जाते हैं।
6 मिमी. तक:	20 प्रतिशत मामलों में पथरी खुद निकल जाती है। दवाओं से आराम न आने पर सर्जरी की जाती है।
9 मिमी. या अधिक:	इस आकार की पथरी को सर्जरी से ही हटाना पड़ता है। यहां अनदेखी भारी पड़ती है।

अंत में, पथरी के आकार से ज्यादा यह मायने रखता है कि पथरी कहां फंसी है। सिर्फ 4–5 मिमी का छोटा कण भी यूरेटर में फंस जाए, तो भयानक दर्द दे सकता है।

सही समय पर सही उपचार जरूरी

यह सोचकर कि छोटी पथरी है, अपने आप निकल जाएगी, हम सही उपचार में देरी कर देते हैं। अप्रमाणिक तरीकों में लंबा समय खपा देते हैं। इस कारण सर्जरी की नौबत आ जाती है। तेज दर्द के साथ संक्रमण बढ़ने लगता है। सर्जरी के आधुनिक तरीकों में आरआईआरएस, पीसीएनएल, ईएसडब्ल्यूएल प्रमुख हैं। पथरी की रोकथाम के लिए इन तरीकों को अपनाएं...

पानी: दिनभर में 2–2.5 लीटर पानी पिएं। गरम इलाकों में रहते हैं,तो ज्यादा पानी पिएं।

सोडियम: नमक कम खाएं। इससे पेशाब में कैल्शियम का स्तर कम होता है। खासकर, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, डिब्बा बंद चीजों से बचें। इनमें स्वाद के लिए अधिक नमक मिलाते हैं।

ऑक्सलेट युक्त चीजें: जैसे पालक, चुकंदर, सोयाबीन, काली मिर्च, मेवे व चॉकलेट कम खाएं। पेशाब में ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ने से वे कैल्शियम से जुड़कर कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाते हैं। देश में यह पथरी सबसे अधिक बनती है।

प्रोटीन: पशु प्रोटीन जैसे मीट और अंडे कम खाएं। इससे यूरिक एसिड बढ़ता है व सिट्रेट कम हो जाता है, जो पथरी का खतरा बढ़ाता है।

विटामिन सी: विटामिन सी से भरपूर चीजें खाएं। इससे क्रिस्टल कम बनता है।

दिनचर्या सुधारें: जल्दी सोएं, जल्दी उठें, नियमित योग और व्यायाय करें। लगातार बैठने से बचें। ये बातें पेशाब के प्रवाह को ठीक रखती हैं, किडनी से दबाव घटता है। तनाव की अधिकता से बनने वाला कॉर्टिसोल हार्मोन कैल्शियम और यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। समय–समय पर पेशाब की जांच करवाते रहें।

पथरी से हमेशा दर्द नहीं होता

पथरी पूरे पेशाब तंत्र को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले किडनी में सूजन या दबाव बढ़ता है। अगर पथरी खिसककर नीचे मूत्राशय, पेशाब नली या यूरेथ्रा में फंस जाए, तो पेशाब रुक-रुक कर आने, तेज दर्द व जलन या संक्रमण की दिक्कतें बढ़ जाती हैं।

कई बार महीन पथरी के कण लंबे समय तक किसी तरह की बाधा पैदा नहीं करते। आमतौर पर पता तब चलता है, जब इनका आकार बढ़ने लगता है या रास्ता ही रुक जाए। ज्यादातर छोटी पथरियां दवा, पानी और जीवनशैली में सुधार से बाहर निकल जाती हैं। हर मामले में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।

पथरी के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि पथरी कहां फंसी हुई है। इसके अलावा हल्का या तेज दर्द (जो कमर के किनारे से पेट और जांघ तक फैलता है),उल्टी जैसा मन रहना और पेशाब संबंधी समस्याएं होने लगती हैं।

डॉक्टर पहले पेशाब टेस्ट कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में कई बार महीन कण पकड़ में नहीं आते, ऐसे में सीटी स्कैन कराया जा सकता है।

'स्टोन बेल्ट' जानते हैं?

इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी और नेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के अनुसार देश में होने वाले पथरी के कुल मामलों में अकेले एक तिहाई से ज्यादा मामले उत्तर और पश्चिम भारत से आते हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह समस्या अधिक है, इसलिए इसे स्टोन बेल्ट कहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, तापमान की अधिकता और खारा पानी इसकी बड़ी वजहें हैं। ऐसे में जो लोग पानी कम पीते हैं, नमक व यूरिक एसिड बनाने वाली चीजें अधिक खाते हैं और विटामिन सी का सेवन कम करते हैं, उनमें पथरी की आशंका बढ़ जाती है।

हमारे विशेषज्ञ: डॉ. प्रदीप बंसल, डॉयरेक्टर (यूरोलॉजी), फोर्टिस, गुड़गांव।
डॉ. आशुतोष सिंह, सीनियर कंसल्टेंट (यूरोलॉजी), मेट्रो हॉस्पिटल, नोएडा

सवाल-जवाब

नब्बे फीसदी कैंसर आनुवंशिक नहीं होते

डॉ. तपस्विनी प्रधान
वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ (सिर व गला), अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली

■ सवाल : मेरे दादाजी को ओरल कैंसर और पिताजी को लिम्फोमा हुआ था। क्या कैंसर आनुवंशिक होता है? मुझे और मेरे बच्चों को इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए?

जवाब : परिवार में कैंसर का इतिहास होने पर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि 90 प्रतिशत से अधिक कैंसर आनुवंशिक नहीं होते, बल्कि हमारी जीवनशैली, पर्यावरण और आदतों से पनपते हैं, जिन पर ध्यान देकर जोखिम को कम किया जा सकता है। आपके मामले में दादाजी को ओरल कैंसर और पिताजी को लिम्फोमा था, जो कि दो बिल्कुल अलग प्रकार के कैंसर हैं और इनका आपस में कोई सीधा जेनेटिक संबंध नहीं दिखता है। लिम्फोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है, जो बिना आनुवंशिक कारणों से अपने आप विकसित हो जाता है।

अक्सर एक ही परिवार में कैंसर के मामले इसलिए दिखते हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों की आदतें, जैसे तंबाकू व धूम्रपान करना, खानपान की शैली और दिनचर्या एक जैसे होते हैं। आप अपने और बच्चों में बदलाव के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे अनिवार्य कदम तंबाकू, सुपारी और शराब से पूरी तरह दूरी बनाना है, क्योंकि मुंह के कैंसर के अधिकांश मामलों में यही मुख्य कारण होते हैं। इसके साथ ही, साल में कम से कम एक बार विशेषज्ञ से ओरल स्क्रीनिंग जरूर कराएं और मुंह में किसी भी सफेद दाग या लंबे समय तक न भरने वाले छाले को नजरअंदाज न करें। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लें। नियमित व्यायाम करें और बच्चों को शुरू से सक्रिय जीवनशैली की आदत डालें। ध्यान रखें, सही आदतों से हम कैंसर के 70 प्रतिशत जोखिम को कम कर सकते हैं।

■ सवाल : कैंसर के उपचार में हुई नई प्रगति के बारे में बताएं। क्या कैंसर दोबारा वापसी करता है?

जवाब : चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति ने कैंसर के उपचार को पहले से कहीं अधिक प्रभावी, सुरक्षित और मरीज-केंद्रित बना दिया है, जिससे अब यह लाइलाज बीमारी नहीं रही। व्यक्तिगत जरूरत के आधार पर तन और मन की सेहत के संपूर्ण उपचार के दृष्टिकोण ने कैंसर के प्रबंधन को पहले से बेहतर और सफल बना दिया है। जिन मरीजों में पारंपरिक इलाज जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन असर नहीं दिखा पाते, उनके लिए इम्यूनोथेरेपी नई राह खोल रही है।

आज इम्यूनोथेरेपी के जरिये शरीर के इम्यून सिस्टम को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वह खुद कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन पर हमला कर सके, वहीं 'टारगेटेड थेरेपी' सीधे ट्यूमर की जेनेटिक पहचान पर प्रहार करती है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को कम नुकसान होता है।

सर्जरी के क्षेत्र में भी रोबोटिक और मिनिमली इनवेसिव तकनीकों ने बड़े ऑपरेशनों की जगह ले ली है, जिससे मरीज जल्दी ठीक होते हैं, जबकि रेडिएशन थेरेपी में आईएमआरटी और प्रोटॉन थेरेपी जैसी आधुनिक विधियां आसपास के स्वस्थ अंगों को सुरक्षित रखते हुए सटीक वार करती हैं। इस तरह साइड इफेक्ट्स पहले से कम हुए हैं।

वर्तमान में 'पर्सनलाइज्ड मेडिसिन' के तहत हर मरीज का इलाज उसके ट्यूमर के जेनेटिक मेकअप और बीमारी की स्टेज के अनुसार तय किया जाता है। कैंसर दोबारा होगा या नहीं, यह कैंसर के प्रकार और किस स्टेज पर कैंसर का उपचार प्रारंभ हुआ है, इस पर भी निर्भर करता है। कैंसर के उपचार के बाद सही जीवनशैली और परहेज पर ध्यान देना भी जरूरी है।

भेजें अपने सवाल

सेहत से जुड़े सवाल tanmanhindustan@gmail.com पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं–

तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301

कैंसर से बचाव के 9 कारगर तरीके

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर 30 से 50 प्रतिशत तक कैंसर के मामलों से बचा जा सकता है। हम क्या खाते हैं, कितना सोते हैं और कितने सक्रिय रहते हैं आदि सामान्य बातें भी हमारी सेहत पर गहरा असर डालती हैं।

1. **वजन काबू रखें:** अधिक वजन या मोटापा कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। शरीर में अतिरिक्त चर्बी सूजन, हार्मोन असंतुलन और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। संतुलित आहार और व्यायाम से वजन नियंत्रित रखें।
2. **सक्रिय रहें:** नियमित व्यायाम से वजन काबू रहता है। हार्मोन संतुलन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट हल्के व्यायाम या 75 मिनट कड़े परिश्रम वाले व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। खुले में टहलें।
3. **संतुलित आहार:** फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा से भरपूर आहार कैंसर का खतरा कम करते हैं। प्रोसेस्ड फूड व मांस कम खाएं। फाइटोकैमिकल्स से भरपूर चीजें, जैसे टमाटर, बेरी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और मौसमी फल व सब्जियां अधिक खाएं।
4. **शराब और धूम्रपान से दूरी:** शराब और धूम्रपान से दूरी कई तरह के कैंसर के जोखिम को कम कर सकती है। फेफड़ों, मुंह, गले, मूत्राशय और अग्न्याशय के कैंसर में धूम्रपान एक बड़ा कारण है।
5. **त्वचा का ध्यान रखें:** जिनकी त्वचा संवेदनशील है, वे तेज धूप, प्रदूषण और हानिकारक रसायनों से बचें। सनस्क्रीन लगाएं। त्वचा ढककर रखें।
6. **संक्रमण से बचाव:** हेपेटाइटिस बी और सी जैसे संक्रमण लिवर कैंसर का कारण बन सकते हैं। सुरक्षित यौन संबंध और टीकाकरण जरूरी है।
7. **टीकाकरण करवाएं:** एचपीवी वैक्सीन से सर्वाइकल, गूदा, गले व जननांग से जुड़े कैंसर से बचाव होता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लिवर कैंसर से बचाव करती है।
8. **नियमित जांच कराएं:** मैमोग्राफी, कोलोनोस्कोपी, त्वचा की जांच से समय रहते खतरे की पहचान में मदद करती हैं। इस संबंध में डॉक्टर से सलाह लें।
9. **पर्याप्त नींद जरूरी:** नींद की कमी से शरीर में सूजन और तनाव बढ़ता है। वहीं अच्छी नींद रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। नींद के दौरान हमारा शरीर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है।

शुरुआती लक्षणों पर नजर

ब्रेस्ट कैंसर: स्तन या बगल के आसपास बिना दर्द की गांठ, एक स्तन का आकार अलग दिखना, स्तन में सूजन, निप्पल का अंदर धंसना। विशेषज्ञों के अनुसार नहाते समय या सेल्फ टेस्ट में कैंसर के मामले सबसे अधिक पकड़े गए हैं।

माउथ कैंसर: मुंह में छाला या जख्म होना, जो दो हफ्ते से अधिक बना रहे। यह छाला दर्द रहित हो सकता है। मुंह में सफेद या लाल धब्बे, जो जीभ, गाल, मसूड़ों या होंठों पर हो सकते हैं। खाना निगलते समय परेशानी, जीभ के रंग में बदलाव या सुन्नपन।

फेफड़े व गले का कैंसर: मुंह से बार-बार खून आना, खांसी के साथ खून आना। अगर किसी तरह का संक्रमण नहीं है और धूम्रपान करते हैं, तो ये लक्षण दिखने पर जांच जरूर कराएं।

सर्वाइकल कैंसर: महिलाओं में होने वाला यह एक प्रमुख कैंसर है। योनि से असमान्य खून निकलना, सेक्स और मेनोपॉज के बाद खून आना, पीरियड्स लंबे समय तक रहना।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान मिल सकता है। धन की प्राप्ति हो सकती है।

वृष : वाणी में मधुरता रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। किसी पारिवारिक कारोबार की पुनः शुरुआत हो सकती है। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है।

मिथुन : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी। आय में कमी व खर्च अधिक हो सकता है।

कर्क : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। परिवार का साथ मिलेगा। सेहत के प्रति सचेत रहें।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। सेहत का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। धन की प्राप्ति हो सकती हैं।

तुला : आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। पिता की सेहत में सुधार होगा। भवन सुख में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

धनु : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

मकर : मन परेशान हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। आय बढ़ेगी।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। मान-सम्मान की वृद्धि होगी। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी।

मीन : आत्मसंयत रहें। बेकार के क्रोध व व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। पैतृक संपत्ति से धन मिल सकता है। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

30 जनवरी, शुक्रवार, **शक संवत्:** 10 माघ (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 17 माघ मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 10 शब्बान, 1447, **विक्रमी संवत्:** माघ शुक्ल द्वादशी तिथि प्रात: 11.10 बजे तक पश्चात त्रयोदशी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 03 .28 बजे तक पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र, बालव करण। चंद्रमा मिथुन राशि में (दिन–रात)।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रात: 10 .30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। प्रदोष व्रत। तिल द्वादशी।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

पूजा करते समय कई बार जो संकेत होते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं? –संदीप, लखनऊ

- यदि पूजा करते हुए आंसू आते हैं, तो अर्थ है कि पूजा भगवान ने स्वीकार की है।
- पूजा करते समय दीपक बुझने का अर्थ है कि पूजा मन से नहीं हुई है।
- पूजा करते समय छींक आ जाए तो अर्थ है कि आपके काम में रुकावट आने वाली है।
- पूजा करते समय हाथ जलना संकेत है कि आपसे पूजा में कोई भूल हो गई है।
- यदि पूजा करते समय बहुत उबासी आती है, तो इसका मतलब है कि पूजा में मन नहीं है। यदि पूजा करते समय दीपक या घंटी गिर जाए, तो यह किसी समस्या का संकेत हो सकता है।

वर्ग पहेली : 8225

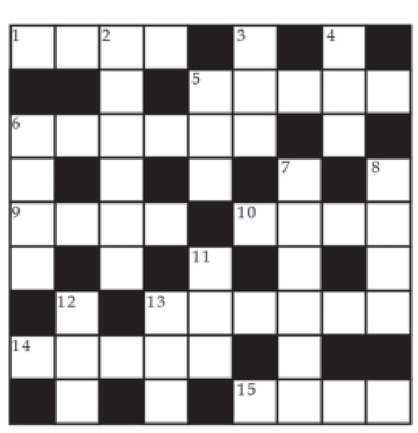

बाएं से दाएं
1. हो सकने की स्थिति; मुमकिन होना; कल्पना; अनुमान (4)
5. परामर्श देना; मशवरा देना; सुझाव देना (3,2)
6. खाना खाना; भोजन ग्रहण करना; भोजन लेना (3,3)
9. फैलना; पैर फैला कर सोना; विस्तृत होना (4)
10. अवनतिकाल; पेड़ों के पत्तें का झड़ना (4)
13. खतरनाक समय का; दुर्गम स्थिति का; संकट काल का (6)
14. घाव होना; घायल होना; जख्म होना; रक्त बहना (2,3)
15. लोगों का मत; जनमत; जनता का आदेश (4)

ऊपर से नीचे
2. उल्लेख करना; बखान करना; विस्तार सहित हाल बताना; विवरण देना; चित्रण करना (3,3)
3. झुलसाना; दागना; पैदा करना (3)
4. शक; संशय (3)
5. निश्छल; निष्कपट; सहज; सुगम; आसान (3)
6. वृक्ष का पत्ता जिस पर प्राचीन काल में लिखा जाता था (4)
7. आगे बढ़ाना; बात चलाना (2,4)
8. दिल की धकधक; हृदय का स्पंदन (4)
11. मना करना; बाधा डालना (3)
12. लुप्त होना; साफ होना; हटना (3)
13. साथी; सोहबत; दोस्ती; मित्रता; साथ (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8224

■	1 स	2 मा	ज	3 से	व	4 क	■	5 स
6 वि	र	ला	■	वा	■	रा	■	र्व
■	क	■	7 या	द	क	र	वा	ना
8 पा	र	9 द	■	ल	■	क	■	म
■	10 ना	म	क	■	11 प	र	12 त	■
13 ब	■	नि	■	14 स	■	15 ना	ह	क
16 च	म	क	द	म	क	■	ल	■
प	■	ल	■	र्थ	■	17 त	गा	दा
न	■	18 ना	म	क	ट	वा	ना	■

सुडोकू : 8207

* मध्यम

9				5				1
	4			9			5	
3		5				9		6
			4	8	2			
1	2						8	4
			9	1	7			
2		8				3		7
	5			2			1	
7				4				5

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8206

9	3	1	4	6	2	5	7	8
8	4	7	9	5	3	6	1	2
5	6	2	8	1	7	4	3	9
3	9	6	2	7	8	1	4	5
7	5	8	6	4	1	2	9	3
2	1	4	5	3	9	7	8	6
6	2	3	1	9	4	8	5	7
4	7	5	3	8	6	9	2	1
1	8	9	7	2	5	3	6	4

सार्थक परिवर्तन का प्रतिरोध प्रगति में गतिरोध ही बढ़ाता है

सुप्रीम कोर्ट की सही रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से लाए गए नए नियमों पर रोक लगाकर कलह और अविश्वास के वातावरण को ही दूर करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथमदृष्टया यह पाया कि नए नियमों में अस्पष्टता है और इसके कारण उनका दुरुपयोग होने की आशंका है। अच्छा होता कि इसे यूजीसी की ओर से ही भांप लिया जाता और उसकी ओर से ऐसे नियम बनाए जाते, जो दुरुपयोग की आशंकाओं को जन्म नहीं देते। इससे इन्कार नहीं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में यदा-कदा भेदभाव के मामले आ जाते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए यूजीसी ने जो नए नियम बनाए, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे शिक्षा संस्थानों में बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा था और एससी-एसटी-ओबीसी वर्गों के लाखों छात्र पीड़ित हो रहे थे। निःसंदेह ऐसी स्थिति नहीं थी। सच यह है कि शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव की कुछ ही शिकायतें सामने आती थीं और उनमें भी चुनिंदा ही सही पाई जाती थीं। आखिर ऐसे में ऐसे नियम क्यों बनाए गए, जो यह प्रतीत करा रहे थे कि शिक्षा संस्थान जातिगत भेदभाव के गढ़ बन गए हैं? जब नियम-कानून बनाते समय कोई समस्या अतिरंजित दिखाई जाती है तो समाज में गलत संदेश तो जाता ही है, राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों की भी पौ बारह हो जाती है। यूजीसी के नए नियमों के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इन नियमों को लेकर विभाजनकारी राजनीति होने लगी और आरक्षित एवं सामान्य वर्गों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का काम होने लगा।

आखिर यूजीसी ने यह आभास क्यों नहीं किया कि समय के साथ जैसे सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर जातिगत भेदभाव कम हुआ है, वैसे ही शिक्षा संस्थानों में भी स्थिति सुधरी है? यह समझना भी कठिन रहा है कि नए नियमों में भेदभाव को जाति-आधारित भेदभाव क्यों कर दिया गया और झूठी शिकायतों के लिए सजा के प्रविधान को क्यों हटा दिया गया? फिलहाल कहना कठिन है कि यूजीसी के नियमों में किस तरह के संशोधन-परिवर्तन होंगे, लेकिन यह ध्यान रखा जाए तो बेहतर कि किसी भी तरह के भेदभाव रोकने के उपाय ऐसे नहीं होने चाहिए, जो समाज को जाति के खांचों में विभक्त दिखाएं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि हमें उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए, जहां भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग शिक्षा संस्थान हों। देश को ऐसे वातावरण की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें कहीं भी किसी तरह के भेदभाव के लिए कोई गुंजाइश न रहे और यदि कहीं कोई समस्या सामने आए तो उसका समाधान इस तरह किया जाए, जिससे सामाजिक सद्भाव को बल मिले। शिक्षा संस्थानों में तो ऐसा वातावरण होना और भी आवश्यक है।

यमुना पार का विकास

दिल्ली में यमुनापार क्षेत्र के विकास के लिए 728 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को स्वीकृति दिया जाना स्वागतयोग्य है। वास्तव में यमुनापार विकास के मामले में उपेक्षित रहा है, यही वजह है कि ये क्षेत्र सुविधाओं और सुंदरता के मामले में कहीं से भी राष्ट्रीय राजधानी का हिस्सा नहीं लगता। बृहस्पतिवार को हुई यमुनापार विकास बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति दे दी। इसके तहत सड़क, ड्रेनेज, जलभराव दूर करने जैसी बुनियादी विकास योजनाओं के साथ ही वेलकम झील के कायाकल्प जैसी योजनाएं भी शामिल हैं।

> यमुना पार के लिए घोषित विकास योजनाओं से क्षेत्र के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है

इसमें कोई दो राय नहीं की दिल्ली के तेजी से होते विकास की दौड़ में यमुनापार क्षेत्र काफी पिछड़ा रहा है। यही नहीं, पांच वर्ष पूर्व यमुनापार विकास बोर्ड को भंग भी कर दिया था। ऐसे में ये आवश्यक था कि इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और यहां रह रहे लोगों को भी राजधानी के अन्य विकसित हिस्सों की तरह ही सुविधाएं मिलें। मुख्यमंत्री का ये कहना भी महत्वपूर्ण है कि यमुनापार का विकास प्राथमिकता में है और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि नई घोषित विकास योजनाओं से इस क्षेत्र में लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही ये क्षेत्र भी शेष दिल्ली की विकास की रफ्तार से कदमताल कर सकेगा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या अजीत पवार के निधन से उनके नेतृत्व वाली राकांपा के समक्ष अस्तित्व का संकट बढ़ गया है?

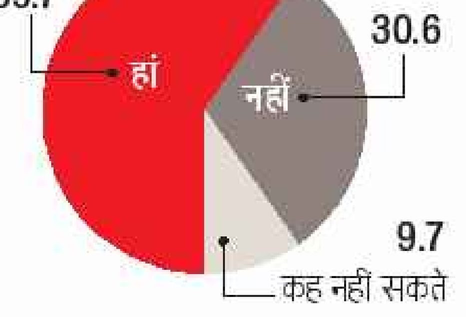

आज का सवाल

क्या यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने सही किया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

श्रम उत्पादकता में सुधार का समय

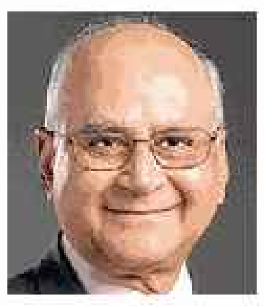

जीएन वाजपेयी

भारत की श्रम उत्पादकता जी-20 देशों में सबसे कम है। कई मध्यम आय एवं उभरती आर्थिकी वाले देशों का प्रदर्शन भी इस पैमाने पर भारत से बेहतर है

उत्पादक क्षमता में विस्तार ही आर्थिक वृद्धि का आधार है। यह उत्पादकता पूंजी, तकनीक और श्रम बल जैसे पहलुओं के मिश्रण पर निर्भर करती है। इसमें भी श्रम एक महत्वपूर्ण अवयव है। श्रम के माध्यम से अन्य संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होता है। श्रम बल के उचित योगदान के अभाव में पूंजी और तकनीक जैसे अन्य संसाधन भी अभीष्ट की पूर्ति में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं रह जाते। उत्पादक क्षमताओं की पड़ताल करें तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आइएलओ के अनुसार भारत की श्रम उत्पादकता प्रति कार्य घंटे आठ अमेरिकी डालर है। जबकि इसी पैमाने पर विश्व में सिरमौर लक्जमबर्ग की प्रति घंटे श्रम उत्पादकता 146, आयरलैंड की 143, नार्वे की 93 और सिंगापुर की 74 डालर है। भारत की श्रम उत्पादकता जी-20 देशों में सबसे कम है। यहां तक कि मध्यम आय और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले मेक्सिको, ब्राजील जैसे देश भारत की तुलना में प्रति कार्य घंटे कई गुना अधिक उत्पादन करते हैं।

भारत सप्ताह में 46-48 घंटे काम करने वाले देशों में शीर्ष पर है, जो चीन और जापान से भी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप बहुत कम वेतन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद सीमित प्रति श्रमिक उत्पादन के कारण नुकसान उठाने के लिए मजबूर है। भारत इस मोर्चे पर बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कम प्रतिस्पर्धी है। इस स्थिति को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बीते नवंबर में श्रम सुधारों की दिशा में कदम उठाए हैं। देश में पहले 29 श्रम कानून थे, जो जटिलताओं से भरे थे। औपनिवेशिक कार्यसंस्कृति से ओतप्रोत ये कानून समय के अनुरूप सुसंगत भी नहीं हो पा रहे थे। इनमें 1436 प्रविधान, 181 फार्म, आठ अलग-अलग पंजीकरण और 31 रिपोर्टिंग कसौटियां थीं। इसने जहां व्यापार सुगमता की राह बाधित की तो श्रमिकों को अपेक्षित सुरक्षा आवरण से भी वंचित बनाए रखा। अब इन 29 कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेट दिया गया है। इनमें वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संबंधी संहिता (2020) 21 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। ये सुधार अनुपालन के सरलीकरण, परिभाषाओं के मानकीकरण, कवरेज दायरे के विस्तारीकरण की राह पर बढ़ते हुए कामकाजी आबादी की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर ढांचागत परिवर्तनों की ओर उन्मुख करते हैं। इसमें उदीयमान गिग इकोनमी को भी जोड़ा गया है। उम्मीद है कि ये श्रम सुधार कार्यसंस्कृति बदल कर श्रमिक सुरक्षा एवं उत्पादकता में संतुलन साधेंगे।

अवधेश राजपूत

देखा जाए तो श्रम सुधार कई तरीकों से उत्पादकता को बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। जैसे स्पष्ट रोजगार शर्तों के माध्यम से औपचारिक रोजगारों को इनसे प्रोत्साहन मिलेगा। एकल पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न से व्यापार सुगमता बढ़ेगी और नौकरशाही के स्तर पर गतिरोध दूर होंगे। अनुपालन के बोझ में कमी कंपनियों को व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी और उनकी लागत घटाएगी। रोजगारों का संगठित स्वरूप भी मानव संसाधन नियोजन एवं उनके बेहतर उपयोग की सुविधा को बढ़ाएगा। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआइसी और भविष्य निधि के तहत चिकित्सा देखभाल, बीमारी की स्थिति में नकदी सहायता, मातृत्व कवरेज और दिव्यांग सहायता के फायदों का विस्तार अनौपचारिक, गिग एवं ऐसे ही अन्य मंचों पर सक्रिय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत एक ऐतिहासिक बदलाव है। इसी तरह अनिवार्य स्वास्थ्य जांच, नियंत्रित कामकाजी समय, सुरक्षा सुविधाएं और लैंगिक समानता मानदंड से मिलने वाले प्रोत्साहन श्रमिकों का हौसला एवं उत्पादकता बढ़ाने का काम करेंगे। जहां रात्रि की पाली में महिलाओं के लिए काम की गुंजाइश उनके लिए अवसर बढ़ाएगी तो निश्चित अवधि के बाद स्थायी कर्मचारियों के रूप में मान्यता श्रमिकों में सुरक्षा भाव का संचार करेगी।

औद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत विशेष रूप से विनिर्माण, आतिथ्य सत्कार और छोटे उद्यमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की नियुक्ति एवं उनके समायोजन में लचीलापन प्रदान किया गया है। इससे उद्यमों के लिए बिना किसी अनावश्यक बोझ के संचालन सुगम होगा। हालांकि, यह नियम केवल तभी लागू होगा जब उद्यम में कर्मचारियों की संख्या 300 या उससे कम हो। राज्यों के पास इस नियम में परिवर्तन की गुंजाइश भी है। पुरानी व्यवस्था में तमाम अवरोधों के चलते भारत के वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्र वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। यह स्थिति अब बदल सकती है। इन सुधारों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए राज्यों को अपने स्तर पर भी उपाय करने होंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और ओडिशा श्रमिकों के मोर्चे पर 300 की मानक संख्या को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये राज्य उद्योगीकरण की बयार पर सवार हैं और दूसरे यहां रोजगार के आकांक्षियों की संख्या भी अधिक है। तमाम संभावित फायदों के बावजूद ट्रेड यूनियनों ने इन सुधारों की आलोचना की है। उनकी दलील है कि इससे रोजगार सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता घटेगी और कर्मचारी नियोक्ता की मर्जी पर निर्भर होकर जाएंगे। वास्तविकता देखी जाए तो श्रम के औपचारिकीकरण और बेहतर नौकरी सुरक्षा से श्रमिकों और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और विवेकाधीन खर्च में वृद्धि से उपभोग में लगभग 75,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। ये सुधार एक सरल, लचीले और समावेशी श्रम बाजार की दिशा में निर्णायक परिवर्तन के प्रतिनिधि प्रतीत होते हैं और यदि इन्हें सही ढंग से लागू किया जाए तो ये निश्चित रूप से नौकरियों में औपचारिकीकरण की प्रक्रिया को गति देंगे, उत्पादकता में सुधार करेंगे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बड़े उद्यमों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा आवरण का कवच तैयार करते हुए अंततः जीडीपी वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाएंगे।

(लेखक सेबी एवं एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

महाराष्ट्र की राजनीति बदलने के संकेत

राज कुमार सिंह

बदली स्थितियों में यदि एनसीपी के धड़े एक होकर राजग में शामिल हुए, तो शिंदे पर भाजपा की निर्भरता घट जाएगी

अजीत पवार के निधन से जीवन का यही सच पुनः रेखांकित हुआ कि नियति के आगे इंसान बेबस है। जिस शख्स ने अपने नाम और काम से महाराष्ट्र की राजनीति में 'दादा' का संबोधन हासिल किया, विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद उसकी पहचान 'घड़ी' से करनी पड़ी। संयोगवश 'घड़ी' अजीत की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का चुनाव चिह्न है। अजीत के नाम पर ही देश में सबसे ज्यादा छह बार उपमुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान है। सत्ता-प्रेम के चलते उनके रास्ते अपने चाचा शरद पवार से भी अलग हो गए, जिनकी अंगुली पकड़ कर वह राजनीति में आए थे। लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद अजीत की एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से चौंकाया। वे चाचा शरद पवार की पार्टी पर भारी पड़े, पर राजनीति असीमित संभावनाओं का खेल है। इधर दोनों गुट नजदीक भी आने लगे थे। हाल के निकाय चुनावों में कुछ जगह दोनों गठबंधन कर चुनाव लड़े थे, तो आसन्न जिला पंचायत चुनाव भी मिलकर लड़ने का मन बन गया था। इसलिए राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल यही है कि क्या अजीत के निधन के बाद पवार परिवार और एनसीपी के दोनों गुट एक होंगे?

राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय शरद पवार द्वारा महाराष्ट्र की राजनीति अजीत को सौंप देने के बाद उन्हें ही राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन बेटी सुप्रिया सुले की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता से भतीजे की महत्वाकांक्षाएं टकराने लगीं। यह टकराव पहली बार सतह पर तब आया, जब 2019 में राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री की एकाएक शपथ ले ली। वह सरकार लगभग 82 घंटे ही चल पाई, पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी वैकल्पिक सरकार में एनसीपी कोटे से अजीत को ही उपमुख्यमंत्री बनाने से संदेश गया कि पवार परिवार की दरारें भर गई हैं। वह खुशफहमी तभी तक बरकरार रह पाई, जब तक कि शिवसेना में विभाजन से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा नई सरकार बनवाने में सफल नहीं हो गई। सरकार को विधानसभा में बहुमत प्राप्त था, फिर भी अजीत पवार एनसीपी तोड़ कर उसमें उपमुख्यमंत्री बन गए। उसके मूल में अजीत के सत्ता-प्रेम के साथ-साथ शिंदे पर भाजपा का अविश्वास भी बड़ा कारक रहा। 2024 के चुनाव में 288 सदस्यीय विधानसभा में अकेले दम 132 सीटें जीतने के बावजूद भाजपा ने शिंदे और अजीत को उपमुख्यमंत्री बनाते हुए गठबंधन सरकार बनाई। दरअसल अपेक्षाकृत विश्वसनीय अजीत को भाजपा अति महत्वाकांक्षी शिंदे पर नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल करती रही।

एनसीपी की आंतरिक राजनीति के बदले समीकरण● फाइल

अब जबकि अजीत पवार नहीं रहे, तो सवाल यही है कि क्या फडणवीस सरकार के समीकरण भी बदलेंगे? जाहिर है, इन दोनों सवालों का सही जवाब पवार परिवार की राजनीति पर निर्भर करेगा। पवार परिवार और उसकी राजनीति को जानने वाले मानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में मराठा राजनीति जिस तरह हाशिये पर खिसक गई है, उसके मद्देनजर खोया हुआ रुतबा पाने के लिए एनसीपी के दोनों गुटों के समक्ष एकता के अलावा कोई विकल्प नहीं। बेशक बेहतर पारिवारिक समझदारी इसमें मददगार होगी, लेकिन राजनीतिक सत्ता का बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। आखिर विधानसभा चुनाव में चाचा पर भारी पड़े भतीजे का परिवार राजनीतिक सत्ता में अपना हिस्सा क्यों नहीं चाहेगा? भाजपा को स्वाभाविक ही अजीत की पत्नी सुनेत्रा या दोनों बेटों-पार्थ और जय में से एक को उपमुख्यमंत्री बनाने में भी कोई रणनीतिक समस्या नहीं होगी, लेकिन बिना करिश्माई नेतृत्व के वह व्यवस्था कितनी लंबी चल पाएगी? बेशक प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता भी हैं, पर 2029 में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे, तो एनसीपी के अजीत गुट को चुनाव जिताऊ चेहरा चाहिए होगा। ऐसे में जीवन के संध्याकाल में खड़े शरद पवार को परिवार की सत्ता महत्वाकांक्षाओं में तर्कसम्मत संतुलन बिठाना होगा। सबसे अहम होगा एकजुट एनसीपी का नेतृत्व। खुद मार्गदर्शक की भूमिका स्वीकारते हुए शरद पवार अपनी बेटी को दिल्ली और अजीत के परिवार द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी को महाराष्ट्र की राजनीति सौंप कर एकता का फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन एकजुट एनसीपी की राजनीतिक राह चुनना दूसरी बड़ी चुनौती होगी। क्या बुजुर्ग पवार अपने भतीजे के परिवार और बेटी को सत्ता राजनीति में स्थापित करने के लिए विपक्षी मोर्चे आइएनडीआइए का मोह त्याग कर राजग में शामिल होंगे? वैसे भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में शायद ही कोई ऐसा हो, जिससे पवार का सीधा संपर्क और संवाद न हो। पवार तो कहे भी 'पावर प्लेयर' जाते हैं।

अगर एकजुट एनसीपी राजग में शामिल होती है, तो न सिर्फ महाराष्ट्र में सत्ता के माहिर सौदेबाज एकनाथ शिंदे पर भाजपा की निर्भरता समाप्त हो जाएगी, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश के दूसरे बड़े राज्य से ज्यादातर सीटें जीत कर अपने दम पर बहुमत हासिल करना भी आसान हो जाएगा। अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के टकराव के चलते एनसीपी के दोनों गुट एक नहीं हो पाए, तो ज्यादा संभावना देर-सबेर अजीत गुट के भाजपा में विलय की रहेगी, क्योंकि उसके 41 विधायक अगले चुनाव में भी जीत कर विधानसभा में लौटना चाहेंगे, जिसके लिए बड़े दल या नेता का नाम चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भविष्य की चिंता

अक्सर लोग असफलता के लिए अपनी निजी परेशानियों को दोष देते हैं, अतीत की कमियों और भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। यह स्थिति उन्हें बड़े फैसले लेने और आगे बढ़ने से रोकती रहती है। असल में अतीत और भविष्य की चिंता, दोनों ही हमारे दिमाग की उपज हैं। बीते कल पर आप चाहे जितना मलाल करें, वह बदल नहीं सकता और भविष्य को लेकर आप चाहे जितनी चिंता करें, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। वर्तमान में रहना ही सबसे अच्छा तरीका है।

अगर आप लगातार अतीत और भविष्य में उलझे रहेंगे, तो कभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में रहने के लिए आपको दो चीजें करने की जरूरत है। पहला, अपने अतीत को स्वीकार करें। बीते कल को देखने का सबसे अच्छा नजरिया यह है कि आप बस ये देखें कि पहले की तुलना में आज कितना आगे आ गए हैं। दूसरा, अपने भविष्य के बारे में सोचते समय यह ध्यान रहे कि भविष्य अनिश्चित होता है। स्वयं से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना या इसके उलट अपने प्रति बहुत नाउम्मीदी रखना बेकार है। भविष्य की चिंता से कोई फायदा नहीं है। भविष्य की चिंता करना उस उधार को चुकाने के समान है, जो आपने कभी लिया ही नहीं। बीता कल गुजर चुका है, इससे सीखा जा सकता है। आने वाला कल सामने है, इसके लिए तैयार हुआ जा सकता है, लेकिन आज और वर्तमान ही है, जिसे जिया जा सकता है। यानी अपने बीते कल को बिना किसी मलाल के स्वीकार करें, अपने वर्तमान का आत्मविश्वास से सामना करें और आने वाले भविष्य का निडर होकर स्वागत करें।

कुल मिलाकर बीते कल, आज और आने वाले कल के प्रति आत्मविश्वास बनाए रखना ही खुश रहने और आगे बढ़ने का तरीका है। आप बीते कल को उसके दिए सबक के लिए धन्यवाद दे सकते हैं और अपने आने वाले कल से कह सकते हैं, मैं तैयार हूं।

राजेंद्र कुमार जांगिड़

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

संस्कृति के विरुद्ध लिव-इन संबंध

'सवालों के घेरे में लिव-इन संबंध' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में ऋतु सारस्वत ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप हमारे देश की विवाह परंपरा का हिस्सा नहीं है। यदि हमारे देश में लिव-इन रिश्तों की स्वतंत्रता दे दी गई, तो यह सच है कि विवाह का पवित्र बंधन भी दागदार हो जाएगा। फिर बहुत से पुरुष और महिलाएं थोड़े-थोड़े समय बाद अपना जीवनसाथी बदलते रहेंगे। परिणामस्वरूप हमारे देश में नैतिकता का गंभीर पतन होगा और अदालतों में इससे संबंधित मामलों का अंबार लग जाएगा। इसलिए कानून और समाज, दोनों को इस रिश्ते को मान्यता बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन तभी अच्छा लगता है जब वह उचित हो और प्रकृति के नियम के दायरे में हो। महिला हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, दोनों को शादी या लिव-इन रिलेशन के लिए तभी हामी भरनी चाहिए, जब रिश्ता निभाने की नीयत हो। सच में रिश्ते वही टूटते हैं, जिनमें स्वार्थ हो, विश्वास की कमी हो या फिर प्रतिशोध की भावना हो। हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा में लिव-इन रिलेशन है ही नहीं और जो संस्कृति की परंपरा के विरुद्ध चलेगा, उसके रिश्ते की बुनियाद कभी मजबूत नहीं हो सकती। जिस देश में पति-पत्नी के रिश्ते की डोर को मजबूत करने की परंपरा रही हो, उसी देश में आज तलाक के मामले और पति-पत्नी के रिश्तों में खटास बढ़ रही है। ऐसे में पश्चिमी सभ्यता की नकल वाला गया लिव-इन भला कैसे मजबूत हो सकता है?

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

कुष्ठ रोग के खिलाफ निर्णायक लड़ाई

कुष्ठ रोग जिसे हैनसेन रोग भी कहा जाता है, मानव इतिहास की सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है। दुर्भाग्यवश आज भी यह बीमारी केवल स्वास्थ्य की नहीं बल्कि सामाजिक सोच की भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को बीमारी से ज्यादा उस भेदभाव, उपेक्षा और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है, जो अज्ञानता और भय से जन्म लेता है। इसी सोच को बदलने और समाज को यह संदेश देने के लिए कि कुष्ठ रोग पूरी तरह इलाज योग्य है, भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से जुड़ा है, जिन्होंने अपने जीवन में कुष्ठ रोगियों के साथ न केवल सहानुभूति दिखाई बल्कि उनके सम्मान और पुनर्वास के लिए भी लगातार काम किया। यह दिवस केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं है, बल्कि सरकार और समाज दोनों के लिए यह आत्ममंथन का अवसर है। भारत में कुष्ठ रोग की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय लगभग 80 से 90 हजार सक्रिय कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं। हर वर्ष करीब एक लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं, जो कुल वैश्विक मामलों का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग उन्मूलन की स्थिति हासिल कर ली है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

हादसों से सबक लेना जरूरी

महाराष्ट्र के पुणे में हुए विमान हादसे ने देश में हवाई सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न उठाया है कि क्या भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली वास्तव में सुरक्षित है? दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ऐसे हादसों में केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि आम नागरिक और अनुभवी पायलट भी अपनी जान गंवाते रहे हैं। अतीत में भी देश ने कई दर्दनाक हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं। वर्ष 2010 की मंगलुरु विमान दुर्घटना हो, 2020 का कोझिकोड हादसा हो, 2025 में अहमदाबाद हादसा या विभिन्न हेलीकाप्टर दुर्घटनाएं जिनमें देश के प्रथम रक्षा प्रमुख विपिन रावत समेत कई वरिष्ठ नेता और सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। हर बार जांच आयोग बनता है, रिपोर्ट आती है, लेकिन क्या उन सिफारिशों को पूरी गंभीरता से लागू किया जाता है? आवश्यकता है कि हम केवल संवेदना व्यक्त करने तक सीमित न रहें, बल्कि यह भी पूछें कि चार्टर विमानों और वीवीआइपी उड़ानों की सुरक्षा मानकों की नियमित और स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होती? क्या ब्लैक बाक्स की रिपोर्ट समय पर सार्वजनिक की जाती है? क्या जिम्मेदारी तय होती है? हवाई यात्रा विश्वास पर टिकी है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और ठोस सुधार अब टाले नहीं जा सकते। कहा जा रहा है कि यह हादसा कम दृश्यता के कारण हुआ है।

अंकित पटेल, जम्मू

पोस्ट

पाकिस्तान बोर्ड आफ पीस में शामिल हो गया है। ट्रंप के घोटाले के जाल में फंसने के लिए पाकिस्तान को बधाई।

डेरेक जे. ग्रोसमैन@DerekJGrossman

जितना मैं मार्क कार्नी की बातें सुनता हूं, उनसे उतना ही प्रभावित होता जाता हूं। कनाडा ने अपने देश के लिए एकदम सही नेता चुना है।

बोस्टन स्माल्स@smalls2672

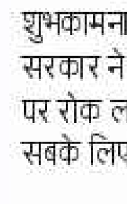

देखा जाए तो सभी जातियां किसी न किसी रूप में पिछड़ी हैं। कुछ सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं, कुछ शैक्षणिक रूप से, कुछ वित्तीय रूप से और कुछ जातियां तीनों ही पैमानों पर पिछड़ी हैं।

कमलेश सिंह@kamleshksingh

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर स्टे लगा दिया है। उसी के निर्देश पर ये नियम आए थे। अच्छा निर्णय है और जिन्होंने अपने हक की आवाज उठाई, उन्हें भी शुभकामना। यह मुद्दा अब सुलझ जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी सकारात्मक संकेत देकर यूजीसी नियमों पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट में विरोध नहीं किया। यह सबके लिए 'विन-विन सिचुएशन' है।

बालियान@Baliyan_x

जनपथ

छोटी को छोटा रखो काटो बड़ी लकीर,
जिनमें दिखता बुद्धि-बल कर दो उन्हें फकीर!
कर दो उन्हें फकीर तभी आएगी समता,
चल करके यह चाल देश की रौंदो क्षमता।
यूजीसी की नीति लगाकर तोहमत झूठी,
करिए बड़ी लकीर हो सके जितनी छोटी!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 196

संसद प्रश्नोत्तर

यमुना जल हस्तांतरण पर गठित किया टास्क फोर्स

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि हथनीकुंड से राजस्थान में भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से यमुना जल पहुंचाने पर डीपीआर तैयार करने के लिए हरियाणा और राजस्थान ने टास्क फोर्स का गठन किया है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि हरियाणा और राजस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों राज्यों ने हथनीकुंड से चूरू, सीकर, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों में भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से यमुना जल हस्तांतरण पर डीपीआर तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है।

हिंदुओं पर हमलों के मामले में भारत की नजर

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने राज्यसभा को बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं पर भारत की नजर है। नई दिल्ली ने इस मुद्दे को ढाका के अधिकारियों के साथ ''लगातार उठाया'' है। विदेश मंत्रालय के राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित उत्तर में कहा भारत की अपेक्षा है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इन घटनाओं की ''गंभीरता से जांच'' करेगी और ''अल्पसंख्यकों के खिलाफ हत्या, आगजनी व हिंसा के सभी अपराधियों को बिना किसी बहाने के न्याय के कटघरे में लाएगी। भारत सरकार अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं की निगरानी रखे हुए है।

भारत में 10 लाख की आबादी पर 22 जज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर लगभग 22 जज हैं। विधि आयोग ने 1987 में अपनी 120वीं रिपोर्ट में प्रति 10 लाख आबादी के लिए 50 जजों की सिफारिश की थी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित उत्तर में कहा कि इस समय देश में जज-और-जनसंख्या का अनुपात लगभग 22 जज प्रति 10 लाख आबादी है। मेघवाल ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या 3,89,910 थी।

वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों पर पुख्ता डाटा नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का सीधा संबंध साबित करने के लिए कोई पुख्ता डाटा नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) सकारात्मक परिणाम दिखा रहा है। कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, कोई पुख्ता डाटा नहीं है जिससे जिससे वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का सीधा संबंध स्थापित किया जा सके। यानी पक्के तौर पर कहा जा सके कि मौत केवल वायु प्रदूषण के कारण ही हुई है।

18 हजार रोजगार मेलों में 2.22 करोड़ को नौकरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा को बताया कि पिछले वर्ष देशभर में 18 हजार रोजगार मेलों में 2.22 करोड़ लोगों को नौकरी दी गई। देश में बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत है, जो विकसित देशों से भी कम है। मनसुख मांडविया ने पूरक प्रश्नों के उत्तर में उच्च सदन को बताया कि सरकार ने रोजगार देने के लिए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल बनाया है। सरकारी क्षेत्र में 11.49 लाख नौकरियां दी हैं। 4.5 लाख युवाओं ने मेलों में भाग लिया, जिनमें से 90 हजार को शार्टलिस्ट किया गया व 43 हजार को केंद्रीय और राज्य स्तर की कंपनियों द्वारा नौकरी दी गई।

बीते महीने एयरलाइंस ने रद की थीं 6,890 उड़ानें

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने संसद को बताया कि बीते महीने दिसंबर में 6,890 उड़ानें रद की गईं, जिससे 9.66 लाख से अधिक यात्रियों पर असर पड़ा। आधिकारिक डाटा के अनुसार, इनमें से 82 प्रतिशत से अधिक उड़ानें इंडिगो ने रद कीं। नियामक ने कुल 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहाल ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि परिचालन में बाधा के प्रमुख कारणों में अपर्याप्त नियामक तैयारी, सिस्टम साफ्टवेयर में कमी और इंडिगो प्रबंधन और परिचालन नियंत्रण में कमियां शामिल हैं।

बजट से रिफार्म एक्सप्रेस को मिलेगी गति, पीएम मोदी ने दिए संकेत

नीलू रंजन • जागरण

- ईयू के साथ एफटीए को निर्माताओं और युवाओं के लिए बताया बड़ा अवसर
- विपक्षी सांसदों को किया आगाह, पीएम ने कहा- यह समय व्यवधान का नहीं

नई दिल्ली: रविवार को पेश होने वाले बजट में रिफार्म एक्सप्रेस को गति देने के लिए विशेष प्रविधान होंगे। पीएम नरेन्द्र मोदी ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद दुनिया के बाजार में भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के प्रविधान हो सकते हैं। पीएम ने हंगामा कर सदन की कार्यवाही बाधित करने वाले विपक्षी सांसदों को भी आगाह किया व कहा आज समय व्यवधान का नहीं है, समाधान का है। बजट सत्र के दूसरे दिन संसद परिसर में अपने पारंपरिक संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म पर सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि सकारात्मक शक्ति से रिफार्म एक्सप्रेस को लगातार गति मिल रही है। देश अब लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से बाहर निकल आया है और समाधान के रास्ते पर बढ़ गया है। रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार देश अब अगली पीढ़ी के सुधारों की ओर बढ़ने वाला है।

पीएम ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते को भारत के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की झलक बताया। उन्होंने इसे आकांक्षी युवाओं के लिए मुक्त व्यापार कहा। उन्होंने कहा कि ''मदर आफ आफ डील्स'' से भारतीय उद्योगों और निर्माताओं के लिए बहुत बड़ा बाजार खुल गया है। माना जा रहा है कि यूरोपीय देशों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास के लिए बजट में विशेष प्रविधान हो सकता है। इसके साथ ही भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी निवेश बढ़ाने, नई यूनिट लगाने और मौजूदा यूनिट के विस्तार के लिए नियमों और प्रक्रियाओं में ढील देने की घोषणा हो सकती है।

सरकार केवल फाइलों तक सीमित नहीं: प्रेट्र के अनुसार, मोदी ने कहा, हमारी सरकार केवल फाइलों तक सीमित नहीं है। यह कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना भी सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 25 वर्षों के महत्व पर जोर दिया।

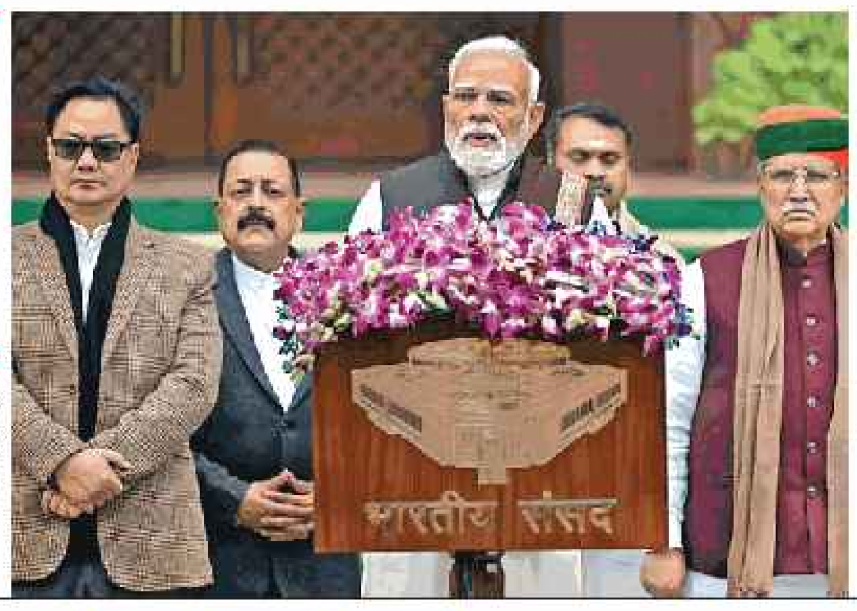

बजट सत्र के दूसरे दिन मीडिया को संबोधित करते मोदी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह, एल मुरुगन और अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे • एएफपी

'एआइ के नैतिक उपयोग पर समझौता नहीं होना चाहिए'

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के नैतिक उपयोग पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने एआइ कौशल और प्रतिभा विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारत का एआइ पारिस्थितिकी तंत्र देश के चरित्र और मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। भारत के पास विशालता, विविधता और लोकतंत्र का अनूठा संयोजन है।

सदन में बातचीत कर रहे सांसदों को स्पीकर ने लगाई कड़ी फटकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान आपस में लगातार बातचीत कर रहे सदस्यों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि यदि वे आपस में ही लंबी चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें सदन से बाहर जाना चाहिए। उधर, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बजट सत्र के दौरान ऊपरी सदन के सदस्यों से शिष्टाचार बनाए रखने और रचनात्मक बहस का आह्वान किया।

स्पीकर ने कहा कि उन्होंने देखा है कि दोनों पक्षों के सदस्य एक-दूसरे से लगातार बात कर रहे हैं, जिससे अन्य सदस्यों को परेशानी हो रही है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संक्षिप्त बातचीत की अनुमति है, लेकिन लंबी चर्चाओं की नहीं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल से कहा कि वे अपने साथी सदस्यों के साथ बातचीत को संक्षिप्त करें। उधर, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को उच्च सदन के 270वें सत्र की शुरुआत करते हुए सदस्यों से अनुरोध किया कि वे बजट 2026-27 व अन्य विधायी प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संसद में शिष्टाचार के उच्चतम मानकों को बनाए रखें।

राज्यसभा में उठा सोने-चांदी की कीमतों का मुद्दा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सोने-चांदी की कीमतों की बढ़ोतरी का मुद्दा राज्यसभा में उठा। शून्यकाल में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से सोने-चांदी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि सोने-चांदी की बेकाबू हो चुकी कीमतों ने गांवों में रहने वाले भारतीयों की कमर तोड़ दी है। ग्रामीण भारत, खासकर महिलाएं परेशान हैं।

विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषि उत्पादकता बड़ी चुनौती : सर्वे

उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास पर्याप्त नहीं, कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत

अरविंद शर्मा • जागरण

नई दिल्ली : विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और निवेश बढ़ाने की जरूरत है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में कृषि क्षेत्र की औसत विकास दर 4.4% रही है एवं पैदावार भी रिकार्ड स्तर पर पहुंची है। किसानों की आय में स्थायी वृद्धि के साथ कृषि को मजबूत आधार देने के लिए बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार की जरूरत है।

सर्वेक्षण के अनुसार सरकार का मानना है कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए खेती को व्यापक सुधारों और नए सोच के साथ आगे बढ़ाना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में माना गया है कि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। केवल एमएसपी के सहारे किसानों की आय को लंबे समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता। खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लागत कम करने, बेहतर तकनीक अपनाने और बाजार से बेहतर जुड़ाव की जरूरत है। सर्वेक्षण में उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को खेती के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का आदर्श अनुपात 4:2:1 माना जाता है, लेकिन मौजूदा समय में यह संतुलन बेहद बिगड़ चुका है। यूरिया की खुदरा कीमत मार्च 2018 से 242 रुपये प्रति 45 किलो बैग पर अपरिवर्तित है। प्रेट्र के अनुसार सर्वेक्षण में किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण की सिफारिश भी की गई है। जलवायु परिवर्तन को भी बड़ी चुनौती बताया गया है। वहीं कृषि ऋण की तस्वीर भी संतोषजनक नहीं है। कुल कृषि ऋण का लगभग 23.4% हिस्सा साहूकारों से लिया जा रहा है।

बजट सत्र के दौरान लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पर बोलती हुई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण • एएनआइ

- देश में पैदावार बढ़ी, लेकिन कई विकसित देशों के मुकाबले अभी भी कृषि उत्पादकता काफी कम
- आर्थिक सर्वेक्षण में माना गया है कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं

समग्र कृषि विकास (2020-24) (% में)

समेकित कृषि क्षेत्र	4.70
फसलें	4.00
पशुपालन	6.10
मत्स्य पालन	7.20

सात प्रतिशत विकास दर हासिल करके रहेंगे: सीतारमण

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की आर्थिक बुनियाद पहले से कहीं अधिक मजबूत है व देश ने वैश्विक आर्थिक दबावों को सफलतापूर्वक पार करते हुए उच्च विकास पथ पर अपनी स्थिति सुदृढ़ की है। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद 'एक्स' पर प्रतिक्रिया देते हुए, सीतारमण ने कहा कि भू-राजनीतिक विभाजन व आर्थिक अनिश्चितता से भरी दुनिया में भारत एक उज्ज्वल वैश्विक उदाहरण के रूप में उभर रहा है, जो लचीला, स्थिर और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, 'हमारी मैक्रोइकोनामिक फंडामेंटल्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत को उच्च विकास की दिशा में ले जाने में हम सफल रहे हैं व संभावित जीडीपी वृद्धि दर को सात प्रतिशत तक बढ़ाया है। इस लक्ष्य को हम हासिल करके रहेंगे।'

बच्चों को इंटरनेट मीडिया की बढ़ती डिजिटल लत से बचाना है तो लगाने होंगे कड़े प्रतिबंध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में बढ़ती डिजिटल लत को लेकर सरकार ने गंभीर चिंता जताते हुए इसके नियमन की जरूरत बताई है। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया और अन्य आनलाइन प्लेटफार्म पर बच्चों और किशोरों की बढ़ती निर्भरता उनके मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई व सामाजिक जीवन पर बुरा असर डाल रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सर्वेक्षण ने आनलाइन कंपनियों को उम्र सत्यापन के लिए जिम्मेदार बनाने और बच्चों के लिए सरल व सुरक्षित डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा कि बच्चों को बेसिक फोन देने की सलाह दी है। दुनियाभर में छोटे बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया को खतरनाक बताया जा रहा है। आस्ट्रेलिया, फिनलैंड ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध भी लगाया है। दुनिया के दूसरे नंबर के स्मार्टफोन बाजार, भारत के लिए ये खास चिंता का विषय इसलिए भी है, क्योंकि देश में सालाना 75 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन बिकते हैं। रिसर्च फर्म डाटारिपोर्टल के अनुसार, देश में एक अरब से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं, 50 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब यूजर, 40 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर और 48 करोड़ से अधिक इंस्टाग्राम यूजर हैं। इन एप्स पर 75% से ज्यादा छोटी उम्र के यूजर्स हैं। वहीं सर्वेक्षण में कहा गया है कि मोटापा खतरनाक दर से बढ़ रहा है और आज भारत में एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन • एएनआइ

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में डिजिटल लत से निजात के लिए कई सिफारिशें
- आनलाइन प्लेटफार्म पर बच्चों के लिए उम्र सत्यापन अनिवार्य करने की सिफारिश
- बच्चों को स्मार्टफोन की जगह सरल और सुरक्षित बेसिक फोन देने की सलाह
- आस्ट्रेलिया, फिनलैंड ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध भी लगाया है

प्रतिबंधों के बेअसर होने की भी चिंता

कुछ एक्टिविस्ट और टेक विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि बच्चों के मामले में शायद उम्र आधारित प्रतिबंध काम न करें, क्योंकि नकली पहचान दस्तावेजों के जरिये सिस्टम को बाइपास करने का जोखिम रहेगा। बच्चों और माता-पिता को इंटरनेट मीडिया के स्वस्थ और सुरक्षित उपयोग को विकसित करने में मदद करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

सर्वे में ऋग्वेद से लेकर लेनिन तक का उल्लेख

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में ऋग्वेद से लेकर रामायण तक और व्लादिमिर इलिच लेनिन तक कई संदर्भों का उल्लेख किया गया है। रामायण जटिल और प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में रणनीतिक शिक्षा के लिए मूल्यवान रूपक प्रदान करता है। युद्ध कांड में रावण की पराजय का क्षण विवेक का पाठ बन जाता है, क्योंकि भगवान राम यह दर्शाते हैं कि शत्रुओं से भी अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है, भले ही उनके मूल्यों या विधियों को न अपनाया जाए। लेनिन के प्रसिद्ध कथन का भी उल्लेख किया गया है। 'कई दशक ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता व कई सप्ताह ऐसे होते हैं जिनमें दशकों का काम हो जाता है।'

सर्वे में उच्च शिक्षा के समक्ष जीइआर बढ़ाने की बड़ी चुनौती

सर्वेक्षण ने दिखाई शिक्षा को नए रास्ते पर चलने की राह, पिछले सालों में ड्राप आउट दर में कमी, खत्म करने की चुनौती बरकरार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: सबको अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में भले ही केंद्र व राज्य सरकारों ने पिछले सालों में कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बाद भी स्कूली शिक्षा के सामने ड्रापआउट खत्म करने और उच्च शिक्षा के सामने अपने जीईआर को बढ़ाने की बड़ी चुनौती अभी भी बरकरार है। मौजूदा समय में प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट की दर 1.9 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2 प्रतिशत व माध्यमिक स्तर पर 14.1 प्रतिशत है। वहीं उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) अभी भी करीब 28 प्रतिशत है। आर्थिक सर्वेक्षण में यह चिंता तब जताई गई है, जब 2030 तक स्कूली शिक्षा के जीईआर को सभी स्तरों तक शत-प्रतिशत करने और उच्च शिक्षा के जीईआर को 2035 तक 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। सर्वेक्षण के मुताबिक स्कूली शिक्षा में बारहवीं का जीईआर 58.4% है वहीं पहली से पांचवीं कक्षा तक की जीईआर 90.9% है। इससे साफ है कि बड़ी संख्या में बच्चे बारहवीं तक आते-आते पढ़ाई अभी भी छोड़ देते है।

शहरों के असंतुलित विकास पर गंभीर सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में शहरों के असंतुलित विकास पर आर्थिक सर्वेक्षण में गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही शहरी विकास से जुड़ी एजेंसियों को आइना दिखाते हुए कहा गया है कि सिर्फ फुटपाथ ठीक करने से कोई शहर रहने योग्य नहीं बन जाते हैं बल्कि उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन व रोजगार जैसी तमाम सुविधाएं भी जुटाना जरूरी है, जो शहर के साथ उनके बेहतर जीवन स्तर और विकास के लिए जरूरी है। हालांकि पिछले कुछ बजट में शहरी विकास को लेकर सरकार की चिंताएं दिखती रही हैं लेकिन जिस सख्ती से आज के हालात को बयां किया गया है उसका यह भी संदेश है कि बजट में कुछ खास प्रविधान होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में शहरीकरण को नागरिक केंद्रित रखने को लेकर यह जोर तब दिया गया है, जब शहरों के विकास को सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर तक सीमित कर दिया गया है। शहरी विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर जरूरी है लेकिन इसके साथ ही नागरिक केंद्रित विकास भी जरूरी है। जिसमें शहरों में रहने वाली आबादी के लिए साफ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सुरक्षा, मनोरंजन, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों आदि को बढ़ाने पर जोर देना होगा। प्रत्येक शहर के मिजाज और सांस्कृतिक विरासत के आधार पर उसके विकास पर फोकस होना चाहिए। सर्वेक्षण में अमेरिका के डेट्रायट और बोस्टन शहर का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि डेट्रायट जहां राजमार्गों व कारखानों में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया, लेकिन नागरिक सुविधाओं पर वैसा ध्यान नहीं दिया गया।

- सिर्फ फुटपाथ ठीक करने से कोई शहर रहने योग्य नहीं बनता
- शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता जैसी सुविधाएं जुटाना भी जरूरी

ईमानदार अधिकारियों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाने की जरूरत

कैग-सीवीसी जैसी संस्थाओं को सलाह, अच्छे इरादे से लिए गए फैसलों को भ्रष्टाचार से अलग कर देखने की जरूरत

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत को जिस 'उद्यमशील राज्य' की सख्त जरूरत है, उसके लिए ईमानदार अधिकारियों को निरर्थक और परेशान करने वाले अभियोजन से संरक्षण देना अनिवार्य है। यह बात आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कही गई है, जिसे संसद में पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश सर्वेक्षण में कहा गया है कि कानूनी और संस्थागत ढांचे ऐसे होने चाहिए, जो सद्भावना में लिए गए निर्णयों को सुरक्षा प्रदान करें और गलती व भ्रष्टाचार के बीच स्पष्ट अंतर तय करें। हर नकारात्मक नतीजा न तो गलत मंशा का परिणाम होता है और न ही अक्षमता का। कई बार विफलताएं अनुमानों की चूक, समय, समन्वय या जवाबदेही के समय-चक्र से जुड़ी होती हैं। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व सतर्कता संस्थाओं के दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत पर बल दिया गया है। 'पूर्व-निर्धारित स्पष्टता व बाद की अनुपातिक समीक्षा, वास्तविक समय की सख्त निगरानी से अधिक महत्वपूर्ण है।'' आने वाले दशकों में भारत को ऐसे फैसले लेने होंगे, जिनके लिए कोई तयशुदा मार्गदर्शिका नहीं होगी।

धोखाधड़ी से विवाह या लिव इन में रहने पर होगी सात साल की सजा

विकास गुसाईं • जागरण

- समान नागरिक संहिता में संशोधन, अध्यादेश में किया गया कड़ी सजा का प्रविधान
- नाबालिग होने का तथ्य छिपा कर विवाह करने पर भी होगी सजा, अर्थदंड भी लगेगा

देहरादून: उत्तराखंड में अब कोई व्यक्ति यदि बल, दबाव या धोखाधड़ी से विवाह करता है अथवा फर्जीवाड़े से किसी के साथ लिव इन में रहता है, तो ऐसे मामलों में आरोपित के लिए सात साल कैद की सजा का प्रविधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत किसी विवाहित का बिना संबंध विच्छेद किए दूसरा विवाह करना या लिव इन में रहना भी दंडनीय अपराध होगा।

वहीं, गलत जानकारी देकर नाबालिग के साथ विवाह करने अथवा लिव इन में रहने वालों को छह माह की सजा व 50 हजार का जुर्माना देना होगा। ऐसे मामलों में आरोपित पर पोक्सो के साथ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अलग से भी मुकदमा चलेगा। प्रदेश सरकार ने इसी माह लोकभवन की स्वीकृति के बाद समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) अध्यादेश जारी किया है। इसमें इस बार सजा के कड़े प्रविधान किए गए हैं।

बाल विवाह के आरोपित पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। यदि कोई गैर कानूनी तरीके से विवाह-विच्छेद करता है तो उस पर तीन साल तक के कारावास की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगेगा। यदि कोई विवाह के लिए अपनी पहचान छिपाता है या गलत जानकारी देता है तो उसका यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय होगा। पति या पत्नी के जीवित होने के बावजूद यदि कोई दूसरा विवाह करता है तो उसे बीएनएस के प्रविधानों के तहत दंड दिया जाएगा।

एनसीएलटी की सुस्ती से दिवालिया कानून सुधार हो रहे बेअसर

- सर्वेक्षण में कड़ी आलोचना, 10 साल लग सकते हैं लंबित मामलों के निपटारे में
- आइबीसी व कंपनी एक्ट के मामलों को संभालने के लिए हैं 30 एनसीएलटी बेंच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: बैंकों की ऋण वसूली की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से बनाए गए दिवालिया कानून (आइबीसी) दिवाला निश्चित तौर पर एक बड़ा सुधारवादी कदम है लेकिन राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में लंबित मामलों की भारी संख्या और फैसलों में देरी इसकी प्रभावशीलता को कमजोर कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में इसकी कड़ी आलोचना कर कहा गया कि मार्च, 2025 तक एनसीएलटी में करीब 30,600 मामले लंबित हैं और मौजूदा निपटारे की दर से इन्हें सुलझाने में 10 साल लग सकते हैं। इस तरह की देरी से 'संपत्तियों का मूल्य घटता है, कर्मचारी कंपनी छोड़ देते हैं, ग्राहक प्रतिस्पर्धियों की ओर रुख करते हैं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध टूट जाते हैं।' वैसे केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष इसकी खामियों को दूर करने के लिए आइबीसी में नया संशोधन किया, लेकिन उससे हालात कितने सुधरेंगे, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। सर्वेक्षण में एनसीएलटी के मौजूदा ढांचे की खामियों पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संस्थागत बाधाएं न केवल अदालतों में बल्कि रिजाल्यूशन प्रोफेशनल्स के स्तर पर भी मौजूद हैं। पूरे देश में आइबीसी व कंपनी एक्ट के मामलों को संभालने के लिए केवल 30 एनसीएलटी बेंच हैं, जबकि 4,527 पंजीकृत आरपी में से केवल 2,198 ही सक्रिय असाइनमेंट के लिए अधिकृत हैं। आरपी एनसीएलटी की तरफ से नियुक्त पेशेवर दिवालिया कानून के तहत कंपनी बंद करने या उसकी हिस्सेदारी व परिसंपत्तियां बेचने व दायित्वों के निपटान की जिम्मेदारी संभालते हैं।

आइबीसी के तहत कार्पोरेट इनसाल्वेंसी रिजाल्यूशन प्रोसेस को 330 दिनों में पूरा करना होता है, पर औसतन यह 713 दिनों तक खिंचता है। वित्त वर्ष 2025 में बंद हुए मामलों में औसत 853 दिन रहा, जो वैधानिक सीमा से 150 प्रतिशत अधिक है। 2021 में छोटे उद्यमों के लिए शुरू की गई प्री-पैकेज्ड इनसाल्वेंसी रिजाल्यूशन प्रोसेस को सरल, तेज व कम लागत वाली प्रक्रिया के रूप में पेश किया गया, लेकिन सर्वेक्षण में इसके कम उपयोग की वजहें प्रक्रिया की जटिलता, एमएसएमई सेक्टर के लोगों में इसके लिए जागरुकता की कमी, छोटे उद्यमों की फंडिंग की असमर्थता आदि बताई गई है।

एथेनाल मिश्रण से विदेशी मुद्रा की बचत, मगर खाद्य सुरक्षा पर संकट

नई दिल्ली, प्रेट्र : आर्थिक सर्वेक्षण (2025-26) के अनुसार, भारत का एथेनाल सम्मिश्रण कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बनकर उभरा है। अगस्त 2025 तक, इस पहल ने 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई है और लगभग 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रतिस्थापित किया है। हालांकि, सर्वेक्षण ने आगाह किया है कि एथेनाल उत्पादन के लिए मक्का पर बढ़ती निर्भरता देश की खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही है। सरकार द्वारा मक्का-आधारित एथेनाल के लिए दी जा रही अनुकूल मूल्य निर्धारण नीतियों के कारण किसान अन्य फसलों को छोड़कर मक्के की ओर रुख कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच मक्का-आधारित एथेनाल की कीमतों में 11.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देखी गई, जो चावल या शीरे की तुलना में अधिक है।

होम लोन चार गुना बढ़कर 37 लाख करोड़, जीडीपी में हिस्सेदारी 11 प्रतिशत

नई दिल्ली, प्रेट्र: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारत में आवास ऋण का दायरा लगातार विस्तृत हुआ है। मार्च 2025 के अंत तक व्यक्तिगत होम लोन बकाया राशि लगभग चार गुना बढ़कर 37 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यह मार्च 2015 में करीब 10 लाख करोड़ थी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि जीडीपी के अनुपात में होम लोन की हिस्सेदारी 2015 में आठ प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 11 प्रतिशत हो गई है, जो आवास मांग के बढ़ते वित्तीयकरण को दर्शाती है। कोविड-19 महामारी के बाद आवास बिक्री में तेजी आई है, जिससे होम लोन की मांग को मजबूती मिली। 'रियल एस्टेट व आवास स्वामित्व' क्षेत्र ने पिछले एक दशक में औसतन सालाना सकल मूल्य वर्धन में लगभग सा प्रतिशत का योगदान दिया है।

2030 तक रोजगार में हो सकती 13 प्रतिशत वृद्धि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: रोजगार वृद्धि के संकेतकों पर संतोष की मुहर लगाते हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने इस दिशा में तेज सुधारों पर जोर दिया है। व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्यबल के मौजूदा अनुपात की चर्चा करते हुए 2025 की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि यदि औपचारिक कौशल प्रशिक्षण में निवेश के माध्यम से कुशल कार्यबल में 12 प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो वर्ष 2030 तक श्रम प्रधान क्षेत्रों में रोजगार में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा कौशल विकास पर विस्तार से चर्चा करते हुए विशेषज्ञों ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) के डिप्लोमा को स्नातक स्तर की डिग्री में परिवर्तित करने का भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया है।

विशेषज्ञों ने कौशल विकास की मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भविष्य के लिए रोडमैप दिखाने का भी प्रयास किया है। समीक्षा में कहा गया है कि पीएलएफएस 2023-24 के निष्कर्षों के मुताबिक, 15-59 आयु वर्ग में किसी न किसी रूप में व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के आंकड़े में सुधार हुआ है। यह वर्ष 2017-18 में 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 34.7 प्रतिशत हो गया। यह भारत में कौशल विकास पहलों के सकारात्मक प्रभाव को दिखाता है, लेकिन चुनौती यह भी है कि 15-29 वर्ष आयु वर्ग के केवल 4.9 प्रतिशत युवाओं ने ही औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि 21.2 प्रतिशत युवाओं ने अनौपचारिक स्त्रोतों से प्रशिक्षण लिया है। इसे देखते हुए ही कौशल प्रशिक्षण का विस्तार करने की सलाह दी गई है।

- आर्थिक सर्वेक्षण में रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार पर जोर
- आइटीआइ के डिप्लोमा को स्नातक स्तर की डिग्री में परिवर्तित करने का भी विशेषज्ञों ने दिया है सुझाव

स्कूली शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता बताई

आर्थिक सर्वे में राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के निष्कर्षों के आधार पर बताया गया है कि केवल 47 प्रतिशत स्कूल कक्षा नौ और उससे ऊपर के स्तर पर कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। इसमें भी भागीदारी मात्र 29 प्रतिशत है। विशेषज्ञों ने शुरुआती चरण में ही सामान्य शिक्षा में व्यापक व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। साथ ही कृषि और सेवाओं को रोजगार सृजन की उच्च क्षमता वाला बताते हुए इनमें कौशल विकास की जरूरत बताई है।

2030 के आसपास चरम पर होगा जनसांख्यिकीय लाभांश

भारत की जनसंख्या यदि उसकी शक्ति है तो उसके सामने कुछ चुनौतियां भी खड़ी नजर आ रही हैं। विशेषज्ञों ने इस पर चर्चा करते हुए उल्लेख किया है कि भारत अपनी कार्यशील आयु (15-59 वर्ष) की जनसंख्या से लगातार लाभान्वित हो रहा है, जिसके अगले दस वर्षों में 98 करोड़ से अधिक होने की संभावना है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश 2030 के आसपास अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है, जब कुल जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में होगा।

सर्वे ने एआइ पर दिखाया सरकार को आईना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस (एआइ) को लेकर गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत सरकार के समक्ष कुछ कड़वी सच्चाइयों को बेबाकी से पेश किया है। परंपरा से हटकर, सर्वेक्षण ने सरकार को आइना दिखाने का भी काम किया है ताकि एआइ की हकीकत और उसके महत्व की समय रहते पहचान की जाए और सही कदम उठाया जा सके।

सर्वे में चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं किया गया है तो तेजी से तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी, सीमित संसाधनों और लगातार अनिश्चितता वाले वैश्विक इकोसिस्टम में भारत सिर्फ एक ग्राहक बनकर रह जाएगा। जबकि कोशिश एआइ के विकास और उपयोग में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो यह भारत के लिए काफी जोखिमपूर्ण स्थिति होगी। इस क्षेत्र में देरी से प्रवेश कर रहे भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वह दूसरे देशों के अनुभव से इसमें बहुत कुछ सीख सकता है और कम ऊर्जा खपत वाले ज्यादा सक्षम एआइ माडल को विकसित कर सकता है।

सर्वे में एआइ रेगुलेशन पर सलाह दी गई है कि आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप संवेदनशील तरीके से डिजाइन करने पर भारत का जोर होना चाहिए। विभिन्न देशों के एआइ से जुड़े मूल डिजाइन में अंतर को रेखांकित करते हुए सर्वेक्षण का सुझाव है कि भारत को ऐसी स्थिति से जूझना पड़ेगा, जहां संसाधनों की कमी होगी और दूसरी बाधाएं होंगी। यहां संतुलन बनाने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

रेगुलेशन को लेकर एक सुझाव यह है कि भारत में एआइ को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाए और उसके बाद ही इससे जुड़ी क्षमता को विकसित किया जाए। अंत में बाध्यकारी नीतियां लागू करने का सुझाव है ताकि संस्थाएं और बाजार साथ-साथ विकसित हो सकें। सर्वेक्षण सलाह देता है कि भारत को बड़े पैमाने पर फाउंडेशनल माडल को प्रशिक्षित करने में संसाधन झोंकने के बजाय छोटे, खास कार्य के लिए चिन्हित एआइ माडल्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हार्डवेयर (स्मार्ट फोन, पीसी) पर चल सकें।

- कहा- सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपभोक्ता बनकर नहीं रह जाए भारत
- एआइ के विकास व उपयोग में सार्थक योगदान देने वाले देश बनने की हो कोशिश

पहले के अनुभवों से सीख सकता है भारत

भारत को घरेलू रूप से क्या बनाना है, वैश्विक रूप से क्या सोर्स करना है, क्या जल्दी रेगुलेट करना है और क्या विकसित होने देना है। सर्वे में इस बारे में फैसला लेने की बात करता है, क्योंकि यही देश में एआइ के भविष्य को तय करेंगे। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत पहले के अनुभवों से सीख सकता है।

जनजीवन को बेहतर कर सकता है एआइ

सर्वेक्षण ने कई उदाहरणों से यह साबित करने की कोशिश की है कि किस तरह से एआइ भारत में आम जनजीवन को बेहतर कर सकता है। दक्षिण भारत में, एआइ-सक्षम थर्मल इमेजिंग टूल्स कम संसाधन वाले इलाकों में स्तन कैंसर की शुरुआती जांच को संभव बना रहे हैं। हिमालयी क्षेत्र में, स्वदेशी सेंसर नेटवर्क को मशीन लर्निंग के साथ जोड़कर भूस्खलन की रीयल-टाइम चेतावनी दे रहे हैं। बेंगलुरु में, एआइ-आधारित जल प्रबंधन प्रणालियां पानी की खपत की निगरानी कर रही हैं और रिसाव का पता लगा रही हैं। पिंपरी-चिंचवाड़ में, एआइ कक्षा शिक्षण परिणामों की निगरानी कर रहे हैं, जिससे छात्रों की भागीदारी में सुधार हुआ है।

संक्षिप्त खबरें

सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाए सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : आर्थिक सर्वेक्षण ने गुरुवार को सिफारिश की कि सरकार को सरकारी कंपनी की परिभाषा में संशोधन पर विचार करना चाहिए। सर्वेक्षण में स्वामित्व की न्यूनतम सीमा को वर्तमान 51 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत करने की आवश्यकता बताई गई है। यह इस आधार पर है कि प्रभावी नियंत्रण अक्सर 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भी बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि इस स्तर की स्वामित्व आमतौर पर विशेष प्रस्ताव अधिकारों की अनुमति देती है जो प्रमुख कंपनी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

एमएसएमई के भुगतान में देरी एक बड़ी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र: आर्थिक सर्वेक्षण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के भुगतान में होने वाली देरी को बड़ी चुनौती बताया गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि एमएमएमई का करीब 8.1 लाख करोड़ रुपये बकाया है, जो इनकी वृद्धि को रोक रहा है। सर्वेक्षण में मध्यम उद्यमों और पहली बार लोन लेने वालों को क्रेडिट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कैश-फ्लो-आधारित लेंडिंग सहित इनोवेटिव उपायों की सिफारिश की गई है।

मोबाइल फोन का उत्पादन 9.34 लाख करोड़ तक पहुंचा

नई दिल्ली, प्रेट्र : आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली प्रोत्साहन योजना के तहत 13,759 करोड़ रुपये के निवेश से सितंबर 2025 तक कुल 9.34 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 5.12 लाख करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में हाल के वर्षों में एक संरचनात्मक बदलाव आया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में सातवीं सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली श्रेणी बन गई है। यह योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2025) में भी विकास की गति जारी है और इस दौरान 2.04 लाख करोड़ रुपये का इलेक्ट्रानिक्स निर्यात हो चुका है।

वर्ष 2026 में भी जारी रहेगा रुपये पर दबाव

स्थिति को बेहतर करना है तो ढांचागत स्तर पर आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन पर देना होगा और ध्यान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पिछला साल यानी 2025 भारतीय रुपये के लिए बहुत ही खराब रहा। 2026 में गिरावट का दौर जारी रहने की आशंका है। हालांकि, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का कहना है कि डालर के मुकाबले रुपये के 91-92 के स्तर पर रहना, इसकी क्षमता का और भारत की अर्थव्यवस्था का सही आकलन नहीं है। संसद में गुरुवार को पेश आर्थिक सर्वे ने भारतीय रुपये की हालिया गिरावट पर विस्तार से प्रकाश डाला है। सर्वे का कहना है कि भारत की मजबूत आर्थिक बुनियादी बातें (उच्च विकास दर, नियंत्रित मुद्रास्फीति, कारपोरेट व बैंकों की मजबूत स्थिति, कर्ज देने में लगातार हो रही वृद्धि) बहुत ही अच्छा माहौल बना रही हैं, इसके बावजूद रुपया दबाव में रह सकता है। अगर स्थिति को बेहतर करना है तो ढांचागत स्तर पर आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन पर और ध्यान देना होगा।

सर्वे में साफ तौर पर कहा गया है कि रुपये की मौजूदा कीमत भारत की आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करती है और यह 'अंडरवैल्यू' (कीमत इसकी क्षमता से कम) है। रुपये की कमजोरी के पीछे मुख्य कारण वस्तुओं में लगातार व्यापार घाटे को बताया गया है जबकि सेवाओं और रेमिटेंस (विदेशों में रहने वाले भारतीयों की तरफ से भेजी जाने वाली राशि) से आने वाली मुद्रा इस घाटे को पूरी तरह भर नहीं पाती हैं। भारत को संतुलन भुगतान बनाए रखने के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह पर निर्भर रहना पड़ता है और जब भी इस प्रवाह में कमी होती है जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफआइआइ) के बाहर जाने से तो भुगतान संतुलन प्रभावित होता है। इसका असर रुपये की कीमत पर होता है। अभी वैश्विक अनिश्चितता, अमेरिकी टैरिफ और आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस (एआइ) का भी खतरा है और इससे भारत में आने वाले निवेश पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है, जिससे रुपये पर दबाव आगे भी रह सकता है। सर्वे ने इन वजहों को वैश्विक कारक बताया है, जो रुपये को शिकार बनाती हैं।

सर्वे की खास बातें

- रुपये की मौजूदा कीमत भारत की आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करती है और यह 'अंडरवैल्यू है
- डालर के मुकाबले रुपये के 91-92 के स्तर पर रहना, इसकी क्षमता और भारतीय आर्थिकी का सही आकलन नहीं
- कमजोर रुपये से फिलहाल नुकसान नहीं, क्योंकि यह अमेरिकी संरक्षणवाद और उच्च टैरिफ के प्रभाव को कर रहा कम

इन वजहों से रहेगा दबाव

- वैश्विक अस्थिरता से निवेश प्रवाह में रुकावट से रुपये पर सबसे ज्यादा खतरा
- निवेशकों की अनिच्छा को दूर करने के लिए हरसंभव कदम उठाने का सुझाव

हाल ही में रुपये ने छुआ 92 का नया निचला स्तर

सर्वे के मुताबिक एक अप्रैल, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक रुपये में डालर के मुकाबले लगभग 6.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वैसे तो यह गिरावट अन्य विकासशील देशों की मुद्राओं के मुकाबले सबसे तेज गिरावट रही, लेकिन सर्वे ने इसे व्यवस्थित माना है। हाल ही में रुपये ने 92 के स्तर को छूकर नया निचला स्तर बनाया। इसके बावजूद सर्वे मानता है कि कमजोर रुपये से फिलहाल नुकसान नहीं, बल्कि फायदा हो रहा है, क्योंकि यह अमेरिकी संरक्षणवाद और उच्च टैरिफ के प्रभाव को कुछ हद तक कम करता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कम कीमतों का भी योगदान है।

पूंजी प्रवाह में बाधा से भारतीय रुपये पर रहेगा दबाव

सर्वे ने 2026 के तीन वैश्विक जोखिम परिदृश्यों का जिक्र किया है, जिसमें पूंजी प्रवाह में बाधा प्रमुख है। अगर भारत में आने वाले निवेश की रफ्तार कम होती है तो रुपये पर दबाव बढ़ेगा। भारत में निवेश करने की इच्छा में आ रही गिरावट को गंभीरता से लेने का सुझाव दिया गया है। यह कहता है कि अल्पावधि में उतार-चढ़ाव सामान्य है, लेकिन मध्यम से दीर्घावधि में रुपये की कीमत उत्पादकता, उच्च-मूल्य वाले निर्यात, ग्लोबल वैल्यू चेन में गहरी भागीदारी और स्थिर नीतिगत वातावरण से निर्देशित होंगे। सर्वे ने अंत में भारत की मजबूत बुनियादी आधार को दोहराया है और कहा है कि रुपये की कमजोरी फिलहाल निर्यातकों के लिए सहायक साबित हो रही है, लेकिन लंबे समय में संरचनात्मक सुधारों से ही मुद्रा की स्थिरता सुनिश्चित होगी।

40% गिग वर्कर की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम

नई दिल्ली, प्रेट्र: आर्थिक सर्वे 2025-26 में बताया गया है कि भारत में लगभग 40 प्रतिशत गिग वर्कर प्रत्येक महीने 15,000 रुपये से कम कमाते हैं। सर्वे में गिग इकोनमी में बड़े नीतिगत बदलावों की भी बात की गई है। इसमें 'हर घंटे या हर काम के लिए कम से कम कमाई' तय करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें इंतजार के समय का मुआवजा भी शामिल है, जिससे सही मजदूरी पक्की हो सके और नियमित व गिग रोजगार के बीच खर्च का फर्क कम हो सके।

सर्वे में कहा गया है कि गिग-इकोनमी पालिसी का मकसद शर्तों को बदलना होना चाहिए ताकि वर्कर कमजोर डिमांड और कौशल की कमी के चलते गिग में मजबूर होने के बजाय किसी अन्य रोजगार का चयन कर सकें। गिग इकोनमी तेजी से बढ़ रही है, फिर भी इनकम में उतार-चढ़ाव एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इससे कर्ज मिलने में रुकावटें आ रही हैं। गिग वर्कर के लिए वित्तीय समावेशन के भी बहुत उपाय नहीं किए गए हैं। सर्वे में कहा गया, 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) और मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी तकनीक के चलते स्किल की कमी और नौकरी जाने का डर वर्कर की कमजोरी को और बढ़ा देता है। वर्कर और काम खोजने के लिए, जरूरी प्लेटफार्म गिग मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं।' गिग इकोनमी पालिसी को प्रतिस्पर्धा नियमों, डेटा एक्सेस और एल्गोरिदमिक पारदर्शिता के जरिये इन मुद्दों का हल खोजना चाहिए। सर्वे में कहा गया, 'पालिसी नियमित और गिग वर्क के बीच कीमत के अंतर को कम कर सकती है।' भारत की गिग इकोनमी में एक ढांचागत बदलाव आया है। वित्त वर्ष 2021 में इसमें 77 लाख लोग कार्यरत थे जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 1.2 करोड़ हो गई। अब यह भारत में कुल कार्यबल का दो प्रतिशत से ज्यादा है।

- सर्वे में गिग इकोनमी में बड़े नीतिगत बदलावों की सिफारिश
- कुल कार्यबल में गिग वर्कर्स की दो प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी

सबसे निचले तबके के 10% लोगों में खपत बढ़ी, गरीबी घटी

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों ने देश में गरीबी को काफी हद तक कम किया और आय वितरण में सुधार हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, समाज के सबसे निचले तबके के 5-10 प्रतिशत लोगों की खपत में बढ़ोतरी हुई है और इनमें गरीबी घटी है।

सर्वेक्षण ने सब्सिडी, पेंशन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च के सकारात्मक परिणामों को उजागर किया है, जिसने कमजोर वर्गों को अभाव से बाहर निकाला है। यह नवीनतम घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24 में परिलक्षित होता है, जो खपत असमानता में कमी और सबसे वंचित समूहों के लिए महत्वपूर्ण लाभ दिखाता है। 2022-23 और 2023-24 के बीच औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) में सबसे बड़ी वृद्धि सबसे निचले 5-10 प्रतिशत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखी गई, जो सरकार की नीतियों के प्रभाव को उजागर करती है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकारी पहलें कमजोर वर्गों को अभाव के चक्र से बाहर निकालने में सकारात्मक परिणाम दे रही हैं, जैसा कि गरीबी में कमी के विभिन्न उपायों में परिलक्षित होता है।

- कल्याणकारी कार्यक्रमों से गरीबी घटाने में मिल रही मदद
- ग्रामीण और शहरों दोनों क्षेत्रों में दिख रहा योजनाओं का असर

ई-वे बिल प्रणाली में किया जाए सुधार

नई दिल्ली, प्रेट्र: आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि जीएसटी सुधारों की अगली कड़ी में ई-वे बिल प्रणाली को केवल प्रवर्तन और नियंत्रण के माध्यम के बजाय सुगम लाजिस्टिक सहायक के रूप में फिर से तैयार किया जा सकता है।

समीक्षा में इलेक्ट्रानिक मोहर और इलेक्ट्रानिक लाकिंग प्रणाली के व्यापक उपयोग का सुझाव दिया गया है। इन्हें ई-वे बिल और ऑटो निगरानी तकनीकों के साथ जोड़ा जा सकता है। इससे सड़क पर नियमित रोक-टोक के बिना माल की सुरक्षित और शुरू से अंत तक निगरानी की जा सकेगी। जमीनी स्तर पर प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली राज्य सरकारें इस बदलाव के केंद्र में होंगी। उन्हें जोखिम आधारित प्रणाली की चेतावनी का अनुसरण करना होगा और विवेकाधीन जांच को सीमित करना होगा।

विकसित भारत कोई नंबर नहीं, सतत प्रक्रिया : सीईए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सात प्रतिशत विकास दर के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि विकसित भारत कोई नंबर नहीं है। विकसित होने की एक सतत प्रक्रिया है। अगर आगे की पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर जिंदगी जीने लगती है और तो इसे ही विकसित भारत कहा जा सकता है।

आर्थिक विशेषज्ञ यह मानते रहे हैं कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हर साल कम से कम आठ प्रतिशत की दर हासिल करनी होगी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में विकास दर 7.4 प्रतिशत तो आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में अधिकतम विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना है। एचडीएफसी की प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता कहती है, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें हर साल 7.5-8 प्रतिशत की दर से विकास करना होगा।

नागेश्वरन ने कहा कि सतत विकास को हासिल करने के लिए लंबे समय तक केंद्र और राज्य को अपने वित्तीय मजबूती रखने की नीति को जारी रखना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने वाली टीम के मुखिया नागेश्वरन ने राज्यों की बढ़ती राजकोषीय घाटे पर चिंता जताई, क्योंकि इससे राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। राज्यों की तरफ से वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करने पर देश की उधार लेने की लागत प्रभावित होती है। राज्यों की वित्तीय सेहत अच्छी नहीं रहने पर पूरे देश की उधार लेने की रेटिंग खराब होती है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि परिवार को नकदी देने से उन्हें मदद तो मिलती है, लेकिन उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए निवेश का असर अपेक्षाकृत अधिक होता है। राज्यों को इस प्रकार के खर्च में सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि छोटी अवधि के लाभ के कारण मध्य व लंबे समय की समृद्धि न प्रभावित हो। नागेश्वर ने कहा कि भू-राजनीतिक कारणों से डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में ह्रास हो रहा है, लेकिन हमारा आर्थिक ढांचा मजबूत है और इस प्रकार की विकास दर से वैश्विक स्तर पर निवेशकों में धारण बदलेगी। आर्थिक विकास में केंद्र के साथ राज्यों की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है।

नई दिल्ली में गुरुवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से जुड़ी जानकारी देते सीईए वी. अनंत नागेश्वरन ● प्रेट्र

- अगर नई पीढ़ी पिछली से बेहतर जिंदगी जीने लगती है तो यही विकसित भारत
- राज्यों की ओर से वित्तीय अनुशासन का पालन न करने पर जताई चिंता

एक नजर में

केनरा बैंक को 5,254 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

नई दिल्ली: केनरा बैंक ने गुरुवार को बताया कि अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 25 प्रतिशत बढ़कर 5,254 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वर्ष समान अवधि में बैंक को 4,214 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बीती तिमाही में बैंक की ब्याज से शुद्ध आय 1.13 प्रतिशत बढ़कर 9,252 करोड़ रुपये, जबकि वैश्विक अग्रिम में 13.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। (वि.)

तीसरी तिमाही में टाटा मोटर्स का लाभ 48% घटा

नई दिल्ली : टाटा मोटर्स ने गुरुवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही उसका शुद्ध लाभ 48 प्रतिशत घटकर 705 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का कहना है कि नए लेबर कोड लागू करने पर 603 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है जिससे बीती तिमाही में शुद्ध लाभ घटा है। अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही में कंपनी को 1,355 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। (प्रेट्र)

चांदी चार लाख के पार, सोना भी नए शिखर पर

नई दिल्ली, प्रेट्र: वैश्विक बाजार में तेजी और सुरक्षित निवेशक के लिए मजबूत मांग को देखते हुए गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमतें चार लाख रुपये प्रति किलो के स्तर को पार कर गईं। वहीं सोना 1.83 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चस्तर पर पहुंच गया। लगातार चौथे कारोबारी सत्र में चांदी ने बढ़त जारी रखी और 19,500 रुपये या 5.06 प्रतिशत बढ़कर रिकार्ड 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बुधवार को यह सफेद धातु 3,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

सोना भी 12,000 रुपये या 7.02 प्रतिशत बढ़कर 1,83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। पिछला बंद भाव 1,71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। कारोबारियों ने कहा कि सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल काफी हद तक वैश्विक रुझान के हिसाब से था, जिसके चलते सोना और चांदी नए उच्चस्तर पर पहुंच गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 177.14 डालर या 3.3 प्रतिशत बढ़कर 5,595.02 डालर प्रति औंस के नए ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। हाजिर सोना 3.59 डालर या 3.07 प्रतिशत बढ़कर 120.45 प्रति औंस के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। कैलेंडर वर्ष 2026 की बात करें तो अब तक (1-29 जनवरी) चांदी के मूल्य में 1,65,500 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हो चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को चांदी का मूल्य 2.39 लाख रुपये प्रति किलोग्राम था, जो अब 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इसी प्रकार, सोने के मूल्य में जनवरी में अब तक 45,300 रुपये प्रति दस ग्राम बढ़ चुका है। 31 दिसंबर 2025 को दिल्ली में सोने का मूल्य 1,37,700 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो अब 1,83,000 रुपये प्रति दस ग्राम हो चुका है। कैलेंडर वर्ष 2025 में चांदी 1,48,500 रुपये किलो या 164 प्रतिशत और सोना 58,310 रुपये प्रति दस ग्राम या 73.45 प्रतिशत बढ़ा था।

19,500 रुपये बढ़कर 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम हुई सफेद धातु

12,000 रुपये बढ़कर 1,83,000 रुपये के नए रिकार्ड पर पहुंचा सोना

वायदा कारोबार में भी चांदी चार लाख रुपये के पार

पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक बाजार में रिकार्ड तोड़ तेजी के चलते गुरुवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकार्ड स्तर को पार कर गई जबकि सोने का भाव 1.8 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर चांदी के मार्च में आपूर्ति वाले अनुबंधों का वायदा भाव 24,434 रुपये 6.34% बढ़कर 4,09,800 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्रों में यह सफेद धातु 21 जनवरी को रिकार्ड किए गए 3,18,492 रुपये प्रति किलोग्राम से 91,308 रुपये या लगभग 29 प्रतिशत बढ़ चुकी है। यह सफेद धातु सिर्फ आठ कारोबारी दिनों में तीन लाख से चार लाख रुपये हो गई। इस साल, इस सफेद धातु ने 74 प्रतिशत का जबरदस्त रिटर्न दिया है। सोने के अप्रैल में आपूर्ति वाले अनुबंधों का वायदा भाव 15,943 रुपये या नौ प्रतिशत बढ़कर 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकार्ड पर पहुंच गया है।

2025 में भारत में सोने की मांग 11% घटी

मुंबई, प्रेट्र : कीमतों के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने और उपभोक्ताओं के खरीद व्यवहार में बदलाव के कारण वर्ष 2025 में भारत की सोने की मांग में 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) की '2025 की स्वर्ण मांग के रुझान' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सोने की कुल मांग 2025 में गिरकर 710.9 टन रह गई, जो 2024 में 802.8 टन थी। परिषद का अनुमान है कि 2026 में देश में सोने की मांग 600 से 700 टन के बीच रह सकती है। हालांकि, कीमतों में भारी उछाल के कारण मूल्य के संदर्भ में सोने की मांग 30 प्रतिशत बढ़कर 7,51,490 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष यह 5,75,930 करोड़ रुपये थी।

डब्ल्यूजीसी के मुताबिक, 2025 में दुनियाभर सोने की कुल मांग 5,002 टन के अब तक के सबसे उच्चस्तर पर पहुंच गई। पिछले साल यानी 2024 में यह आंकड़ा 4,961.9 टन था। निवेश मांग 2024 के 1,185.40 टन की तुलना में बढ़कर 2025 में 2,175.3 टन हो गई।

आर्थिक सर्वेक्षण से शेयर बाजारों को मिला सहारा

मुंबई, प्रेट्र: सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.8-7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताए जाने घरेलू शेयर बाजारों पर सकारात्मक असर पड़ा और दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए।

बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 636.74 अंक गिरकर 81,707.94 के निचले स्तर पर पहुंचा था। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद इसमें तेजी आई और यह निचले स्तर से 980 अंक तक बढ़कर 82,689.96 के उच्च स्तर तक पहुंचा। अंत में यह 221 अंक बढ़कर 82,566.37 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 76.15 अंक की तेजी के साथ 25,418.90 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में यह 182.95 अंकों गिरकर 25,159.80 के निचले स्तर तक पहुंचा था। सेंसेक्स टाटा स्टील में 4.41 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि की गई। इसके अलावा, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक, एटरनल, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स और आइसीआइसीआइ बैंक के शेयर भी बढ़कर बंद हुए।

- निचले स्तर से 980 अंक से ज्यादा बढ़ा बीएसई सूचकांक
- अंत में 221 अंक बढ़कर 82,566 पर बंद हुआ सेंसेक्स

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

चिंतन

शैक्षिण संस्थानों को जातीय भेदभाव से दूर रखा जाए

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों पर रोक लगाना केवल एक कानूनी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था के मूल उद्देश्यों पर पुनर्विचार का भी संकेत है। शीर्ष अदालत ने सख्त नसीहत देते हुए साफ शब्दों में कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को जातीय और भाषाई भेदभाव से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, न कि उसे वर्गों में बांटना। यूजीसी द्वारा 13 जनवरी को अधिसूचित नए नियमों का उद्देश्य कथित तौर पर भेदभाव की शिकायतों से निपटना था, लेकिन देशभर में इसके विरोध ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इन प्रावधानों से समस्या सुलझेगी या और जटिल होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या शामिल थे, ने माना कि नियमों के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने अगले आदेश तक इन पर रोक लगा दी और 2012 के पुराने नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया। अदालत की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी जातीय आधार पर समितियों के गठन को लेकर आई। कोर्ट ने चेताया कि शैक्षणिक संस्थानों में जातीय आधारित कमेटियां बनाना खतरनाक असर डाल सकता है। शिक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए, जहां छात्र अपनी पहचान के बजाय अपनी योग्यता और परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ें। यदि संस्थानों के भीतर ही जातीय पहचान को औपचारिक रूप से रेखांकित किया जाएगा तो यह अनजाने में ही विभाजन और प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं जिनमें मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान शामिल हैं, ने नए नियमों को जनरल कैटेगरी के छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण बताया। यह तर्क अपने आप में संवेदनशील है, क्योंकि भारत की आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय की बहस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि शिक्षा का अधिकार सबका समान है और सवर्ण तथा गैर-सवर्ण जैसी श्रेणियों में छात्रों को बांटना शिक्षा के मूल भाव के खिलाफ है। अदालत ने भाषाई भेदभाव का मुद्दा भी उठाया, जो अक्सर शिक्षा व्यवस्था में अनदेखा रह जाता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा के आधार पर भेदभाव की संभावना वास्तविक है। यदि शैक्षणिक संस्थानों में भाषा ही पहचान और प्रभुत्व का औजार बना दिया जाए, तो यह समान अवसर की अवधारणा को कमजोर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक-दूसरे पर हावी होने की रणनीति किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक चेतना का विस्तार करना है, न कि समाज में पहले से मौजूद खाइयों को और गहरा करना। हालांकि, यह भी सच है कि जातीय भेदभाव की शिकायतें वास्तविक हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह नहीं है कि भेदभाव से कैसे निपटा जाए। यदि नियम अस्पष्ट होंगे या अत्यधिक पहचान-आधारित ढांचे पर टिके होंगे, तो वे समाधान से ज्यादा समस्या पैदा कर सकते हैं। इसी संतुलन की तलाश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नया ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप याद दिलाता है कि शिक्षा नीति केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि समाज के भविष्य की दिशा तय करने वाला उपकरण है। ऐसे में इसका हर शब्द, हर प्रावधान, अत्यंत सोच-समझकर तय किया जाना चाहिए।

उम्मीदों व यथार्थ के बीच संतुलन जरूरी

बजट
महेन्द्र तिवारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार नौवां आम बजट पेश करने जा रही हैं। यह केवल एक औपचारिक आर्थिक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि उस दौर का आईना होगा जिसमें आम आदमी महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य और भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच संतुलन खोज रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने अपेक्षाकृत स्थिरता दिखाई है, लेकिन इसका सीधा लाभ हर घर तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। मध्यम वर्ग, जो कर व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, आज सबसे अधिक अपेक्षाएं लगाए बैठा है। यदि इसमें उम्मीदों और यथार्थ के बीच संतुलन बना, तो यह केवल नौवां बजट नहीं, बल्कि विश्वास का दस्तावेज बन सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार नौवां आम बजट पेश करने जा रही हैं। यह केवल एक औपचारिक आर्थिक दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि उस दौर का आईना होगा जिसमें आम आदमी महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य और भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच संतुलन खोज रहा है। यह अवसर ऐतिहासिक भी है, क्योंकि वह मोरार जी देसाई के दस बजटों के रिकॉर्ड के करीब पहुंच रही हैं। ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है, विकसित देशों की मौद्रिक नीतियों का दबाव है, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती दिख रही है और युद्धों के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित है, भारत का यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि भरोसे का दस्तावेज होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने अपेक्षाकृत स्थिरता दिखाई है, लेकिन इसका सीधा लाभ हर घर तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया है। मध्यम वर्ग, जो कर व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, आज सबसे अधिक अपेक्षाएं लगाए बैठा है। यह वर्ग केवल कर में छूट नहीं चाहता, बल्कि जीवन की बुनियादी जरूरतों में राहत चाहता है। वेतनभोगी परिवारों के लिए बढ़ती किस्तें, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और मकान का सपना लगातार महंगा होता जा रहा है।

ऐसे में उम्मीद है कि कर कटौती की सीमा बढ़े, ताकि हाथ में बचने वाली आय से रोजमर्रा का जीवन थोड़ा आसान हो सके। केवल आयकर की दरों में बदलाव ही नहीं, बल्कि मकान ऋण पर मिलने वाली ब्याज छूट को बढ़ाने से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिल सकता है। आज शहरों में एक साधारण घर भी मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर होता जा रहा है, ऐसे में सस्ते आवास को प्रोत्साहन देना सामाजिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी की चिंता और भी गहरी है। बीमारी आज केवल शारीरिक संकट नहीं, बल्कि आर्थिक आपदा बन जाती है। निजी अस्पतालों की बढ़ती लागत और बीमा प्रीमियम ने मध्यम और निम्न आय वर्ग को डरा रखा है। यदि स्वास्थ्य बीमा पर कर में अधिक छूट मिले, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान हों और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का दायरा बढ़े तो यह बजट वास्तव में जीवन रक्षक साबित हो सकता है। आयुष आधारित उपचार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मजबूती और दवाओं की सस्ती उपलब्धता जैसे कदम आम परिवार के लिए राहत की सांस होंगे। ग्रामीण भारत और किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव हैं। आधी से अधिक आबादी आज भी खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है, लेकिन आय की अनिश्चितता और बढ़ती लागत ने किसान को असुरक्षित बना दिया है। किसानों को मिलने वाली प्रत्यक्ष सहायता राशि में वृद्धि, सस्ते ऋण की सीमा बढ़ाना और फसल बीमा को अधिक पारदर्शी तथा त्वरित बनाना समय की मांग है। सिंचाई परियोजनाओं में बड़े निवेश से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि गांवों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जब गांव मजबूत होंगे, तभी शहरों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा और सामाजिक संतुलन बना रहेगा। लघु और मध्यम उद्योगों की भूमिका भी इस बजट में

केंद्र में रहनी चाहिए। ये उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। आसान ऋण, सरल कर व्यवस्था और तकनीकी सहायता से ये इकाइयां आत्मनिर्भर बन सकती हैं। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को प्रोत्साहन देने से सामाजिक बदलाव भी आएगा।

गांव और कस्बों में यदि छोटे उद्योग फलते-फूलते हैं, तो पलायन रुकेगा और स्थानीय विकास को नई दिशा मिलेगी। महिलाओं और युवा किसी भी देश के भविष्य की असली पूंजी होते हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति की भी शर्त है। स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और कौशल प्रशिक्षण योजनाओं को यदि मजबूत समर्थन मिले तो महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की सहभागी बनेंगी। युवाओं के लिए रोजगार सृजन सबसे बड़ी चुनौती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी न मिलना आज लाखों युवाओं की हकीकत है। यदि बजट में प्रशिक्षु कार्यक्रम, नई नौकरियों के लिए प्रोत्साहन और नवाचार आधारित उद्यमों को सहायता मिले तो यह निराशा उम्मीद में बदल सकती है। शिक्षा पर निवेश लंबे समय का निवेश होता है। विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा तक गुणवत्ता सुधारना आवश्यक है। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को समाज की मुख्यधारा में लाने से युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा सकता है। डिजिटल माध्यमों से दूरदराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने से ग्रामीण और शहरी बच्चों के बीच की खाई कम होगी। जब शिक्षा सशक्त होगी, तभी जनसंख्या का लाभ वास्तविक आर्थिक शक्ति में बदलेगा। स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे पर खर्च किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अस्पताल, डॉक्टर, जांच सुविधाएं और चिकित्सा उपकरण यदि सुलभ होंगे तो जनता का भरोसा मजबूत होगा।

इसी तरह सड़क, रेल, हवाई संपर्क और ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश से न केवल रोजगार पैदा होते हैं, बल्कि पूरे देश की उत्पादकता बढ़ती है। स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल योजनाओं से आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य तैयार किया जा सकता है। जब घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पहुंचेगी। इससे बिजली का खर्च घटेगा और प्रदूषण भी कम होगा। निर्मला सीतारमण के पिछले बजटों में नीति की निरंतरता दिखी है। बड़े सुधारों के साथ-साथ स्थिरता बनाए रखने की कोशिश रही है। इस बार भी उनसे यही अपेक्षा है कि वे विकास और जनकल्याण के बीच संतुलन साधें। आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब उसका असर आम आदमी की थाली, जेब और भविष्य की सुरक्षा पर दिखे। विदेशी निवेश, निर्यात और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि लाभ केवल चुनिंदा वर्गों तक सीमित न रह जाए। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तभी पूरी होगी, जब गांव का किसान, शहर का मजदूर, मध्यम वर्ग का कर्मचारी, महिला उद्यमी और पढ़ा-लिखा युवा सभी खुद को इस विकास यात्रा का हिस्सा महसूस करें। यह बजट केवल सरकार की मंशा का नहीं, बल्कि देश की दिशा का संकेत देगा। यदि इसमें उम्मीदों और यथार्थ के बीच संतुलन बना, तो यह केवल नौवां बजट नहीं, बल्कि विश्वास का दस्तावेज बन सकता है। आम आदमी आज चमत्कार नहीं, बल्कि ईमानदार कोशिश चाहता है। अगर यह कोशिश दिखाई दी तो 2047 के सपने की राह और भी स्पष्ट हो जाएगी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

दिवस विशेष
डॉ. मोनिका शर्मा

स्वदेशी सामानों के उपयोग के समर्थक थे महात्मा गांधी

समाज को सामाजिक-पारिवारिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाने का संदेश देने के साथ ही महात्मा गांधी ने देश की आर्थिक सबलता को भी महत्वपूर्ण माना था। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का भाव उनके विचारों का ही नहीं, व्यवहार का भी हिस्सा रहा। आर्थिक सबलता और आत्मनिर्भरता के इसी लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वदेशी सामानों को अपनाने का मंत्र दिया था। अपने देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का उनका यह विचार आज के दौर में और भी प्रासंगिक लगता है। वस्तुतः 'स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ' का नारा देते हुए गांधी जी रोजगार, स्वावलंबन और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए देश को सशक्त बनाना चाहते थे। गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से समाज के हर वर्ग से विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर देश में बने उत्पादों के उपयोग का आग्रह किया था। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आज स्वदेशी सामानों को अपनाने की इस राह पर चलने का संकल्प और जरूरी हो चला है। विकसित देशों की धमकियों और दबदबे से बाहर आने के लिए देशवासियों का देश में बने सामानों का समर्थन देना बहुत आवश्यक है। सुखद है कि बीते कुछ वर्षों से देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले 'वोकल फॉर लोकल' की मुहिम बल भी पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कई अवसरों पर देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील करते रहे हैं। खासकर त्योहारी मौसम में हर भारतीय से 'मेड इन इंडिया' उत्पादों का उपयोग बढ़ाने का आग्रह रहा है। कुछ समय पहले देशवासियों को लिखे एक खुले पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा था कि 'हर बार जब आप अपने देश के कारीगर, मजदूर और उद्योगों द्वारा बनाए गए सामान खरीदते हैं तो आप न सिर्फ रोजगार को बढ़ावा देते हैं बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका भी सुरक्षित करते हैं। मैं दुकानदारों और व्यापारियों से अपील करता हूं कि वे 'मेड इन इंडिया' सामान ही बेचें और गर्व से कहें- जो खरीदेंगे वो स्वदेशी, जो बेचेंगे वो स्वदेशी। विचारणीय है कि स्वदेशी चीजों को अपनाना युवाओं का पलायन रोकने से लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने तक, कई पक्षों से गहराई से जुड़ा है। यह हर तरह से भारत की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाला भाव और झुकाव है। ज्ञात हो कि महिलाओं की एक बड़ी आबादी स्वदेशी उत्पाद बनाने वाले उपक्रमों से जुड़ी है। रोजगार हो या स्वरोजगार, देशी सामानों के उत्पादन से महिलाओं की बड़ी आबादी जुड़ी है। विशेषकर त्योहार मौसम में महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, सजावटी सामग्री और खाद्य पदार्थों की बिक्री सीधे-सीधे महिलाओं को फायदा पहुंचाती है। ध्यातव्य है कि हर वर्ष त्योहारों की श्रृंखला का समय देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में यह रेखांकित करने योग्य है कि भारत की बेहतरी से जुड़े बदलाव के मोर्चे पर अब आमजन भी डटे दिखते हैं। अपने देश को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी सामानों की खरीद को प्राथमिकता दी जाने लगी है। जनमानस भारत में बनी चीजों को अपनाने के प्रति जागरूक हुआ है। अब त्योहारी मौसम में चीनी सामानों की बिक्री में भारी गिरावट के साथ 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की लोकप्रियता का असर साफ नजर आता है। साल-दर-साल स्थानीय कारीगरों और भारतीय कंपनियों के उत्पादों को खरीदने में लोगों की रुचि बढ़ रही है। विदेशी सामानों के बजाय देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने से स्थानीय लोगों को तो फायदा हुआ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है। ऐसे में भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और अर्थव्यवस्था को बल देने के मोर्चे पर बापू के विचार आज भी प्रासंगिक लगते हैं। निस्संदेह, महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का मंत्र अपनाते हुए वैश्विक पटल पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई जा सकती है। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया सकता है। आर्थिक सुधारों से जुड़ी इस मुहिम को देशवासियों की सरोकारी समझ का साथ मिलना सबसे जरूरी है। यह समझ संस्कृति को सहेजने और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने वाली है। सुखद है कि समय के साथ देश में बनी चीजों को खरीदने और उनके इस्तेमाल को लेकर गर्व का भाव भी आ रहा है। स्वदेशी सामानों को प्राथमिकता देकर हर भारतीय देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकता है। घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने और विदेशी आयात पर निर्भरता घटाने में हर भारतवासी एक अहम भूमिका निभा सकता है। जरूरी है कि गांधी द्वारा देखे गए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हर नागरिक अपने दायित्वबोध को समझे।

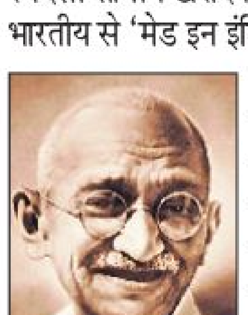

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

निरंतर रूप से निखारती है आत्म-प्रतिस्पर्धा

संकलित
दर्शन

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अनेक छोटे-बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। समाज का अंग होते हुए, समाज में अपनी पहचान बनाना भी प्रत्येक व्यक्ति का एक उद्देश्य जैसा ही प्रतीत होता है। इन उद्देश्यों, लक्ष्यों व उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए चल रहे अनवरत प्रयत्नों के फलस्वरूप एक सामाजिक प्रक्रिया जन्म लेती है। इस सामाजिक प्रक्रिया का नाम है-प्रतिस्पर्धा। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो बेहतर प्रदर्शन करने की तीव्र लालसा। यह लालसा एक अबोध शिशु से लेकर एक वृद्ध तक सभी में विद्यमान रहती है। वस्तुतः जब आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होती, तो प्रतिस्पर्धा स्वतः ही जन्म ले लेती है। प्रतिस्पर्धा में कदाचित विरोध व ईर्ष्या की भावनाएं भी अंतर्निहित होती हैं, किंतु ऐसी प्रतिस्पर्धा स्वस्थ नहीं कही जाती। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वास्तव में उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रतिस्पर्धा की यही विशेषता इसे संघर्ष से अलग करती है। एक अन्य विशेष बात यह है कि प्रतिस्पर्धा किसी तंत्र विशेष तक ही सीमित रहती है। एक विशेष तरह की प्रतिस्पर्धा एक विशेष तंत्र में ही दृष्टिगोचर होती है। किसी व्यक्ति के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा केवल तभी तक रहती है, जब तक आप उसके साथ किसी तंत्र को साझा करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा वह तंत्र छोड़ते ही प्रतिस्पर्धा स्वतः समाप्त हो जाती है। यह आवश्यक नहीं कि प्रतिस्पर्धा सदैव दूसरे व्यक्ति के साथ ही हो। विवेकशील या विद्वान व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा प्रायः स्वयं से होती है।

शिव जी के अंशावतार हैं हनुमान जी

संकलित
प्रेरणा

शिव जी के 19 अवतारों में से एक अवतार है हनुमान। इसे शिव जी का अंशावतार माना जाता है। त्रेता युग में जब रावण का आतंक बढ़ गया, तब विष्णु जी राम अवतार लेने वाले थे। उस समय सभी देवताओं ने श्रीराम की सेवा और मदद करने के लिए अलग-अलग अवतार लिए थे। शिव जी ने श्रीराम के परमभक्त हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। जब श्रीराम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनका यज्ञ घोड़ा घूमते-घूमते देवपुर नगर पहुंचा। उस नगर के राजा थे वीरमणि। वीरमणि शिव भक्त थे। राजा के पुत्र रुक्मांगद ने यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया था। जब ये बात जब श्रीराम के भाई शत्रुघ्न को मालूम हुई तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण कर दिया। शत्रुघ्न और वीरमणि की सेना का युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी भी वीरमणि की सेना खत्म करने लगे। राजा की हार होती देखकर शिव जी राजा की ओर से युद्ध करने लगे। युद्ध में जब शिव जी और हनुमान जी का सामना हुआ तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप तो राम भक्त हैं। फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं। शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है इसलिए मुझे राजा की ओर से युद्ध करना पड़ रहा है, वह मेरा प्रिय भक्त है। शिव जी और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ, लेकिन जब शिव जी पराजित नहीं हुए, तो उन्होंने श्रीराम का स्मरण किया। जब श्रीराम युद्ध में पहुंचे तो शिव जी राजा वीरमणि के साथ श्रीराम की शरण में चले गए। इस तरह ये युद्ध शांत हो गया।

झांकी

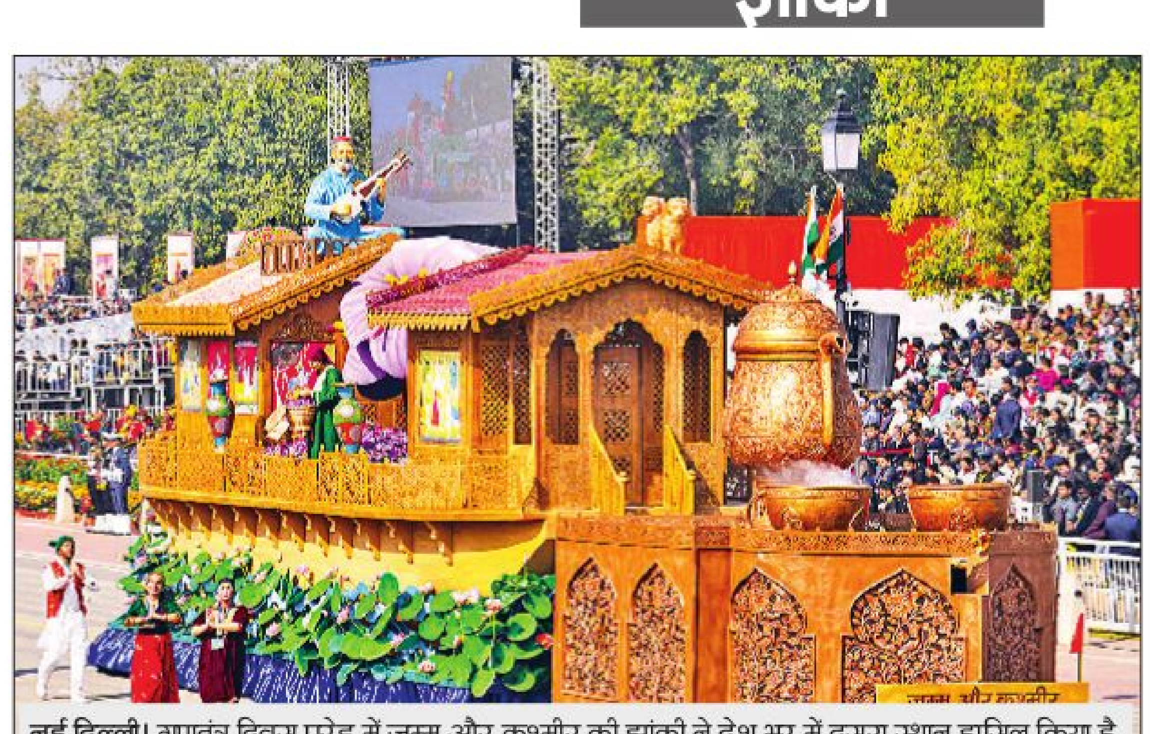

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू और कश्मीर की झांकी ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें इस क्षेत्र की सदियों पुरानी कला, हस्तशिल्प और लोक परंपराओं का चित्रण किया गया।

आज की पाती

समाचार पत्रों का महत्व

हमारे देश में 29 जनवरी को, राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। हमारे देश का पहला समाचार पत्र 29 जनवरी, वर्ष 1780 को प्रकाशित हुआ था। इसे हिक्कीज बंगाल गजट के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य समाचार पत्रों के महत्व और इसके उद्देश्य के प्रति जागरूकता और सम्मान देना भी है। आज न्यूज चैनलों की बाढ़ आ जाने के बावजूद हर कोई अखबार का इंतजार जरूर करता है। नेता हो, अभिनेता या फिर आमजन, हर कोई अखबार में ही खबर पढ़कर संतुष्ट होता है। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाचार पत्रों को अहमियत देता है। यह आमजन की मूलभूत समस्याओं को सत्ताधारियों तक पहुंचाने में भूमिका अदा करते हैं। स्वतंत्रता संग्रामों और आंदोलनों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भी प्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

- कमलेश चतुर्वेदी, दुर्ग

ट्रेंड

स्वदेशी हथियार हाइटेक

ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि हमारे स्वदेशी हथियार कितने एडवांस और हाइटेक हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और रक्षा नवाचार आज हमारी फोर्सेस को और आधुनिक बना रहे हैं, जिससे हमारे युवा साथियों के लिए संभावनाओं का बहुत विस्तार हुआ है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कम्प्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन

हर्ष का विषय है कि जोधपुर ने पर्यटन के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 38 लाख से अधिक पर्यटकों के आगमन ने सिद्ध कर दिया है कि जोधपुर अब विश्व का नया 'कम्प्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन' बन चुका है।

- भजनलाल शर्मा, सीएम, राजस्थान

यूजीसी के नियम

सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का फैसला उचित, जबकि देश में, इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता, अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती।

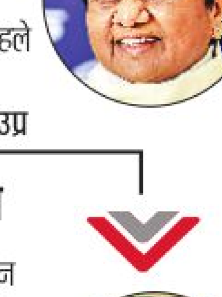

-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

घुसपैठियों को संरक्षण

ममता बनर्जी के पास 15 सालों के शासन के बाद बताने के लिए कोई उपलब्धियां तक नहीं हैं। और तो और, अब वो रोहिंग्याओं व बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने के अपने कुकृत्य पर भी पर्दा डालना चाह रही हैं।

-अनुराग ठाकुर, सांसद, भाजपा

करंट अफेयर

नेपाल के मुस्तांग में भारी बर्फबारी से ट्रेकिंग रोकी गई

नेपाल के मुस्तांग क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण अधिक ऊंचाई वाले पांच मार्गों पर ट्रेकिंग को रोक दिया गया है। प्रशासन ने ट्रेकिंग करने वालों को इन पांच मार्गों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बर्फबारी के बाद, लोकप्रिय पर्यटन स्थल मुस्तांग को मनांग से जोड़ने वाले सरिबुंग दर्रे, मेसो कुन्डो दर्रे, थोरोंग ला दर्रे, मुस्तांग को डोलपा से जोड़ने वाले यक्खरक मार्ग और म्यागदी और मुस्तांग को जोड़ने वाले धौलागिरी ट्रेकिंग मार्ग पर ट्रेकिंग रोक कर दी गई है। हर साल, हजारों लोग मुख्य रूप से मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए बर्फ से ढके पहाड़ों के पास स्थित मुस्तांग जिले में आते हैं। ये रास्ते अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित हैं और बर्फबारी के दौरान बेहद जोखिम भरे माने जाते हैं। मुख्य जिला अधिकारी अजिता शर्मा ने बताया कि तीन पड़ोसी जिलों से मुस्तांग को जोड़ने वाले ट्रेकिंग मार्ग भारी बर्फबारी के कारण बेहद जोखिम भरे हो गए हैं। उन्होंने कहा, 'हमें जानकारी मिली है कि कुछ ट्रेकिंग मार्गों पर चार फीट तक बर्फ जमा हो गई है। अगर पर्यटक फंस जाते हैं तो बचाव अभियान बेहद मुश्किल हो जाएगा।'

ऑफ बीट

मांसपेशियों में व्यायाम के बाद हल्का दर्द क्यों होता है

जब हममें से कई लोग इस खराब मौसम से उबरने के लिए जिम जाते हैं या दौड़ने जाते हैं, तो उन्हें मांसपेशियों में थोड़ा अतिरिक्त दर्द महसूस हो सकता है। ऐसा खास तौर से तब होता है जब कसरत किए कुछ समय हो गया हो। एक आम गलतफहमी यह है कि ऐसा दर्द मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण होता है। हालांकि, शोध से पता चलता है कि लैक्टिक एसिड का इससे कोई लेना-देना नहीं है। सच्चाई कहीं अधिक दिलचस्प है, लेकिन थोड़ी अधिक जटिल भी है। यह लैक्टिक एसिड नहीं है। हम दशकों से जानते हैं कि लैक्टिक एसिड का व्यायाम के बाद मांसपेशियों में होने वाले दर्द से कोई लेना-देना नहीं है। वास्तव में, जैसा कि हम में से एक (रॉबर्ट एंड्रयू रॉबर्ट्स) ने लंबे समय से तर्क दिया है, कोशिकाएं लैक्टेट का उत्पादन करती हैं, लैक्टिक एसिड का नहीं। यह प्रक्रिया वास्तव में मांसपेशियों और रक्तप्रवाह में एसिड के निर्माण का विरोध नहीं करती है। दुर्भाग्य से, लोग अभी भी व्यायाम के संबंध में 'लैक्टिक एसिड' शब्द का उपयोग करते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं तो लैक्टेट उन मांसपेशियों के लिए बड़ी समस्या पैदा नहीं करता है जिनका उपयोग आप करते हैं। आपकी कार्यशील मांसपेशियों को होने वाले अन्य लाभों के कारण संभवतः इसके बिना आपकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी।

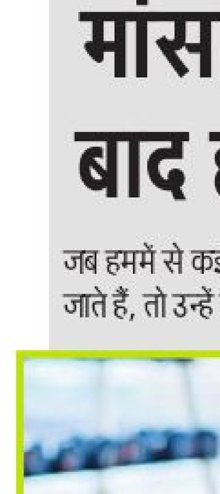

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

एटीएम से निकासी 2025 में घटी प्रति लेनदेन की राशि बढ़ी

■ देश के भीतर उपभोक्ता खर्च के लिए नकद का इस्तेमाल अब भी बढ़ रहा

एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

देश में एटीएम से नकद निकासी में 2025 के दौरान गिरावट देखी गई जबकि प्रति लेनदेन की औसत राशि बढ़ी है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वित्तीय संस्थानों को लॉजिस्टिक समर्थन और एटीएम संचालन से जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की रिपोर्ट 'भारत में उपभोग रुझान 2025' कहती है कि देश के भीतर उपभोक्ता खर्च के लिए नकद का इस्तेमाल अब भी बड़े पैमाने पर हो रहा है।

शिक्षा, आतिथ्य व मनोरंजन में खर्च घटा है

वहीं, शिक्षा, आतिथ्य और मीडिया एवं मनोरंजन में खर्च क्रमशः सात, नौ और 15 प्रतिशत घटा। सीएमएस के मुख्य व्यवसाय अधिकारी अनुष राघवन ने कहा, /"वर्ष 2025 के दौरान जीएसटी सुधार और अन्य वृहद-आर्थिक दबावों के बीच भारतीय उपभोक्ता ने खर्च में कटौती नहीं की, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित किया।/"

उपभोक्ता अधिक सोच समझकर खर्च कर रहा

राघवन ने कहा कि उपभोक्ता अब अधिक सोच-समझकर खर्च कर रहे हैं और अस्थायी विलासिता से मूल्य, सुरक्षा और उपयोगिता की तरफ रुख कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति संगठित खुदरा और उपभोक्ता उत्पादों के क्षेत्र में मजबूत वृद्धि के रूप में नजर आई।

जीएसटी सुधार के बाद खर्च के रुझान में आया बदलाव

कंपनी ने दुकानदारों से संबंधित नकदी प्रबंधन आंकड़ों के आधार पर उपभोक्ता खर्च के रुझान भी साझा किए। सितंबर महीने में जीएसटी सुधारों के बाद खर्च के रुझान में बदलाव देखे गए। बीमा क्षेत्र पर 2025 में उपभोक्ता व्यय 25 प्रतिशत रहा जो सरकार की पहल से 32 प्रतिशत बढ़ा।

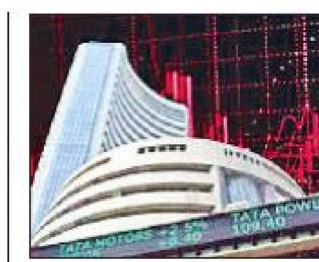

आशावादी आर्थिक समीक्षा से बाजार ने तेजी पकड़ी

■ सेंसेक्स 222 और निफ्टी 76 अंक मजबूत

एजेंसी ▶▶| मुंबई

टाटा स्टील एवं लार्सन एंड टुब्रो में जबर्दस्त खरीदारी और आर्थिक समीक्षा 2025-26 में अगले वित्त वर्ष के लिए 6.8-7.2 प्रतिशत का वृद्धि अनुमान जताए जाने से बृहस्पतिवार को स्थानीय शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स में 222 अंक की बढ़त रही जबकि निफ्टी 76 अंक बढ़ा। बीएसई सूचकांक सेंसेक्स दोपहर के सत्र में बढ़ी लिवाली के दम पर 221.69 अंक बढ़त के साथ 82,566.37 अंक पर बंद हुआ। हालांकि, सुबह के कारोबार में यह 636.74 अंक टूटकर 81,707.94 अंक तक गिर गया था। वहीं निफ्टी 76.15 अंक चढ़कर 25,418.90 अंक पर बंद हुआ। विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक बाजारों में तेजी और विदेशी कोषों के निवेश में बढ़ोतरी ने प्रमुख सूचकांकों को निचले स्तर से उबारने में मदद की। सेंसेक्स की कंपनियों में से टाटा स्टील ने सबसे अधिक 4.41 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एकीकृत लाभ 10 प्रतिशत बढ़कर 71,450 करोड़ रुपये होने का नतीजा देने वाली लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में भी 3.66 प्रतिशत की तेजी रही। इसके अलावा एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, अदाणी पोर्ट्स और आईसीआईसीआई बैंक भी लाभ में रहे।

नई दिल्ली। इण्डिन ऑयल कार्पोरेशन लिए द्वारा आवास एयर से एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए दोनों अधिकारीयह समझौता पत्र हवाई परिवहन के लिए ईंधन की पर्यापत आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किया गया। चित्र में दोनों अधिकारी इसे समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए।

आईटीसी के लाभ में मामूली बढ़ोतरी

नई दिल्ली। विविध क्षेत्रों में कार्यरत प्रमुख कंपनी आईटीसी लिमिटेड का दिसंबर 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ मामूली रूप से बढ़कर 5,018 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसने 5,013 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व बढ़कर 21,707 करोड़ रुपये हो गया।

विश्व स्वर्ण परिषद ने वर्ष 2025 के लिए जारी की रिपोर्ट

कीमतों में आए रिकॉर्ड उछाल से 2025 में भारत में सोने की मांग 11 प्रतिशत घटी

एजेंसी ▶▶| मुंबई

कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने और उपभोक्ताओं के खरीद व्यवहार में बदलाव के कारण वर्ष 2025 में भारत की सोने की मांग में 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

डब्ल्यूजीसी की '2025 की स्वर्ण मांग के रुझान' रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सोने की कुल मांग 2025 में गिरकर 710.9 टन रह गई, जो 2024 में 802.8 टन थी। परिषद का अनुमान है कि 2026 में देश में सोने की मांग 600 से 700 टन के बीच रह सकती है।

सोने की मांग 7,51,490 करोड़ रुपए तक पहुंची

हालांकि, कीमतों में भारी उछाल के कारण मूल्य के संदर्भ में सोने की मांग 30 प्रतिशत बढ़कर 7,51,490 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष यह 5,75,930 करोड़ रुपये थी।

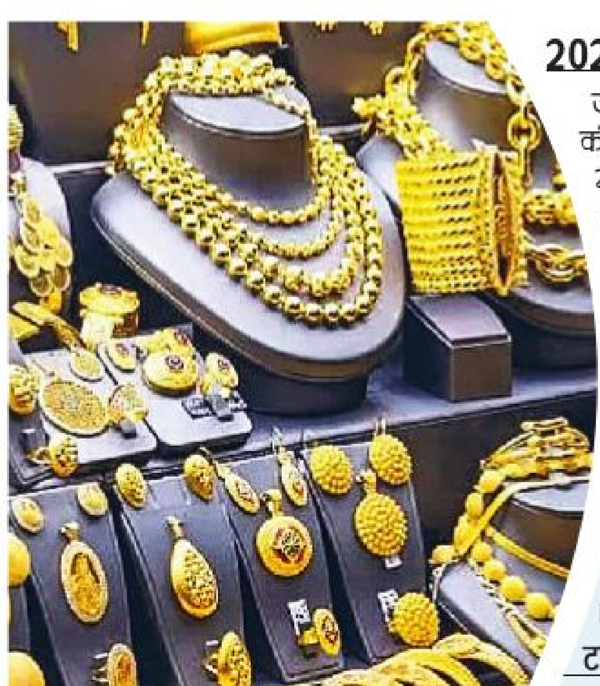

2025 में सोने ने 60 फीसदी रिटर्न दिया

जैन ने कहा, /"शादियों के सीजन के बावजूद ऊंची कीमतों और महंगाई के कारण आभूषणों की बिक्री में 23 प्रतिशत की कमी आई। 2025 में सोने ने 60 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया और 53 बार सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ।/"इसके विपरीत, निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ी है। चौथी तिमाही में निवेश मांग 26 प्रतिशत बढ़कर 96 टन रही, जबकि इसका मूल्य 108 प्रतिशत उछलकर 1,20,700 करोड़ रुपये हो गया।

■ उपभोक्ताओं के खरीद व्यवहार में बदलाव के कारण गिरावट दर्ज

■ भारत में सोने की मांग गिरकर कुल 710 .9 टन रह गई

■ वर्ष 2024 में भारत में सोने की मांग 802,8 टन थी

ऊंची कीमतों के कारण उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव

डब्ल्यूजीसी के क्षेत्रीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ - भारत) सचिन जैन ने बताया, वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में सोने की मांग पर ऊंची कीमतों और उपभोक्ताओं के बदलते व्यवहार का असर स्पष्ट दिखा। मात्रा के आधार पर इस तिमाही में मांग नौ प्रतिशत गिरकर 241.3 टन रही, लेकिन मूल्य के आधार पर यह 49 प्रतिशत बढ़कर करीब 3,03,470 करोड़ रुपये हो गई।'

आभूषणों की मांग 24 फीसदी घटकर 430 टन रही

वर्ष 2025 के दौरान आभूषणों की कुल मांग 24 प्रतिशत घटकर 430.5 टन रही, जो 2024 में 563.4 टन थी। हालांकि, मूल्य के लिहाज से यह 12 प्रतिशत बढ़कर 4,54,390 करोड़ रुपये रही।

सोने की वैश्विक मांग 5,000 टन से अधिक हुई

वैश्विक स्तर पर सोने की मांग 2025 में 5,000 टन से अधिक होकर एक नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। डब्ल्यूजीसी की '2025 की स्वर्ण मांग के रुझान' रिपोर्ट के अनुसार, कुल सोने की मांग 2025 में 5,002 टन के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई, जो पिछले वर्ष 4,961.9 टन थी।

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मांग दो फीसदी बढ़ी

रिपोर्ट में कहा गया कि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से निवेश मांग में तेज उछाल के कारण हुई, जो 2025 में बढ़कर 2,175.3 टन हो गई जबकि यह 2024 में 1,185.4 टन थी। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उपभोक्ता मांग दो प्रतिशत बढ़कर 1,345.3 टन हो गई जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,318.5 टन थी।

रुपये तीन पैसे सुधरकर 91.96 प्रति डॉलर पर बंद

मुंबई। विदेशी कोषों की बिकवाली और वैश्विक बाजारों में जोखिम लेने की धारणा कमजोर होने के बीच, अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 91.96 पर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर के करीब बंद हुआ और निम्नतम स्तर के आसपास जा पहुंचा है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता और विदेशी पूंजी की निकासी के बीच रुपया, अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 92 के अपने अब तक के सबसे निचले दिन के कारोबार के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का भी रुपये पर दबाव पड़ा।

आईपीओ में भारत दुनिया भर में अग्रणी बनकर उभरा

नई दिल्ली। संसद में गुरुवार को पेश की गई आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश के प्राथमिक पूंजी बाजार ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया है। अनिश्चित वैश्विक माहौल के बावजूद भारत आईपीओ के मामले में दुनिया भर में एक अग्रणी देश बनकर उभरा है। समीक्षा में कहा गया कि मजबूत आर्थिक आधार, घरेलू निवेशकों की भारी भागीदारी और सेबी के नियामकीय सुधारों ने बाजारों को मजबूती प्रदान की। दुनिया भर में व्यापारिक बाधाओं, अस्थिर पूंजी प्रवाह और कंपनियों के असमान मुनाफे के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। इसके बावजूद भारतीय बाजार अडिग रहे।

कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन ने बाजार को दिया सहाराः इसके अलावा, घटती मुद्रास्फीति और दूसरी तिमाही में कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन ने भी बाजार को सहारा दिया।

आरबीआई एक लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगी

■ केंद्रीय बैंक डॉलर-रुपया अदला-बदली नीलामी करेगी आयोजित

एजेंसी ▶▶| मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि वह बैंकों में नकदी डालने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा और 10 अरब डॉलर की डॉलर-रुपया अदला-बदली नीलामी आयोजित करेगा। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि वह 29 जनवरी और पांच फरवरी को दो किस्तों (प्रत्येक 50,000 करोड़ रुपये) में कुल 1,00,000 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की ओएमओ (खुले बाजार का परिचालन) खरीद नीलामी आयोजित करेगा। इससे पहले, केंद्रीय बैंक ने घोषणा की थी कि ये नीलामी पांच फरवरी और 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी। एक दूसरे बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह चार फरवरी को तीन साल की अवधि के लिए 10 अरब डॉलर की ''अमेरिकी डॉलर-रुपया खरीद/बिक्री'' स्वैप नीलामी आयोजित करेगा। यह स्वैप रिजर्व बैंक की ओर से एक साधारण विदेशी मुद्रा खरीद/बिक्री के रूप में होगा।

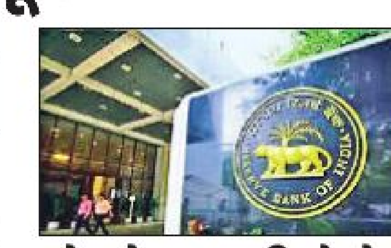

लेन-देन सहमति से होगा

इसके तहत, एक बैंक रिजर्व बैंक को अमेरिकी डॉलर बेचेगा और साथ ही स्वैप अवधि के अंत में उतनी ही राशि के अमेरिकी डॉलर वापस खरीदने के लिए सहमत होगा।

ईरान में अशांति का भारतीय कंपनियों पर खास असर नहीं

मुंबई। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि ईरान में अशांति का भारतीय कंपनियों पर अब तक कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि हालांकि तनाव जारी रहने या बढ़ने पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में तेल रिफाइनिंग, विमानन और कच्चे तेल से जुड़े क्षेत्रों जैसे विशेष रसायन, पेंट, पेट्रोकेमिकल्स और सिंथेटिक वस्त्र उद्योग पर असर पड़ सकता है। क्रिसिल ने कहा, /"ईरान में जारी अशांति का अब तक भारत के वैश्विक व्यापार या घरेलू कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।/" रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, ईरान की वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में चार प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

भारत में 500 की छंटनी करेगी अमेजन

■ कर्मियों को नोटिस मिलने शुरू, बढ़ भी सकती है यह संख्या

बेंगलुरु। वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन अपने भारत स्थित टेक, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस टीमों में कम से कम 500 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहा है। इस मामले से परिचित लोगों का दावा है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है। यह छंटनी अमेजन द्वारा दुनिया भर में किए जा रहे लगभग 16,000 कर्मचारियों के बड़े स्तर के पुनर्गठन का हिस्सा है। घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि इस बार भारत में असर अपेक्षाकृत कम है। करीब 500 लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह संख्या 800 तक जा सकती है। बेंगलुरु जैसे शहरों में कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से छंटनी की सूचना दी जा रही है और आने वाले दिनों में और कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। 28 जनवरी से लोगों को नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं। कंपनी बैचों में कर्मचारियों को सूचित कर रही है। इसके अलावा इस वैश्विक पुनर्गठन के तहत अमेरिका और यूरोप की कुछ उच्च-लागत वाली भूमिकाओं को भारत में स्थानांतरित किया जा रहा है।

महाप्रबंधक उत्तर रेलवे ने भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर-कटरा खंड का निरीक्षण किया; शून्य से नीचे तापमान में कर्मचारियों की सुरक्षा को दी प्राथमिकता

नई दिल्ली। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार वर्मा ने आज श्रीनगर से कटरा रेल खंड का गहन निरीक्षण किया। यह निरीक्षण ऐसे महत्वपूर्ण समय में किया गया है जब कश्मीर घाटी भारी बर्फबारी और शून्य से नीचे (सब-जीरो) तापमान के कारण मौसम की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है। प्रमुख स्टेशनों और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण अपने दौरे के दौरान, महाप्रबंधक ने श्रीनगर, पंपोर, अनंतनाग और काजीगुंड सहित कई प्रमुख स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भीषण सर्दी के बावजूद यात्रियों को असुविधा न हो। श्री वर्मा ने विभिन्न सुरंगों और पुलों पर चल रहे रखरखाव और निर्माण कार्यों की समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली दक्षिण द्वारा स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन

नई दिल्ली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली दक्षिण द्वारा हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 27.01.2026 को अटल आदर्श विद्यालय, नौरोजी नगर, दिल्ली 110029 में भाषण प्रतियोगिता एवं राजभाषा क्विज, दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसमें **VII** से **IX** कक्षा के 60 विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की। दोनों प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए गए। भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। प्राचार्य एवं स्कूल स्टाफ सदस्यों को यूनियन बैंक की ओर से मोमेंटो भी प्रदान किए गए। प्रतियोगिता के आरंभ में अंचल कार्यालय से श्री सत्येंद्र कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा विद्यार्थियों को विश्व हिन्दी दिवस के विषय में जानकारी दी गई।

उत्तर रेलवे

इलेक्ट्रॉनिक निविदा ई प्रणाली के अन्तर्गत मदों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली–110001 द्वारा इच्छुक फर्मों से निम्नलिखित मदों के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र0 सं0	निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
01	82261035	सेकुकिनुमाब इंजेक्शन 150mg	341	18–02–2026

निविदा शर्तें – 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानी www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

टेंडर नोटिस सं. टेबलेट/इंजेक्शन और दवाएं

दिनांकः–29.01.2026 325/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

इलेक्ट्रॉनिक निविदा ई–प्रणाली के अंतर्गत मदों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य सामग्री प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, नई दिल्लो –110001 द्वारा इच्छुक फर्मों से निम्नलिखित मदों के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	टेंडर सं.	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
1.	82261026	इंजेक्शन पर्टुजुमैब 420 मि.ग्रा.	225 नग	24.02.2026
2.	82261029	इंजेक्शन सेटक्सिमैब 500 मि.ग्रा.	200 नग	20.02.2026
3.	82269943	इंजेक्शन TDM-1 (एडो–ट्रास्टुजुमैब एम्टैनसीन) 160 मि.ग्रा.	420 नग	26.02.2026
4.	82262174	टैबलेट सेमाग्लूटाइड 7 मि.ग्रा.	45990 नग	23.02.2026
5.	82261196	इंसुलिन एस्पार्ट एवं इंसुलिन डिग्लुडेक इंजेक्शन 30/70, 100 IU प्रति मि.ली., 3 मि.ली. कार्ट्रिज (मध्यम अवधि प्रभावी इंसुलिन)	8706 नग	23.02.2026

निविदा शर्तें : 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानि www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी।

टेंडर नोटिस सं.: टेबलेट/इंजेक्शन और दवाएं

दिनांक: 29.01.2026 321/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

राशिफल

मेष – रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा।

वृष – परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। मानसिक शान्ति रहेगी,परन्तु बातचीत में संयत रहें। लाभ के अवसर मिलेंगे।

मिथुन – तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।सेहत का ध्यान रखें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

कर्क – आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

सिंह – कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। यात्रा खर्च बढ़ सकते हैं। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। रहन-सहन कष्टमय रहेगा।

कन्या – परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती हैं। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। क्रोध के अतिरेक से बचें।

तुला – धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। चिकित्सीय खर्च बढ़ सकते हैं।

वृश्चिक – भाग-दौड़ अधिक रहेगी। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। बातचीत में सन्तुलन बनाये रखने का प्रयास करें। वस्त्र उपहार में प्राप्त हो सकते हैं।

धनु – कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शैक्षिक या बौद्धिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

मकर – व्यर्थ के क्रोध एवं वाद-विवाद से बचें। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। सन्तान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।

कुंभ – तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। पठन-पाठन में रुचि रहेगी। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि के स्रोत विकसित होंगे।

मीन – दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। वाणी में मधुरता रहेगी।

मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग़ में जांच के नाम पर दिखावे का खेल

नई दिल्ली। डॉक्टरों को सदियों से समाज ने भगवान का स्वरूप माना है लेकिन जब यही भगवान अपनी संवेदना और नैतिकता को बेचकर मौत का सौदा करने लगें तो यह आस्था टूटकर भय और आक्रोश में बदल जाती है। ये कलयुगी बहुरूपिये ठीक वैसे छल करते हैं, जैसे रावण ने मुनि का भेष धारण कर विश्वासघात किया था। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या ये तथाकथित भगवान ही अब मौत का चेहरा बन चुके हैं? क्या इस नेक व्यवसाय का इस हद तक व्यापारीकरण हो चुका है कि किसी इंसान की जिन्दगी का भी कोई मूल्य नहीं? क्या लालच और स्वार्थ के आगे मानवता को तिलांजलि देने वाले ऐसे क्रूर हत्यारों की जिम्मेदारी केवल ईश्वर की अदालत तक सीमित है? 30 दिसम्बर 2025 की रात साढ़े आठ बजे वरुण सिंह को मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग़ में 102F बुखार और बेचैनी की शिकायत के साथ भर्ती कराया गया था। इमरजेंसी में भर्ती होने के दो घंटे बाद तक केवल जांच के नाम पर दिखावे का खेल चलता रहा। तात्कालिक राहत के लिये दवा देने के बजाय, नौसिखिये डॉक्टर सिर्फ समय बर्बाद करते रहे। मनमाने ढंग से एनेस्थीसिया के तीन-तीन इंजेक्शन देकर एम.आर.आई. करवाने ले जाया गया। एनेस्थीसिया के ओवरडोज तथा इलाज में लापरवाही की वजह से वरुण ने एम.आर.आई. मशीन में ही दम तोड़ दिया। मानवीय संवेदनाओं से परे, इसके बाद भी अस्पताल के संवेदनहीन जल्लाद डॉक्टर गिद्ध की तरह केवल धनलोलुपता में इलाज का ढोंग करते रहे। मृतक के पिता एस.आर. सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल तथा देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उक्त अस्पताल में चल रहे कुकृत्य की जांच कर उन पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि मैक्स जैसे नामी अस्पताल बड़े-बड़े डॉक्टरों के नाम का इस्तेमाल केवल अपनी ब्रांडिंग के लिये करते हैं।

शब्द पहेली - 6123

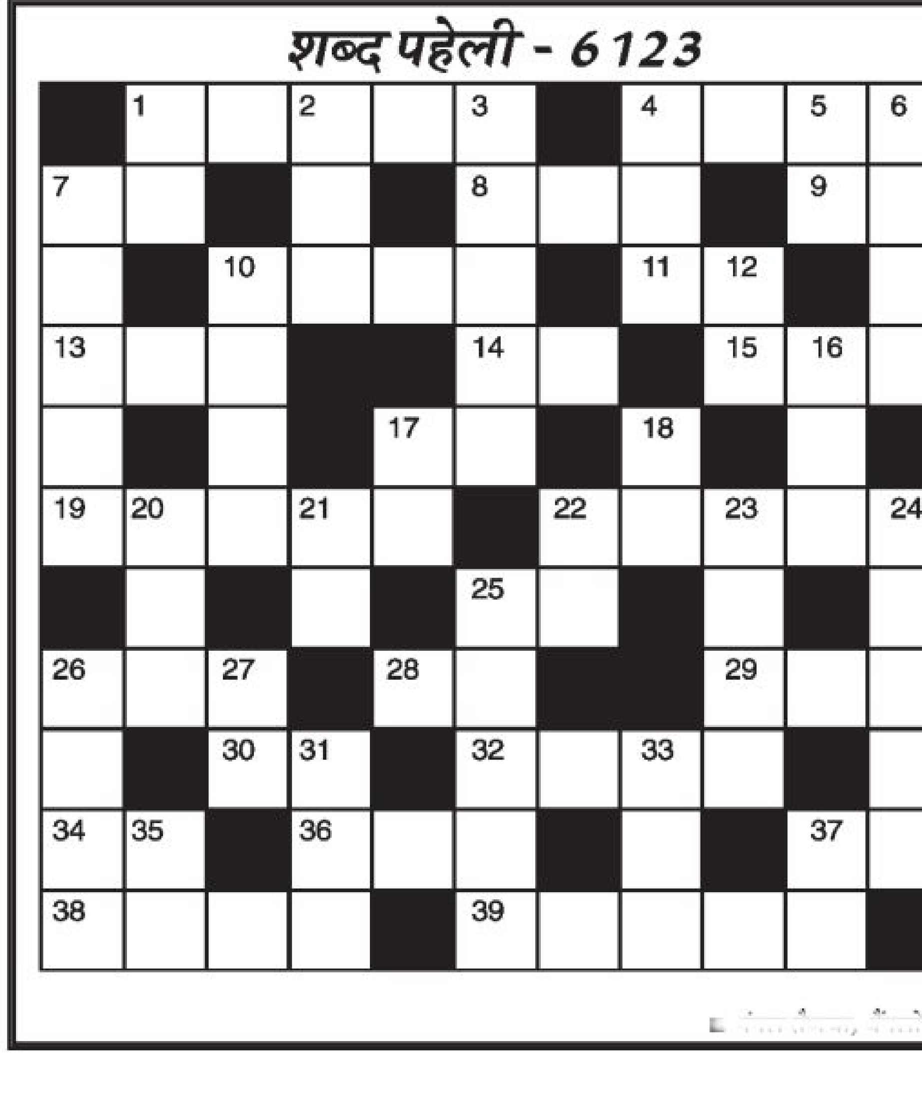

बाएँ से दाए
1.अपनापन का विलोम-5
4.हठ करना,रोना,लालसा करना-4
7.गीत (अंग्रेजी-2)
8.गलीचा,कारपेट-3
9.किनारा,छोर-2
10.झगड़ा,कहासुनी-4
11.समय,वक्त-2
13.बेबस-3
14.राष्ट्र,स्वदेश-2
15.पुत्र,लड़का-3
17.प्राप्त करना-2
19.सेंधमार-5
22.चरित्र,व्यवहार-2,3
25.जीव,दूत,जासूस-2
26.आत्मबलि देना-3
28.ताकत,जोश,बल-2
29.कराह,टीस,लालसा-3
30.वहम,संदेह-2
32.आह भरना-4
34.दूर्वा,घास-2
36.चोंगा,गाऊन-3
37.सफर,जात्रा-2
38.दयालु,कृपालु-4
39.निर्माण करने वाला-5

ऊपर से नीचे
1.पांव, पैर-2
2.भिखारी,मंगता-3
3.अस्वीकृत करना-3,2
4.माला का मोती-3
5.बुरी आदत-2
6.नाटक से परिपूण-4
7.हल्का काला,श्याम-5
10.व्यवस्थित-4
12.बुरी आदत-2
16.अनुकृति-3
17.तांबूल,पत्ता-2
18.रुखसार,कपोल-2
20.डोली अथवा पालकी उठाने वाले -3
21.जोड़,योग-2
22.चतुर्थ-2
23.आनंद ध्वनि करना-4
24.महात्मा गांधी की दांडी यात्रा-5
25.चमकीला-5
26.नीच,नराधम -4
27.विनाश, नेस्तनाबूत-2
31.रंग (अंग्रेजी-3)
33.पराजित करना-3
35.गौरेया, एक चिड़िया-2
37.दोस्त,मित्र, सखा-2

शब्द पहेली- 6122 का हल

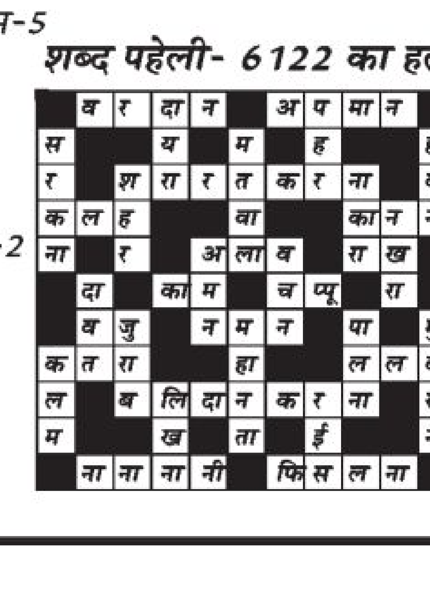

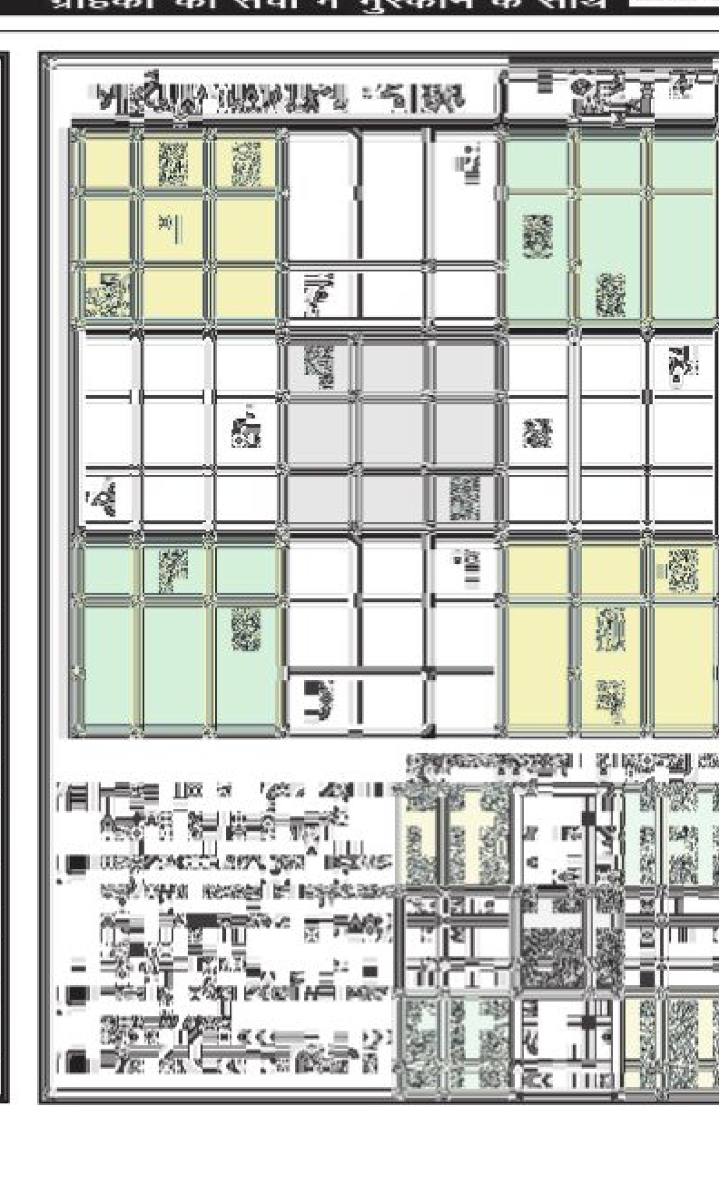

Last Day to join Private Channel, I am closing it now.

✅ I Give My Earliest Newspapers updates from 5 AM in Private channel with All Editions

♦ Indian Newspaper

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ International Newspapers channel

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ Magazine Channel

National & International

[Genaral & Exam related]

Click Here

♦ English Editorials

[National + International Editorials]

प्रेरणा

हम जितने ऊंचे पद पर बैठते हैं, हमें उतना ही विनम्र होना चाहिए। -सिसरो

संपादकीय

ईयू से ट्रेड-डील के हमारे लिए मिले-जुले संकेत

भारत-ईयू ट्रेड डील की घोषणा के कुछ पल बाद ही अमेरिकी वित्त-मंत्री ने कहा कि यह डील दोनों पार्टनरों द्वारा यूएस के ट्रेड दबाव की प्रतिक्रिया में उठाया गया रणनीतिक कदम है। डील का यह प्रावधान यूएस को सबसे ज्यादा चुभने वाला है कि भारत को पर्यावरण-प्रयास पर मिली छूट वही है, जो यूएस को एक साल पहले फॉरवर्ड-मोस्ट फेवर्ड नेशन मान कर दी गई थी। इसका लाभ भारत को स्टील, एल्युमीनियम, सीमेंट, आॅइल रिफाइनरी, पेपर, ग्लास और फर्टिलाइजर के निर्यात में मिलेगा क्योंकि अमेरिका की तरह भारत भी इनके निर्माण में कार्बन उत्सर्जन वाली भट्टियों का इस्तेमाल करता है। बहरहाल एक अड़चन होगी भारत के कृषि उत्पादों में कीटनाशकों का भारी इस्तेमाल, जिसे ईयू मानव स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं मानता। ईयू के कानूनी प्रावधान बाहरी देशों द्वारा निर्यात के लिए काफी जटिल और कड़े हैं। उन पैरामीटर्स पर खरा उतरने के लिए भारत के निर्माताओं को अधिक निवेश करना होगा। दूसरी ओर ट्रेड विशेषज्ञों को मानना है कि भारत का तीन-चौथाई ट्रेड पहले ही 1% टैरिफ वर्ग में आता है, लिहाजा डील से बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। बहरहाल ईयू का भारत को अमेरिका के समकक्ष पसंदीदा मानना, विश्व राजनीति में एक मजबूत संदेश देने के अलावा हमारे यहां के रोजगार देने वाले एमएसएमई सेक्टर्स के लिए भी संजीवनी की तरह है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

गांधी और हनुमान दोनों के पास राम नाम की ताकत थी

आज गांधी फिर याद किए जाएंगे। यह बात तो उनके आलोचक भी मानते हैं कि गांधी जी इंसानियत के शिक्षक थे। और भक्तों का कहना है कि हनुमान जी मानवता के गुरु हैं। गांधी कहा करते थे कि जो सत्य की खोज में हो, वो हिंसक नहीं हो सकता। जब हम सुंदरकांड में हनुमान जी की लंका यात्रा देखते हैं तो इसका प्रमाण मिल जाता है। कुछ बातें गांधी की आज भी सही लगती हैं- सत्यता, सादगी, सदाचार, स्वदेशी और स्वच्छता। गांधी से जुड़ने के लिए सारे रास्ते राजनीति की भेंट चढ़ गए, लेकिन हनुमान जी से जुड़ने के लिए एक रास्ता बड़ा सरल है- हनुमान चालीसा। इसे मंत्र के रूप में सामूहिक रूप से पढ़ें तो पूरे ब्रह्मांड में उसकी पॉजिटिव एनर्जी विस्तारित होगी। इसीलिए एक कार्यक्रम 'महानिर्वाण' के नाम से किया जाता है। संस्कार टीवी पर आज शाम 7 बजे उसे देखा जा सकता है। हनुमान जी और गांधी- दोनों ने भक्ति का सक्रिय रूप समाज को अर्पित किया था। दोनों के पास राम नाम की ताकत थी। हम इसे अपना सकते हैं। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

टु द पीपुल • स्त्रियों के लिए न्याय के क्या मायने हैं?

हमारा सिस्टम ही महिलाओं के पक्ष को कमजोर करता है

कानून

डेरेक ओ ब्रायन
राज्यसभा में टीएमसी के नेता
office@derek.in

इस महीने की शुरुआत में मणिपुर में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई एक 20 वर्षीय युवती ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीड़िता की बहन के ये शब्द मुझे कभी नहीं भूलेंगे- 'कोई उसे न्याय नहीं दिला सका।' भारत में महिलाओं के लिए न्याय के क्या मायने हैं? देखें कि कैसे हमारा कानूनी-तंत्र ही महिलाओं के पक्ष को कमजोर करता है।

1. भारतीय दंड संहिता, 1860 में संहिताबद्ध और भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में कायम रखे गए कानून के तहत पति द्वारा पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए गए यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं माना गया है। यह कानून विवाह में महिलाओं की सहमति के सिद्धांत को नकारता है, क्योंकि पत्नी के निर्णय के बजाय पति के यौन-अधिकार को महत्व देता है। यद्यपि महिलाएं घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत नागरिक समाधानों की मांग कर सकती हैं, लेकिन वैवाहिक दुष्कर्म पर आपराधिक कार्रवाई से इनकार एक ऐसी व्यवस्था को मजबूत करता है, जिसमें किसी स्त्री के अपने शरीर पर अधिकार को उसके वैवाहिक स्टेटस के समक्ष नगण्य माना जाता है। 1971 में 42वीं विधि आयोग रिपोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की सिफारिश की थी, लेकिन उसे माना नहीं गया।

2. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और उससे संबंधित कानूनों के तहत विवाह की न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। लेकिन इस भेद का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यदि उद्देश्य कम उम्र में विवाह को रोकना है तो यह सभी जेंडर के लिए समान होना चाहिए। और यदि उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा ही है, तो उनके लिए विवाह की आयु को कम रखना इस लक्ष्य को मजबूत कैसे बना सकता है? उलटे यह इस धारणा को वैधता देता है कि विवाह के समय स्त्री और पुरुष की आयु में अंतर होना चाहिए। ऐसा करके यह स्त्री की पुरुष पर निर्भरता को बढ़ावा देता है और उनकी शिक्षा को सीमित करता है। जो कानून असमानता को संस्थागत रूप देता हो, वह गरिमा को बढ़ावा देने का दावा नहीं कर सकता।

3. दाम्पत्य सहवास की बहाली (आरसीआर) का प्रावधान पति या पत्नी को यह अधिकार देता है कि यदि दूसरा जीवनसाथी कोई उचित कारण सिद्ध किए बिना अलग रह रहा हो, तो उसे साथ रहने के लिए बाध्य किया जा सके। यह प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 22 में संहिताबद्ध है। यह विवाह को सहमति पर आधारित संबंध के बजाय सहवास के कानूनी दायित्व के रूप में देखता है। इसके चलते विवाह-संबंध से अलग होकर रहने वाले व्यक्तियों- अधिकतर महिलाओं पर यह बोझ डाल दिया जाता है कि वे अपने निर्णय को तर्कसंगत ठहराएं, फिर भले ही अलगाव का कारण भावनात्मक, मानसिक या यौन उत्पीड़न ही क्यों न हो। चूंकि वैवाहिक दुष्कर्म अपराध नहीं है, इसलिए यह प्रावधान महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों में लौटने के लिए मजबूर कर सकता है, जो उनकी गरिमा से समझौता करती हों।

4. पॉक्सो कानून, 2012 के तहत यौन उत्पीड़न संबंधी अपराधों में असहमति का प्रमाण आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि 18 वर्ष से कम आयु के किशोर-किशोरी किसी यौन क्रिया में संलिप्त हैं, तो इसमें उनकी सहमति अप्रासंगिक हो जाती है। पॉक्सो के अंतर्गत बड़ी संख्या में दर्ज होने वाले मुकदमे किशोरों के बीच सहमति-आधारित प्रेम संबंधों से जुड़े होते हैं। ऐसे मुकदमे अकसर स्वयं उनके परिजनों द्वारा दर्ज किए जाते हैं, जो विशेषकर अंतर-जातीय, अंतर-धार्मिक या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य संबंधों में लड़कियों की पसंद को नियंत्रित करना चाहते हैं। यौन शोषण और सहमति से बनाए संबंधों के बीच भेद किए बिना यह कानून किशोरों की स्वायत्तता पर तो अंकुश लगाता है, लेकिन उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान नहीं कर पाता।

वैवाहिक दुष्कर्म पर आपराधिक कार्रवाई से इनकार एक ऐसी व्यवस्था को मजबूत करता है, जिसमें किसी स्त्री के अपने शरीर पर अधिकार को उसके वैवाहिक स्टेटस के समक्ष नगण्य माना जाता है। वैवाहिक दुष्कर्म अपराध क्यों नहीं है?

5. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 विवाह के झूठे वादे के आधार पर बनाए यौन संबंध को अपराध घोषित करती है। यह इस धारणा पर आधारित है कि महिलाओं की यौन सहमति विवाह की अपेक्षा से ही जुड़ी होती है। इस तरह सहमति पर आधारित संबंधों को भी धोखा बता दिया जाता है। रिश्तों में इरादे समय के साथ बदलते हैं, लेकिन स्पष्ट कानूनी मानकों के अभाव में यह प्रावधान दुरुपयोग की संभावना पैदा करता है। जब तक हमारे कानूनों में सहमति सशर्त बनी रहेगी, तब तक महिलाओं के लिए न्याय भी सशर्त ही रहेगा- जो गरिमा, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक वादे के विपरीत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं। इस लेख की सहायक शोधकर्ता चाहत मंगतानी हैं।)

दूरदृष्टि • यह विकसित देश बनने के लिए जरूरी है

टैरिफों के बहाने ही सही, हम ट्रेड-डील्स की ओर तो बढ़े

ट्रेड

नीरज कौशल
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर
nk464@columbia.edu

ट्रम्प भारत को 'किंग ऑफ टैरिफ' कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की अनेक मान्यताएं और बयान भले ही दुरुस्त ना हों, लेकिन इस एक बिंदु पर वे सही हैं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत के पास यकीनन सबसे ऊंची टैरिफ-दीवारें और अनेक गैर-टैरिफ बाधाएं हैं। भारत के लिए बेहतर होगा अगर वो टैरिफ और गैर-टैरिफ- दोनों से संबंधित बाधाओं को कम करे। व्यापार में आने वाली रूकावटें एक विकसित राष्ट्र बनने की राह को और कठिन बना देती हैं।

आत्मनिर्भर भारत के विचार में देश की मौजूदा ट्रेड-नीति का सार है। इसके चलते ही पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार ने टैरिफ बढ़ाए हैं, बड़ी संख्या में गैर-टैरिफ बाधाएं खड़ी की हैं और व्यापार समझौतों से परहेज किया है। अफसोस कि जहां भारतीय मीडिया ट्रम्प के टैरिफों की तीखी आलोचना करता है, वहीं मोदी सरकार की कांग्रेस के जमाने वाली संरक्षणवादी नीतियों की ओर वापसी को खामोशी से स्वीकार कर लिया जाता है। यह भारत के हित में नहीं है।

1980 के दशक में भारत की औसत टैरिफ दर लगभग 125% के आसपास थी। इतनी ऊंची टैरिफ दरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर के बजाय गैर-प्रतिस्पर्धी बना दिया। पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के विपरीत- जिन्होंने व्यापार के सहारे आर्थिक समृद्धि हासिल की- भारत की इस नीति ने अर्थव्यवस्था को धीमी विकास दर की राह पर बांध दिया।

उस समय भारत को अक्सर 'बास्केट केस' कहा जाता था- यानी ऐसी गंभीर वित्तीय या आर्थिक कठिनाइयों वाला देश, जो अपने कर्ज चुकाने में भी असमर्थ हो। 1990 में यही स्थिति पैदा हो गई थी, जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 1 अरब डॉलर से भी नीचे आ गया। यह मुश्किल से तीन हफ्तों के आयात के लिए ही पर्याप्त था। भारत को बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण लेने के लिए अपने स्वर्ण भंडार को गिरवी रखना पड़ा था और आईएमएफ से 2 अरब डॉलर के आपात ऋण के लिए सम्पर्क करना पड़ा, जो अर्थव्यवस्था की री-स्ट्रक्चरिंग की शर्तों के साथ आया। इसके बाद के दो दशकों में सरकारों ने टैरिफ कम किए और 2013 तक प्रभावी टैरिफ दर घटकर 13% रह गई।

लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत एनडीए सरकार ने न केवल उदारीकरण को रोक दिया, बल्कि टैरिफ भी धीरे-धीरे फिर से बढ़ने लगे। 2021 तक तो प्रभावी टैरिफ दर बढ़कर 18% हो गई। गैर-टैरिफ बाधाओं का हालिया इतिहास- जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स या क्यूसीओ के रूप में सामने आया है- उतना ही चिंताजनक है। 2014 में केवल 14 क्यूसीओ लागू थे। 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर 800 से अधिक हो गई। औपचारिक रूप से इन्हें उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये आयात को सीमित करने वाले गैर-टैरिफ उपाय हैं। उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय ये भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर कर रहे हैं और विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर रहे हैं।

अच्छी खबर यह है कि सरकार अब क्यूसीओ को कम करने पर ध्यान देती हुई दिख रही है। नवंबर 2025 में सरकार ने टेक्स्टाइल्स क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले रसायनों, पॉलिमरों और फाइबर इंटरमीडियरीज से जुड़े 14 क्यूसीओ हटाए। साथ ही ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न उद्योगों में उपयोग होने वाले स्टील-संबंधी इंटरमीडियरीज पर लागू 55 अन्य क्यूसीओ भी समाप्त किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि कस्टम्स मेरा अगला बड़ा क्लीन-अप असाइनमेंट है। उम्मीद है कि इस सफाई अभियान में टैरिफ दरों में उल्लेखनीय कटौती, टैरिफ की संख्या में कमी और अधिक से अधिक क्यूसीओ को समाप्त या कम करने जैसे कदम भी शामिल होंगे।

ट्रम्प के टैरिफ-युद्ध ने भारत को आत्मनिर्भरता के खोल से बाहर निकलकर व्यापार समझौतों के जरिये नए बाजार तलाशने के लिए भी मजबूर किया है। लगता है 2026 का साल द्विपक्षीय ट्रेड-डील्स का साबित होगा।

ट्रम्प के टैरिफ-युद्ध ने भारत को आत्मनिर्भरता के खोल से बाहर निकलकर व्यापार समझौतों के जरिये नए बाजार तलाशने के लिए भी मजबूर किया है। पिछले एक वर्ष में भारत ने यूके, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के चार सदस्य देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। अब ईयू से भी ट्रेड डील कर ली गई है। ऐसा लगता है कि 2026 का साल द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में प्रवेश का साबित होगा।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक | प्यूमा, जर्मनी की स्पोर्ट्सवियर कंपनी

भाइयों के झगड़े के बाद शुरू हुई थी प्यूमा, 1993 में गंभीर संकट में फंसी, अब स्पोर्ट्सवियर दिग्गजों में

वर्ष 1987, बाजार से पूंजी जुटाने के लिए प्यूमा आईपीओ लेकर आई। कंपनी मैनेजमेंट ने इस आईपीओ से मिली पूंजी का विस्तार के लिए आक्रामक रूप से इस्तेमाल किया। यहां तक कि बिना सोचे-समझे बैंकों से भी भारी कर्ज ले लिया। इसके बाद जब सेल्स उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी, तो कंपनी ने जमा माल को बेचने के लिए डिस्काउंट स्टोर्स में इन्हें बेचना शुरू कर दिया। इससे प्यूमा की पहचान एक 'प्रीमियम एथलेटिक ब्रांड' से घटकर 'डिस्काउंट स्टोर ब्रांड' जैसी बन गई। निवेशक डर गए, शेयर की कीमतें क्रैश हो गईं और कंपनी उस कर्ज के जाल में फंस गई जिसका ब्याज चुकाना भी 1993 तक असंभव लगने लगा था।

हालांकि कंपनी ने समय रहते नेतृत्व में बदलाव करने, गैर जरूरी खर्चों में कटौती और रीस्ट्रक्चरिंग जैसे उपायों से खुद को डूबने से बचा लिया। इसके बाद नए बाजारों में पहुंच, विस्तार की नई रणनीतियों के चलते प्यूमा न केवल बाजार में मजबूती के साथ वापस लौटी बल्कि दुनिया की शीर्ष स्पोर्ट्सवियर कंपनियों में शामिल हो गई। प्यूमा की कहानी बताता है कि अगर रणनीति सही न हो तो बड़ा से बड़ा ब्रांड भी धराशायी हो सकता है। ऐसे में आज ब्रांड से सबक में पढ़िए कहानी प्यूमा की।

वर्तमान स्थिति

120 से अधिक देशों में बिक रहे हैं इसके प्रोडक्ट

आज प्यूमा दुनिया की प्रमुख स्पोर्ट्सवियर कंपनियों में शामिल है। प्यूमा के उत्पाद 120 से अधिक देशों में बिकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब 38 हजार करोड़ रुपए है। फुटवियर सेगमेंट कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें फुटबॉल, और लाइफस्टाइल स्नीकर्स शामिल हैं। भारत के 30 राज्यों में इसके शोरूम हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 3300 करोड़ रुपए के उत्पादों की बिक्री भारत में की। उसका ई-कॉमर्स बिजनेस सालाना 20% की दर से बढ़ रहा है।

सबक क्यों- कभी आर्थिक संकट इतना था कि बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया था, अब अक्सर टॉप थ्री कंपनियों में रहती है शामिल।

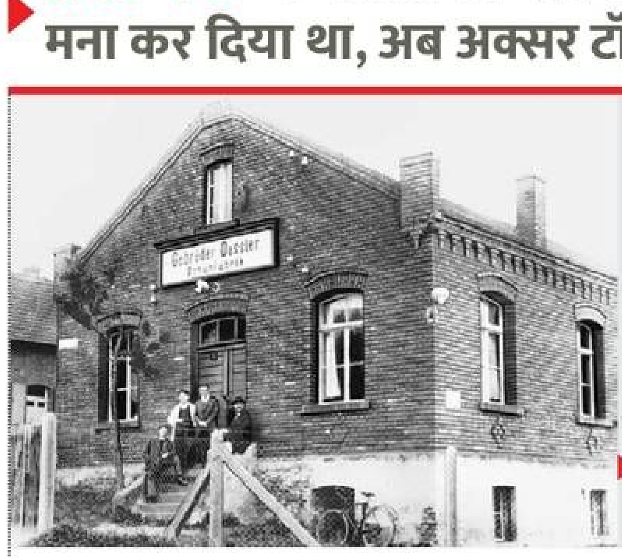

120 से अधिक देशों में प्रोडक्ट बेचती है प्यूमा।

38 हजार करोड़ रुपए मूल्य की कंपनी है वर्तमान में प्यूमा।

30 भारतीय राज्यों में शोरूम हैं कंपनी के।

3300 करोड़ रु. के करीब उत्पाद बेचे हैं कंपनी ने 2023-24 में भारत में।

तस्वीर डास्लर ब्रदर्स शू फैक्ट्री की है, जिसे एडिडास और प्यूमा शुरू करने वाले डास्लर ब्रदर्स चलाते थे।

4 कारणों से संकट में घिरी थी प्यूमा

1. **ब्रांड वैल्यू से समझौता** : 80 के दशक के अंत तक प्यूमा यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह एक स्पोर्ट्स ब्रांड है या मास-मार्केट डिस्काउंट ब्रांड। प्यूमा हर जगह सस्ते दाम पर बिकने लगा। इससे इसकी ब्रांड वैल्यू कमजोर पड़ गई।
2. **एडिडास से अंधा कॉम्पीटिशन :** एडिडास को हराने के चक्कर में रुडोल्फ ऐसे फैसले लेते रहे, जो आर्थिक रूप से गलत थे। वे इनोवेशन के बजाय सिर्फ एडिडास को नीचा दिखाने पर केंद्रित रहे।
3. **ट्रेंड को समझने में चूक :** 90 के दशक में जूते सिर्फ खेल मैदान तक सीमित नहीं रहे, वे 'स्ट्रीट वियर' बन रहे थे। नाइकी ने 'एयर जॉर्डन' के जरिए यह खेल समझ लिया, लेकिन प्यूमा इसमें पिछड़ गया।
4. **लीडरशिप का अभाव: :** रूडोल्फ के बेटों के हटने के बाद कंपनी वर्षों तक बिना ठोस लीडरशिप के चलती रही, जिसका असर सेल्स पर पड़ा।

इस तरह की वापसी

1. **योचेन जिट्ज को सीईओ बनाना :** कंपनी ने 30 साल के योचेन जिट्ज को सीईओ बनाया। योचेन ने आते ही '100-दिन का सर्वाइवल प्लान' लागू किया। उन्होंने गैर-जरूरी खर्चों में 25% की कटौती की। इससे कंपनी का बर्न-रेट कम हुआ।
2. **स्पोर्ट्स-लाइफस्टाइल का नया कॉन्सेप्ट :** स्पोर्ट्स-लाइफस्टाइल शब्द दिया। कहा कि हर कोई एथलीट नहीं है, लेकिन वैसा दिखना चाहता है। फैशन डिजाइनर जिल सैंडर को खुद से जोड़ा।
3. **सेलेब्रिटी और कल्चरल इन्फ्लुएंस :** प्यूमा ने सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, बल्कि पॉप कल्चर के दिग्गजों को पकड़ा। मैडोना का प्यूमा पहनना एक टर्निंग पॉइंट था।
4. **नीश मार्केटिंग:** प्यूमा ने उन खेलों को चुना जहां नाइकी और एडिडास कम सक्रिय थे, जैसे फॉर्मूला वन रेस। आज प्यूमा मोटरस्पोर्ट्स गियर में लीडर है।

रफ्तार और फुर्ती को दिखाने के लिए रखा गया था प्यूमा नाम

शुरुआत : दो भाइयों के झगड़े ने रखी थी प्यूमा कंपनी की नींव

1924 में जर्मनी के हर्जोगेनौराच में दो भाइयों, एडोल्फ और रूडोल्फ डास्लर ने 'डास्लर ब्रदर्स शू फैक्ट्री' शुरू की, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोनों के बीच मतभेद और गलतफहमियां इतनी बढ़ीं कि 1948 में वे अलग हो गए। एडी ने एडिडास बनाई और रूडी ने अलग कंपनी शुरू की। रूडी ने कंपनी को ऐसी पहचान देने की कोशिश की जो रफ्तार और फुर्ती की प्रतीक हो।

सबसे गंभीर संकट : 1993, जब बैंकों ने उधार देने से मना कर दिया

1993 का साल कंपनी के लिए सबसे गंभीर संकट लेकर आया। कर्ज उसकी क्षमताओं से अधिक हो गया। मीडिया में इसके भविष्य को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई जाने लगीं। अधिकांश बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया। तभी कंपनी ने एक दांव खेला। 30 साल के योचेन जिट्ज को सीईओ बनाया, जिन्होंने कमाल करते हुए उसे संकट से बाहर निकाला।

ऐसे पड़ा नाम : रूडोल्फ ने पहले कंपनी का नाम अपने नाम के अक्षरों पर 'Ruda' रखा था। बाद में बदलकर 'प्यूमा' कर दिया, जो तेजी और फुर्ती का प्रतीक था।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : प्यूमा के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी एडिडास और नाइकी हैं। हाल के कुछ वर्षों में अंडर आर्मर और स्केचर्स से भी चुनौती मिली है।

पीपुल भास्कर | अरिजीत सिंह | प्रसिद्ध भारतीय प्लेबैक सिंगर

700 गाने गाए, स्पॉटीफाई पर सर्वाधिक 14 करोड़ फॉलोअर्स, बच्चों की शिक्षा पर काम कर रहे अरिजीत

वर्ष 2005, सोनी टीवी पर एक संगीत रियलिटी शो आया फेम गुरुकुल। इस शो के जज थे मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर महादेवन और गायक केके। शो में प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए अरिजीत सिंह 6वें स्थान पर रहे और बाहर हो गए। उस दौरान जावेद अख्तर ने कहा था, 'ये तुम्हारा कम, शो का नुकसान ज्यादा है।'

अरिजीत सिंह की गिनती लाइमलाइट से बहुत दूर रहने वाले, कम बोलने वाले, सिर्फ काम पर फोकस करने वाले लोगों में होती है। उनसे जुड़ा एक किस्सा है। मुंबई में एक शो चल रहा था। शो के बाद अरिजीत घर जाने के लिए अपनी कार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कार को लेकर आने में ड्राइवर को समय लग रहा था। तभी सामने उन्हें एक ऑटो दिखा। अरिजीत ने ऑटोवाले को आवाज दी और बैठकर घर चले गए। अरिजीत कहते हैं कि उन्हें प्रसिद्धि से बहुत लगाव नहीं है। उन्हें सादगी पसंद है। यही कारण है कि कई बार स्कूटी पर घूमते हुए या झोला लिए सब्जी खरीदते हुए उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। वे कहते हैं कि वे इसलिए गाते हैं क्योंकि उन्हें संगीत पसंद है।

मीडिया सूत्रों के अनुसार फिलहाल वे निर्देशक के रूप में कदम रखने जा रहे हैं। वे एक जंगल एडवेंचर फिल्म बना रहे हैं, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। संगीत के अलावा उन्हें साइकिल चलाना, पढ़ना, फोटोग्राफी करना, बैडमिंटन, लेख लिखना और डॉक्यूमेंट्री बनाना पसंद है। वे फुटबॉल के भी प्रशंसक हैं।

चर्चा में क्यों- हाल ही में उन्होंने अचानक प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की घोषणा कर लोगों को चौंका दिया है।

दुनिया के शीर्ष डीजे में शुमार नीदरलैंड्स के मार्टिन गैरिक्स (दाएं) 2023 में अरिजीत सिंह से मिलने आए थे।

अरिजीत सिंह गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने के अलावा गरीबों के लिए मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, जहां बेहद सस्ता इलाज उपलब्ध हो। फिलहाल वे इस समय फिल्म मेकिंग पर फोकस कर रहे हैं।

जन्म : 25 अप्रैल 1987
जियागंज, पश्चिम बंगाल
शिक्षा : ग्रेजुएट
परिवार : पत्नी- कोयल सिंह, 3 बच्चे
संपत्ति : करीब 414 करोड़ रुपए
(विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार)

शुरुआत

हजारी बंधुओं से ली है संगीत की शिक्षा

अरिजीत के पिता काकर सिंह पंजाबी सिख थे जबकि मां बंगाली हिंदू। अरिजीत की मौसी प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीत गायिका थीं जबकि मामा तबला बजाते थे। उनकी नानी भी गाती थीं। ऐसे में अरिजीत का बचपन से ही संगीत के प्रति रुझान रहा। प्रसिद्ध हजारी बंधुओं राजेंद्र, धीरेंद्र और बीरेंद्र से उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, तबला और पॉप संगीत की शिक्षा ली।

विवाह

दो शादियां की, पहली साल भर भी नहीं चली

अरिजीत ने रियलिटी शो 'फेम गुरु' में प्रतिभागी रही रूपरेखा बनर्जी से 2013 में शादी कर ली। हालांकि उसी साल दोनों का तलाक हो गया। कहा जाता है कि यह शादी आवेग में आकर की गई थी, जिसके चलते टिक नहीं सकी। फिर 2014 में बचपन की दोस्त कोयल राय से उन्होंने शादी की। यह दोनों की दूसरी शादी थी। कोयल को पहले पति से एक बेटी है।

करियर

रियलिटी शो से फिल्म फेयर अवॉर्ड तक

करियर की शुरुआत 2005 में रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' से हुई। हालांकि वे 6वें स्थान पर रहे। फिर रियलिटी शो '10 के 10 ले गए दिल' में भाग लिया और विजेता बने। 2011 में फिल्म मर्डर-2 के गाने 'फिर मोहब्बत' से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की। पहचान आशिकी 2 के गाने 'तुम ही हो' से मिली। इसके लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर मिला।

रोचक : 2016 से 20 तक 5 बार लगातार फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते थे।

खास : गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए चला रहे एनजीओ

- 'लेट दियर बी लाइट' नाम से एनजीओ चलाते हैं जो गरीब बच्चों की पढ़ाई पर काम करता है।
- अरिजीत अब तक 532 हिंदी, 144 बंगाली और 25 तेलुगु समेत कई भाषाओं में 700 से ज्यादा गाने का चुके हैं।
- स्पॉटीफाई पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले सिंगर हैं। उनके 14 करोड़ फॉलोअर्स हैं।

उपलब्धि : संगीत से जुड़े 100 से अधिक अवॉर्ड जीत चुके हैं

- 2025 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।
- वे संगीत से जुड़े 100 से अधिक अवॉर्ड्स जीत चुके हैं। इनमें 2 नेशनल और 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड भी शामिल हैं। उन्होंने 2016 से 2020 तक लगातार पांच बार फिल्मफेयर अवॉर्ड जाता था।

विवाद भी : मारपीट में गिरफ्तार हुए, सलमान से भिड़े

- सितंबर 2013 में एक पत्रकार ने जब उनसे पहली पत्नी के साथ तलाक को लेकर प्रश्न पूछा तो उसके साथ मारपीट कर दी थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।
- 2014 के गिल्ड अवॉर्ड में बेस्ट सिंगर का अवॉर्ड मिला था। इस दौरान होस्ट सलमान से भिड़ गए थे। बाद में अरिजीत ने माफी मांगी थी।

इकोनॉमिक सर्वे दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की बदलती नीतियां, एआई की ओर मुड़ता विदेशी निवेश भारत के लिए बाहरी चुनौतियां पेश कर रहे हैं

भरोसे का नया भारत: रिकॉर्ड निवेश, मजबूत बैंकिंग, कॉन्सर्ट इकोनॉमी बदलेंगे तस्वीर

भारत आज न केवल दुनिया का रेमिटेंस चैंपियन है, बल्कि घरेलू निवेशकों के बढ़ते भरोसे के दम पर एक आत्मनिर्भर वित्तीय बाजार भी बन चुका है। भारत अब कृषि और डिजिटल इकोनॉमी के जरिए साख मजबूत कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि बैंकिंग सुधार, बढ़ता हाउसिंग लोन और डिजिटल निवेश मिलकर नए भारत की समृद्ध तस्वीर पेश कर रहे हैं।

खेती से खुशहाली | 5 साल में 8.2% की निर्यात वृद्धि, अब 9.2 लाख करोड़ रु. के क्लब पर नजरें

- केंद्र ने 4 वर्ष में एग्री, मरीन, फूड एक्सपोर्ट 9.2 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य रखा, जबकि वित्त वर्ष 2025 में कृषि निर्यात 4.7 लाख करोड़ रहा। भारत की वैश्विक कृषि निर्यात में हिस्सेदारी सिर्फ 2.2% है। 2020-25 के बीच कृषि निर्यात 8.2% कंपाउंडेड ग्रोथ से बढ़ा, जो कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ से तेज है।

घर का सपना हुआ बड़ा | 10 साल में होम लोन 4 गुना बढ़ा, 37 लाख करोड़ पहुंचा पोर्टफोलियो

2015 में व्यक्तिगत हाउसिंग लोन का बकाया 10 लाख करोड़ था, वहीं मार्च 2025 तक यह 37 लाख करोड़ पहुंच गया। यानी 4 गुना उछाल। अब होम लोन का आकार जीडीपी के 11% पहुंच चुका है। हाउसिंग डिमांड महानगरों तक नहीं रही। टियर-2, 3 शहरों में बढ़ती आय, अनुकूल क्रेडिट ने मांग को आधार दिया है।

रेमिटेंस में हम ग्लोबल लीडर | 12.5 लाख करोड़ रुपए भेजकर प्रवासियों ने भरी भारत की तिजोरी

2025 में देश को 12.5 लाख करोड़ का रेमिटेंस मिला, जो दुनिया में सर्वाधिक है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। बाहरी आर्थिक झटकों के समय सुरक्षा कवच बनती है। अब रेमिटेंस का बड़ा हिस्सा एडवांस्ड इकॉनमीज से है। यानी विदेशों में काम कर रहे भारतीय वर्कर्स की संख्या और आय दोनों बढ़ी हैं।

बैंकिंग का 'सुपर-क्लीन' दौर | 13.2% से बढ़कर 26.2% पहुंचा रिकवरी रेट, आर्थिक सेहत सुधरी

बैंक का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट अनुपात अब 2.2% पर आ गया है, जो कई दशकों में सबसे कम है। खराब कर्जों की वसूली में प्रगति हुई है। एनपीए रिकवरी रेट 2018 के 13.2% से बढ़कर 2025 में 26.2% पहुंच गया। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से रिकवरी 36.6%तक सुधरी है, जो तरक्की के लिए ठोस आधार है।

हमारी बचत में बड़ा बदलाव
12 साल में इक्विटी निवेश आठ गुना बढ़ा, डिपॉजिट 23 फीसदी घटा

अब बचत के पैसे का बड़ा हिस्सा शेयर मार्केट में जा रहा है। शेयर बाजार में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2014 के 11% से बढ़कर सितंबर 2025 तक 18.8% हो गई है। व्यक्तिगत इक्विटी होल्डिंग वित्त वर्ष 14 के 8 लाख करोड़ से उछलकर सितंबर 2025 तक 84 लाख करोड़ पहुंच गई है। म्यूचुअल फंड जैसे परोक्ष रास्तों के जरिए होने वाला निवेश तीन गुना बढ़कर 9.2% हो गया है।

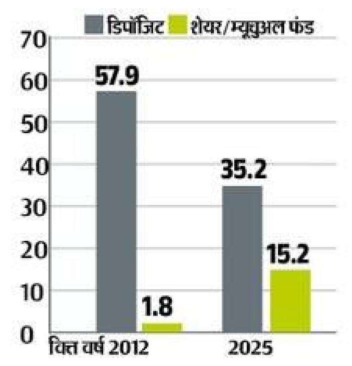

- सालाना वित्तीय बचत में इक्विटी और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2012 के 1.8% से बढ़कर 2025 में 15.2% से अधिक हो गई है। बैंक जमा की हिस्सेदारी 58% से गिरकर 35% रह गई है।

दुनिया का भरोसा बरकरार | 7.5 लाख करोड़ के विदेशी निवेश के साथ साउथ एशिया में अव्वल

अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम है। 2025 में 7.5 लाख करोड़ रुपए का ग्रॉस एफडीआई मिला, जो सालाना आधार पर 13% अधिक है। भारत साउथ एशिया का सबसे बड़ा एफडीआई डेस्टिनेशन है, जो उसकी मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति और नीतिगत स्थिरता को रेखांकित करता है।

कॉन्सर्ट इकोनॉमी | ब्रिटेन से सबक... टूरिज्म और रोजगार का नया पावरहाउस बनेंगे म्यूजिक टूरिज्म

देश में कॉन्सर्ट इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। युवा आबादी, बढ़ती आय ने अनुकूल माहौल तैयार किया। ब्रिटेन में म्यूजिक टूरिज्म ने 2022 में 60,713 करोड़ रुपा का योगदान दिया, जो जीडीपी का 0.3% है। अगर भारत में नीतिगत बाधाएं कम की जाएं, तो कॉन्सर्ट इकोनॉमी टूरिज्म, रोजगार के लिए बड़े अवसर खोलेगी।

भास्कर व्यू

मदन सबनवीस, चीफ इकोनॉमिस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा

अस्थिर दुनिया में घरेलू सुधारों की ताकत भारत को सुरक्षित रखेगी

आर्थिक सर्वे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8-7.2% रखा गया है। नॉमिनल ग्रोथ 10% रहने की उम्मीद है, जो बजट निर्माण का आधार बनेगी। विकास के खपत, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर तीन बड़े इंजन हैं। जीएसटी सुधारों के बाद बढ़ती मांग को बनाए रखना जरूरी है। निजी क्षेत्र के निवेश को गति देना अनिवार्य है ताकि 7% की वृद्धि हासिल हो सके।अमेरिका और अन्य देशों में एई निवेश बढ़ने से विदेशी फंड का प्रवाह प्रभावित हुआ है। हालांकि, भारत का कम चालू खाता घाटा और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षा कवच बन रहे हैं।

श्रम सुधार, यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते निर्यात को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। बाहरी वातावरण अनिश्चित और जोखिम भरा हो सकता है, पर घरेलू सुधारों की ताकत भारत को सुरक्षित रखेगी।

बिजनेस ब्रीफ

शापूरजी पालोनजी ग्रुप भी ला रहा बड़ा आईपीओ

मुंबई | शापूरजी पालोनजी ग्रुप अपनी कंपनी शापूरजी पालोनजी रियल एस्टेट का आईपीओ लाकर 8 हजार करोड़ रुपए जुटाएगा। मिस्त्री परिवार पर प्रमोटर स्तर का करीब 30 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। यह ग्रुप के कुल कर्ज का लगभग आधा है। इसे घटाने के लिए ग्रुप आईपीओ का सहारा ले रहा है।

भारत की विमान फ्लीट तीन गुना होगी: एयरबस

हैदराबाद | एयरबस का मानना है कि भारत की कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लीट एक दशक में तीन गुना बढ़कर 2,250 विमानों तक पहुंच जाएगी। भारत 2035 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन बाजार बन जाएगा। भारत में पैसेंजर ट्रैफिक 2035 तक सालाना 8.9% की दर से बढ़ेगा।

वेदांता का मुनाफा 61% बढ़कर ₹5,710 करोड़

मुंबई| वेदांता ने तीसरी तिमाही के लिए मजबूत नतीजे दिए हैं। कंपनी का समेकित शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 61% बढ़कर 5,710 करोड़ रुपए रहा, जबकि ऑपरेशन से आय 36.9% बढ़कर 23,369 करोड़ रुपए पहुंच गई। तिमाही में एबिटा 34% उछलकर रिकॉर्ड 15,171 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 41% पर पहुंच गया।

टाटा मोटर्स सीवी का लाभ 48% घटा, पर आय बढ़ी

नई दिल्ली| टाटा मोटर्स (कमर्शियल व्हीकल बिजनेस) का तीसरी तिमाही में मुनाफा 48% घटकर 705 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि आय 16% बढ़कर 21,847 करोड़ रुपए पहुंची। तिमाही में ऑपरेटिंग मार्जिन सुधरकर 12.6% रहा। घरेलू वॉल्यूम 18% और निर्यात 70% बढ़ा।

यूरोप को इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 37% बढ़ा

नई दिल्ली | वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से यूरोप को इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात 37% बढ़कर 11.79 अरब डॉलर हो गया। इसमें स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 60% से अधिक रही। इलेक्ट्रॉनिक्स अब इंजीनियरिंग सामान और पेट्रोलियम उत्पादों के बाद भारत की प्रमुख निर्यात जिंसों में है।

कैश बर्न • अक्टूबर-दिसंबर में घाटा 33% बढ़कर 1,065 करोड़

स्विगी: आय 54% बढ़ी, पर इंस्टामार्ट का घाटा 57% बढ़ा

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 1,065 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। यह पिछले साल की इसी तिमाही में हुए 799 करोड़ रुपए के घाटे से 33% ज्यादा है। बीती तिमाही कंपनी की आय 6,148 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले 3,993 करोड़ के मुकाबले 54% ज्यादा है।

गुरुवार को जारी नतीजों के मुताबिक, बिजनेस ग्रोथ के मामले में स्विगी की स्थिति हर तिमाही सुधर रही है। दिसंबर तिमाही में कंपनी को ग्राहकों से मिले कुल ऑर्डर का मूल्य 8.6% बढ़कर 18,122 करोड़ रुपए हो गया। जुलाई-सितंबर तिमाही में यह 16,683 करोड़ रुपए था। सालाना आधार पर इसमें 49% की बढ़ोतरी हुई। संभवतः इसीलिए बीएसई पर स्विगी के शेयर 1% से ज्यादा तेजी के साथ 327.40 रुपए पर बंद हुआ।

नतीजे : 34 नए स्टोर खोलने में खर्च का दिखा असर

ताकत: फूड डिलीवरी से मुनाफा 48 फीसदी बढ़ा

अक्टूबर-दिसंबर में स्विगी के फूड डिलीवरी बिजनेस का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इस सेगमेंट का मुनाफा (एडजस्टेड एबिटा) 48% बढ़कर 272 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले यह 184 करोड़ था। इस बीच इस सेगमेंट की ऑर्डर वैल्यू भी 20.5% बढ़कर 8,959 करोड़ रुपए हो गई।

कमजोरी: क्विक कॉमर्स बिजनेस से घाटा 57% बढ़ा

क्विक कॉमर्स (इंस्टामार्ट) की ऑर्डर वैल्यू तो 103% बढ़कर 7,938 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन प्रतिस्पर्धा और 34 नए स्टोर खोलने में हुए खर्च की वजह से फिलहाल कंपनी को इस सेगमेंट में घाटा हो रहा है। इंस्टामार्ट का घाटा 57% बढ़कर 908 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले 578 करोड़ था।

ग्रोथ: 8,959 करोड़ के फूड ऑर्डर, 3 साल में सबसे ज्यादा

- बीती तिमाही स्विगी के सक्रिय ग्राहकों की संख्या 22% बढ़कर 1.81 करोड़ हो गई।
- फूड ऑर्डर की वैल्यू 8,959 करोड़ हो गई, जो 3 साल में सबसे ज्यादा है।
- रेस्टोरेंट साझेदार बीती 6 तिमाहियों यानी 18 माह में सबसे ज्यादा 9 फीसदी बढ़े।
- बीती तिमाही कंपनी ने निवेशकों से 10,000 करोड़ रुपए।
- मुख्य बिजनेस पर फोकस के लिए रैपिडो में हिस्सेदारी बेचकर भी 2,400 करोड़ रुपए जुटाए।

इसी साल अप्रैल-जून में घाटा खत्म करने का है लक्ष्य

नए आइडिया और बेहतर कामकाज के दम पर हम लंबे समय में सफल होंगे। कंपनी को पर्यावरण, सामाजिक और शासन में 78 अंक मिले, जो हमें लीडरशिप श्रेणी में लाता है। डिलीवरी करने वाले हमारे साथी अभी 6.9 लाख हैं। कंपनी ने अप्रैल-जून 2026 में घाटा खत्म करने का लक्ष्य रखा है।

-श्रीहर्ष मजेटी, सीईओ, स्विगी

भारत-यूरोप के बीच ट्रेड 65% तक बढ़ेगा: मूडीज

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्मुक्त व्यापार समझौते पर मूडीज ने बड़ी संभावना जताई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, इससे दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार 41-65% बढ़ सकता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र होगा, जिसके दायरे में करीब 200 करोड़ लोग और वैश्विक जीडीपी का 25% हिस्सा आएगा। इसके लागू होने पर भारत के टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। भारत से यूरोप भेजे जाने वाले करीब 3 लाख करोड़ रुपए के सामान पर टैक्स नहीं लगेगा। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 4-26% आयात शुल्क लगता था, जो अब शून्य हो जाएगा।

₹1,837 करोड़ थी लागत, ₹138 करोड़ में मिल रहा

कतर रॉयल फैमिली के 'उड़ता महल' पर 92% छूट

दोहा | कतर की रॉयल फैमिली का एक प्राइवेट जेट कंट्रोलर डॉट कॉम पर 1.5 करोड़ डॉलर (138 करोड़ रुपए) में बिक रहा है। साल 1995 में इसे 20 करोड़ डॉलर (1,837 करोड़ रुपए) में खरीदा गया था। इंटीरियर पर ही 64 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस हिसाब से ये उड़ता महल 92% छूट पर उपलब्ध है। यह विमान अभी ऑपरेशनल है, 68,700 घंटे फ्लाइट टाइम, स्पेयर इंजन और पार्ट्स के साथ उपलब्ध है।

नया बाजार • 10 साल में लग्जरी कार खरीदारों की औसत उम्र 15 साल घटी

30-40 साल के युवा खरीद रहे महंगी कारें

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

देश में लग्जरी कारों का बाजार अब अनुभवी दिग्गजों के बजाय रईस युवाओं के सहारे बढ़ रहा है। 10 साल पहले तक महंगी कारें खरीदने वालों की औसत उम्र 45-50 साल थी, जो अब घटकर 30-40 साल रह गई है। बीएमडब्ल्यू के खरीदार अब 30 से 49 साल के बीच हैं, जबकि ऑडी के 70% से ज्यादा ग्राहक 50 साल से कम उम्र के हैं। मर्सिडीज-बेंज की औसत बिक्री कीमत भी महामारी के 57 लाख से बढ़कर अब 1 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। भारत के उलट, अमेरिका और यूरोप में 50% से ज्यादा खरीदार 'बेबी बूमर्स' (55+ उम्र) हैं, जो अपनी कारें लंबे समय तक नहीं बदलते हैं।

लग्जरी कार ग्राहकों की औसत उम्र भारत में कम

देश	10 साल पहले	अब (2026)
भारत	45-50 साल	30-40 साल
चीन	38-40 साल	33-35 साल
अमेरिका	48-52 साल	52-55 साल
यूरोप	44-50 साल	50-54 साल

(स्रोत: मैकिंजी एंड कंपनी, बैन एंड कंपनी और जेडी पावर)

नया ट्रेंड: भारत में 7-10 साल के बजाय अब 3-4 साल में बदली जा रहीं गाड़ियां, इससे मांग बढ़ रही

लग्जरी कार मालिकों का व्यवहार बदला है। पहले लोग एक कार को 7-10 साल तक चलाते थे। अब यह रिप्लेसमेंट साइकिल घटकर 3-4 साल रह गई है। युवाओं में हर नए मॉडल और लेटेस्ट तकनीक तुरंत अपनाने की भूख बढ़ी है। यही वजह है कि कंपनियां अब तकनीक और सॉफ्टवेयर पर ज्यादा निवेश कर रही हैं।

क्या चाहते हैं... सर्विस पैकेज, वारंटी पर फोकस

आज का युवा खरीदार शोरूम जाने से पहले ऑनलाइन पूरी रिसर्च करता है। वे अब सीधे नकद छूट (कैश डिस्काउंट) के बजाय लंबी वारंटी, सर्विस पैकेज और बेहतर रीसेल वैल्यू (बायबैक) पर जोर देते हैं। जेएलआर इंडिया के मुताबिक, नए ग्राहकों के लिए कार अब केवल स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि एक 'पर्सनल स्पेस' या सुकून वाली जगह है।

रिटेल महंगाई के इंडेक्स में फूड का वेटेज घटेगा

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

रिटेल महंगाई (सीपीआई) मापने के नए फॉर्मूले में खाने की चीजों का वेटेज घटाकर 36.75% किया जाएगा, जो अभी 45.86% है। परिवहन का वेटेज 8.8%, स्वास्थ्य का 6.10% और कपड़ों का 6.38% होगा। सरकार का उद्देश्य देश में उपभोग के तरीके में आए बदलाव को दर्शाना है। हाल के सर्वे में शहरी घरों में भोजन पर खर्च 39.7% और ग्रामीण परिवारों में 47% रह गया है। सीपीआई की प्रस्तावित नई सीरीज में 2024 को आधार वर्ष बनाया जाएगा, जो अभी 2011-12 है।

सुधार • शेयर बाजार में तीसरे दिन तेजी, मेटल इंडेक्स में 3% उछाल

आर्थिक सर्वे से सेंसेक्स 982 अंक रिकवर

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही। इसमें इकोनॉमिक सर्वे की बड़ी भूमिका रही। संसद में यह सर्वे पेश होने से पहले सेंसेक्स 81,708 के निचले स्तर पर आ गया था। लेकिन सर्वे आने के बाद यह दिन के निचले स्तर से 982 अंक चढ़कर 82,690 के स्तर तक पहुंच गया। अंत में सेंसेक्स 222 अंक चढ़कर 82,566 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 76 अंकों की तेजी के साथ 25,419 पर पहुंच गया। दरअसल इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान देश की आर्थिक विकास दर 6.8-7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसने बाजार का रुझान पलट दिया। बीएसई पर कुल 4,389 शेयरों की ट्रेडिंग हुई। इसमें से 59% यानी 2,599 शेयर बढ़त पर बंद हुए। बीएसई के मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा 3% उछाल आया। विश्लेषकों के मुताबिक, बाजार की नजर अब 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले आम बजट पर है।

बाजार में तेजी के रुझान की गुंजाइश मजबूत हुई

डेली चार्ट पर बुलिश कैंडल बना है। इसका मतलब है कि आगे तेजी की गुंजाइश ज्यादा और गिरावट की आशंका कम नजर आ रही है। इस बीच सेंसेक्स यदि 82,800 का स्तर लांघने में कामयाब होता है तो नए सिरे से तेजी आ सकती है। ऐसे में यह निकट भविष्य में 83,300 तक जा सकता है।

-श्रीकांत चौहान, इक्विटी रिसर्च हेड, कोटक सिक्युरिटीज

एक फोन से मैनेज होंगे परिवार के सारे 'आधार'

नया आधार एप लॉन्च: घर बैठे बदलें मोबाइल नंबर और पता

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने गुरुवार को नया आधार मोबाइल एप लॉन्च किया। यह एप पुराने वर्जन से ज्यादा एडवांस है और यूजर्स को अपनी डिजिटल पहचान पर अधिक नियंत्रण देता है। सरकार के मुताबिक, यह नेक्स्ट जेनरेशन एप है, जिसे प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

इस नए एप में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अब आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और पता बदलने के लिए आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। यूजर्स ये दोनों काम सीधे अपने स्मार्टफोन से कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया आसान बनेगी। हांलाकि इसके लिए जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे।

प्राइवेसी: सिर्फ जरूरी जानकारी ही शेयर होगी

नए एप में सिलेक्टिव शेयरिंग फीचर दिया गया है। अब यूजर्स पूरा आधार कार्ड दिखाए बिना केवल नाम और उम्र जैसी जरूरी जानकारी साझा कर सकते हैं। होटल या अन्य जगहों पर इससे प्राइवेसी बनी रहेगी और आधार डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा कम होगा।

15 दिन में 13.5% घटी वैल्यू

बिटकॉइन 5 फीसदी टूटा, 84,410 डॉलर तक आया

एजेंसी | न्यूयॉर्क

बिटकॉइन की वैल्यू गुरुवार को 5.43% घटकर 84,410 डॉलर रह गई। यह बीते दिसंबर की शुरुआत से अब तक इसका सबसे कम स्तर है। 1 दिसंबर को यह 85,410 डॉलर पर था। इसके बाद 14 जनवरी को 97,549 तक डॉलर पहुंचा था। तब से अब तक यह 13.47% टूट चुका है। एक साल का रिकॉर्ड देखें तो बिटकॉइन 08 अप्रैल, 2025 को 66,663 डॉलर के निचले स्तर पर था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बिटकॉइन में तेज गिरावट किसी एक कारण से नहीं आई। अमेरिका में ब्याज दर और घटने की उम्मीद कम होना, भू-राजनैतिक जोखिम, ईटीएफ से निकासी और तकनीकी बिकवाली भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

बिजनेस एंकर दुनिया के सबसे अमीर मस्क का फोकस इलेक्ट्रिक कारों से नई तकनीक पर शिफ्ट

टेस्ला की सालाना आय पहली बार 3% घटी, बंद होंगे मॉडल एस और एक्स; इनकी फैक्ट्रियों में बनेंगे 'ऑप्टिमस' ह्यूमनॉइड रोबोट

एजेंसी | ऑस्टिन (टेक्सास)

दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। पहली बार कंपनी की सालाना आय में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। इसका असर मुनाफे पर भी दिखा है, जो पिछले 3 महीनों में 61% तक गिर गया। घटते मुनाफे और बाजार की बदलती मांग को देखते हुए कंपनी के मालिक इलॉन मस्क ने कंपनी के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह बदलने का संकेत दिया है।

टेस्ला अपनी लग्जरी कारों, मॉडल एस और मॉडल एक्स का उत्पादन बंद करने जा रही है। इन कारों को बनाने वाले कैलिफोर्निया प्लांट का इस्तेमाल अब 'ऑप्टिमस' नामक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने मे किया जाएगा। मस्क अपना पूरा ध्यान रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर लगा रहे हैं। चीन की इलेक्ट्रिक कार निर्माता बीवाईडी से पिछड़ने और वैश्विक बाजार में बढ़ती स्पर्धा के बीच मस्क भविष्य की तकनीक पर दांव लगा रहे हैं। वे टेस्ला को एक कार कंपनी नहीं, बल्कि रोबोटिक्स और एआई दिग्गज बनाना चाहते हैं। मस्क का मानना है कि आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट की मांग कारों से कहीं ज्यादा होगी। रोबोट न केवल फैक्ट्रियों में, बल्कि घरेलू कामकाज में भी इंसानों की मदद करेंगे।

टेस्ला आने वाले साल में अपने पूंजी खर्च को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाने वाली है। मस्क के मुताबिक कंपनी लगभग 20 अरब डॉलर (करीब 1.84 लाख करोड़ रुपए) निवेश करने की योजना बना रही है। यह पैसा नई रोबोटैक्सी तकनीक, एआई सुपरकम्प्यूटर और ऑप्टिमस रोबोट के विकास पर खर्च होगा। हालांकि मुनाफा घटने के बावजूद इतना बड़ा खर्च एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन मस्क इसे एक 'एक महान और ऐतिहासिक' भविष्य की तैयारी बता रहे हैं। उनका लक्ष्य कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान फर्म बनाए रखना है।

बड़ा दांव: एआई कंपनी एक्सएआई में लगाए 18,392 करोड़ रुपए

इलॉन मस्क ने अपनी एआई कंपनी एक्सएआई में 2 अरब डॉलर (करीब 18,392 करोड़ रुपए) के भारी-भरकम निवेश का ऐलान किया है। यह निवेश शेयरधारकों की इच्छा और भविष्य की एआई जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। टेस्ला अब सिर्फ एक कार निर्माता कंपनी न रहकर एक हाई-टेक एआई फर्म बनने की राह पर है। मस्क का कहना है कि एआई ही वह तकनीक है जो भविष्य में टेस्ला की कारों को पूरी तरह स्वायत्त या ड्राइवरलेस बनाएगी। यह निवेश कंपनी की तकनीक को अगले स्तर पर ले जाने के लिए जरूरी माना जा रहा है।

इंडिया एनर्जी वीक • ट्रक, बस जैसे वाहनों के लिए एलएनजी पर फोकस

ईवी को कार, दोपहिया जैसे हल्के वाहनों तक सीमित करने के प्रस्ताव पर विचार

सुजीत ठाकुर | बैतूल (गोवा)

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की नीति बदलने पर विचार कर रही है। ईवी को मुख्य रूप से कार, दोपहिया जैसे हल्के वाहनों तक सीमित किया जा सकता है। ट्रक, बस जैसे भारी वाहनों के लिए एलएनजी (तरल प्राकृतिक गैस) को प्रमुख विकल्प बनाया जाएगा। इस बदलाव से ईवी को हल्के सेगमेंट में तेजी से बढ़ावा मिलेगा, जबकि भारी ट्रांसपोर्ट में एलएनजी से उत्सर्जन कम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द तैयार होगा।

इंडिया एनर्जी वीक में नीति निर्माताओं और तेल-गैस सेक्टर की कंपनियों ने माना कि भारी इलेक्ट्रिक वाहनों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रकों और इंटरसिटी बसों के लिए चार्जिंग में लगने वाला समय, सीमित बैटरी रेंज और बैंकों से फाइनेंस की मुश्किलें बड़ी बाधा बन रही हैं।

ट्रक के लिए सस्ते एलएनजी कन्वर्जन मॉडल पर काम

पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कटौती का वादा किया है। इस लिहाज से भारी वाहनों के लिए एलएनजी सेंट्रिक नीति समय की मांग है। एनर्जी वीक में कई कंपनियों के बीच एलएनजी आयात, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और रिटेल नेटवर्क मजबूत करने के समझौते हुए। कुछ कंपनियां ट्रक ऑपरेटरों के लिए सस्ते कन्वर्जन मॉडल पर भी काम कर रही हैं।

एक साल में 4,000 से ज्यादा एलएनजी स्टेशन का प्रस्ताव: केंद्र का लक्ष्य है कि अगले एक साल में स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4,000 से ज्यादा एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं।

कल्पमेधा

अगर आप स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाएंगे, तो सहायता देने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो पहले अपने अहं का नाश कर डालें।

– स्वामी विवेकानंद

समीक्षा के संकेत

हर साल संसद में पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा आमतौर पर इस बात का ब्योरा होती है कि पिछले बजट में देश की अर्थव्यवस्था और अन्य मोर्चे पर सुधार के लिए जो वादे किए गए थे, वे किस हद तक पूरे किए जा सके। यह इसका भी संकेत होता है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार के आर्थिक फैसलों में किन मसलों को प्राथमिकता मिल सकती है। इस लिहाज से देखें, तो वित्त मंत्री ने जो आर्थिक समीक्षा पेश की है, वह देश की परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो रही आर्थिक चुनौतियों के बीच उम्मीद जगाती है, लेकिन यह आने वाले वक्त के जोखिमों के प्रति आगाह भी करती है। समीक्षा में वित्त वर्ष 2026-27 में सकेल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.8 फीसद से 7.2 फीसद के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। विदेशी पूंजी प्रवाह में कमी के कारण रुपए पर प्रतिकूल असर और बीते वर्ष भारतीय मुद्रा में कमजोरी के बावजूद यह अनुमान अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संकेत देता है। हालांकि समीक्षा में विकसित भारत और वैश्विक प्रभाव का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से मजबूत और स्थिर मुद्रा को एक स्वाभाविक जरूरत बताने के समांतर रुपए के मूल्य में गिरावट को हानिकारक नहीं माना गया, क्योंकि यह भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क में इजाफे के असर को कुछ हद तक कम करता है।

दूसरी ओर, यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर यह उम्मीद जताई गई है कि यह भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक, निर्यात और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करेगा। समीक्षा के मुताबिक, अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत को घरेलू वृद्धि को प्राथमिकता देने की जरूरत है और इसके लिए वित्तीय सुरक्षा उपायों और नकदी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जाहिर है, वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर तेजी से बदलते समीकरण और भू-राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए अपने हितों के अनुकूल उपाय करने होंगे। आर्थिक समीक्षा में नवोन्मेष और वैश्विक पहलकदमियों को कमजोर किए बिना दक्षता और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की संभावनाओं को मजबूत करेगा। कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। इस बिंदु पर सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि कृषि निर्यात में व्यापार नीति का उपयोग कीमतों और उत्पादन में अस्थिरता के बीच अल्पकालिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। मगर बार-बार नीतिगत बदलाव आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं।

यह देखने की बात होगी कि समीक्षा में जाहिर इस चिंता के संदर्भ में बजट की क्या दिशा होती है। यों, महंगाई का असर नरम रहने और अगले वर्ष भी चिंता का बड़ा कारण नहीं बनने को लेकर उम्मीद जताई गई है। समीक्षा में अस्थायी कामगारों के लिए काम से जुड़ी शर्तें नए सिरे से तय करने के उद्देश्य से नीति लाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, नागरिकों की सेहत की सुरक्षा के मद्देनजर अधिक वसा और चीनी वाले अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई है और इन उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी दिया गया है। आर्थिक समीक्षा में कई राज्यों में लोकलुभावन घोषणाओं और नकद अंतरण के कारण राजस्व घाटा बढ़ने को लेकर भी चिंता जताई गई। सवाल है कि जिस दौर में मुफ्त सुविधाओं की घोषणा को चुनावी जीत का जरिया बनाने की प्रवृत्ति हावी हो रही हो, उसमें बजट में क्या कोई ऐसी घोषणा सामने आ सकती है, जो इस पर लगाम लगाए!

लापरवाही के जिम्मेदार

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पानी में डूब कर एक युवा इंजीनियर की मौत के मामले में अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवालों के बीच विशेष जांच दल (एसआइटी) ने सरकार को अपनी रपट सौंप दी है। उसने बचाव कार्य में घोर लापरवाही की ओर इशारा करते हुए बारह से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है। यह बेहद दुखद है कि एक नौजवान जान बचाने के लिए करीब डेढ़ घंटे तक गुहार लगाता रहा और बचाव दल मौके पर मूकदर्शक बने रहे। एसआइटी ने इसे गंभीर मानते हुए दमकल, पुलिस, प्राधिकरण और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की भूमिका पर सवालिया निशान लगाए हैं। किसी घटना के तूल पकड़ लेने के बाद सरकार की ओर से जांच और कार्रवाई को लेकर गंभीर दिखने की कोशिश की जाती है, लेकिन कार्रवाई के निशाने पर आमतौर पर निचले स्तर के कर्मचारी आते हैं, जबकि वास्तविक जिम्मेदार लोगों को कठघरे में नहीं किया जाता। इस लिहाज देखें तो नोएडा में युवक के पानी में डूब जाने की घटना के बाद एसआइटी ने जिस तरह बारह अधिकारियों के खिलाफ अपनी रपट दी है, वह समस्या की जड़ों को पकड़ने की कोशिश है।

सवाल है कि सड़क किनारे किसी बड़े गड्ढे में पानी भरा हो, तो उसकी अनदेखी की मूल जिम्मेदारी किस पर जाती है। दरअसल, समस्या और उसके मूल कारणों के साथ-साथ वास्तविक जिम्मेदार लोगों की पहचान और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वक्त की जरूरत है। विडंबना यह है कि निर्माण स्थलों के पास पानी से भरे बड़े गड्ढों से लेकर कई बड़े नाले महीनों तक खुले रहते हैं और वहां अवरोधक, चेतावनी के संकेतक या सुरक्षा घेरा लगाने या अन्य कोई सुरक्षात्मक उपाय करना जरूरी नहीं समझा जाता। क्या इसी अनदेखी का नतीजा कई बार त्रासद नहीं होता? क्या यह उच्च स्तर के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा नहीं होता? हादसे के बाद आमतौर पर सभी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने लगते हैं। ऐसे में एसआइटी ने जिस तरह बारह अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है, वह भविष्य में ऐसी घटनाओं या हादसों को रोकने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण है।

बालिका सुरक्षा के समांतर संघर्ष के मोर्चे

तमाम संघर्षों और बाधाओं को पार करने के बाद आगे चल कर कई बालिकाएं विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष पदों तक पहुंचीं। मगर इतना सब कुछ प्राप्त कर लेने के बावजूद आज भी उनकी सुरक्षा समाज के लिए चिंता का विषय है।

रचना सिद्धा

हमारे देश में बेटियों के जीवन और संरक्षण के लिए सरकार और समाज के स्तर पर तमाम कवायदें होती रही हैं और इसके मद्देनजर समय-समय पर विशेष आयोजन होते रहे हैं। मगर ऐसा क्यों है कि आज भी बच्चियों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकार से जुड़े लक्ष्य अधूरे हैं? लैंगिक समानता का विमर्श तब तक अधूरा है, जब तक बालिकाओं की दशा और दिशा का ईमानदारी से मूल्यांकन नहीं होता। महज दिवस और समारोह मना लेने भर से बच्चियों के संपूर्ण विकास का दावा नहीं किया जा सकता। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के सात दशक बाद लाखों बालिकाओं की शिक्षा अधूरी रह जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उनके स्वास्थ्य की जिस तरह से उपेक्षा होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। उचित पोषण के अभाव में उन्हें कई बीमारियां घेर लेती है। चिंता की बात है कि तमाम योजनाओं के बावजूद सामाजिक सोच में आज भी बदलाव नहीं आया। समाज में बालिकाओं को लेकर दोहरी मानसिकता रही है। घर से लेकर बाहर तक उनसे भेदभाव होता है। आज भी भ्रूण हत्या एक बड़ी चुनौती है। बालिका किसी तरह बच जाती है, तो आगे चल कर उसे शिक्षा से वंचित रखने की साजिश होती है। हालांकि जागरूकता बढ़ने से लोग बेटा-बेटी को समान मानने लगे हैं। शहरों में तस्वीर जरूर बदली है, लेकिन ग्रामीण और वंचित तबकों में बालिकाएं अब भी उपेक्षित हैं।

आज बालिकाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा। लड़कियां खेलों में स्वर्ण पदक जीतने से लेकर अंतरिक्ष में जाने तक के लिए तैयार हो रही हैं। तमाम संघर्षों और बाधाओं को पार करने के बाद आगे चल कर कई बालिकाएं विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष पदों तक पहुंचीं। मगर इतना सब कुछ प्राप्त कर लेने के बावजूद आज भी उनकी सुरक्षा समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकडों पर नजर डालें, तो भारत में 2023 में महिलाओं से हुए अपराध के करीब 4.48 लाख मामले दर्ज किए गए जो 2022 के मामलों से अधिक था। वास्तविकता यह भी है कि ब्यूरो के आंकड़े केवल पुलिस में दर्ज कराए गए मामलों को दर्शाते हैं। जबकि पारिवारिक हिंसा, उत्पीड़न और घरेलू परेशानियों का बहुत बड़ा हिस्सा अक्सर दर्ज नहीं होता। लोगों के अनुभव बताते हैं कि घरेलू हिंसा और परिस्थितिजन्य डर के कारण कई मामलों की शिकायत ही नहीं की जाती। कई मामलों में तो विभिन्न प्रकार के डर, दबाव और धमकियों की वजह से की गई शिकायत भी वापस ले ली जाती है। इनके अलावा, मौजूदा समय में डिजिटल और आनलाइन हिंसा भी तेजी से समाज में जड़ें जमा रही हैं। इसे रोकने के लिए कानून और सुरक्षा प्रणालियां विकसित नहीं हुई हैं, जिनका खमियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है।

केंद्र और राज्य सरकारें अपनी ओर से इस समस्या के निराकरण के लिए कई कदम उठा रही हैं। निर्भया अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसे कानून और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, निर्भया फंड, महिला हेल्प लाइन, महिला थाने और 'पिंक पेट्रोलिंग' जैसी योजनाएं ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। मगर लड़कियों की

सुरक्षा केवल कानून और योजनाएं बना देने भर से नहीं होगी, बल्कि कड़ाई से इनका अनुपालन भी उतना ही जरूरी है, जिससे लड़कियों की सुरक्षा पर हमला करने वालों में भय व्याप्त हो। एक बहुत बड़ा दायित्व है लड़कियों के प्रति सामाजिक सोच को लेकर है। आज भी जिस तरह की सोच समाज में

> **इस समय लड़कियों की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ-साथ सामाजिक चेतना तथा जिम्मेदारी का सवाल भी बन चुका है। सभी कानूनों और योजनाओं पर सही तरीके से अमल हो और इनका समुचित उपयोग हो, इसके लिए हम सभी को उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। कई स्तरों पर इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। बेटियों के पास खुल कर अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। जिस तरह बेटे को बिना किसी झिझक या भय के अपनी बात कहने का अधिकार है, वही अधिकार बेटी को भी बिना किसी शर्त देना होगा, जिससे उसके भीतर आत्मविश्वास भरा जा सके।**

लड़कियों को लेकर आमतौर पर बनी हुई है, उसे स्वस्थ सोच तो कतई नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थितियों में परिवर्तन आया है, परंतु अभी भी परिवर्तन का दायरा बहुत सीमित है और अधिकांश लड़कियों को इस परिवर्तन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है।

यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सरकारी, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रयासों में समन्वय और संयोजन बहुत जरूरी है। इस समय लड़कियों की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ-साथ सामाजिक चेतना तथा जिम्मेदारी का सवाल बन चुका है। सभी कानूनों और योजनाओं पर सही तरीके से अमल हो और इनका समुचित उपयोग हो, इसके लिए हम सभी को उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। कई स्तरों पर इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। बेटियों के पास खुल कर अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। जिस तरह बेटे को बिना किसी झिझक या भय के अपनी बात कहने का अधिकार है, वही अधिकार बेटी को भी बिना किसी शर्त देना होगा, जिससे उसके भीतर आत्मविश्वास भरा जा सके। किसी भी तरह का भेदभाव, बेटियों के हौसले को धीरे-धीरे खत्म कर सकता है। जिम्मेदारियों से लेकर घर के काम तक, भावनाओं को साझा करने से लेकर आर्थिक फैसले लेने तक, सभी कामों का बंटवारा बराबरी के स्तर पर करना होगा।

सबसे जरूरी बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वह है लड़कियों की सुरक्षा का मामला। लड़कियों की सुरक्षा को खतरा किससे है, हमें यह समझना होगा। बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर हमें अपने लड़कों से खुल कर बात करनी होगी। उन्हें ऐसे संस्कार देने होंगे जिसमें वे लड़कियों को एक वस्तु या कमजोर तथा असहाय नहीं, बल्कि बिल्कुल अपनी ही तरह अपनी ही बराबरी का एक इंसान समझें। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, लड़कियों की सुरक्षा का मसला काफी हद तक सुलझ जाएगा। अभी भी हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ गलत किया, तो माता-पिता उसे बचाने में जुट जाते हैं। अव्वल तो उस लड़के की परवरिश में कहीं तो कोई कमी रही कि उसने लड़की को इंसान नहीं समझा और जब उसने गलती की, तो उसे सजा दिलाने के बजाय उसे बचाने की कोशिश होने लगती है। यह स्थिति ठीक नहीं है। बच्चे हैं, उम्र ही ऐसी है और इस उम्र में गलतियां हो ही जाती हैं, जैसे जुमले लड़कियों की सुरक्षा के और अधिक खतरे की स्थिति तैयार करते हैं।

परिवार में हमें ऐसा माहौल तैयार करना होगा जिसमें लड़कियों को हर दृष्टि से लड़कों के बराबर अधिकार और स्थान मिले। बालिकाएं समाज की आधारशिला हैं। वे केवल परिवार और समाज की ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति का भी वाहक होती हैं। ऐसे में उनके साथ समाज में हो रहा भेदभाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है। आज जरूरत है हमें बालिकाओं को प्रोत्साहन देने और अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की, तभी सही मायने में देश विकास कर पाएगा। शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और पोषण, लैंगिक भेदभाव का अंत, सुरक्षा और संरक्षण तथा समान अवसर जैसे कई क्षेत्र हैं, जिनमें लड़कियों के लिए काम किए जाने की आवश्यकता है। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना होना चाहिए जहां हर लड़की को सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर मिले। साथ ही, हर लड़की अपने सपनों की उड़ान भरते हुए आकाश की ऊंचाइयों को छूने का हौसला रख सके।

सहयोग की गरिमा

सुप्रिया सत्यार्थी

दुनिया मेरे आगे

अक्सर हम समाज सेवा, देश की उन्नति और दूसरों के दुख में हाथ बंटाने की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ये बातें सुनने और कहने में बहुत गर्व का अनुभव कराती हैं, लेकिन क्या यह सब तब भी उतना ही सच्चा और प्रभावी रहता है, जब हम अपने ही परिवार के किसी सदस्य की सिसकियों को अनसुना कर देते हैं? क्या यह संभव है कि हम समाज के लिए ईमानदारी से कार्य करें, जबकि अपने ही घर के लोगों की तकलीफों को समझने और उनके सुख-दुख में सहभागी बनने का समय हमारे पास नहीं हो? सच यह है कि अगर हम अपने परिवार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं, उनके सुख-दुख को महसूस नहीं कर पाते, तो हमारी समाज सेवा और दूसरों के प्रति दया-भाव महज एक दिखावा है। यह असल में उस वास्तविकता से मुंह मोड़ने जैसा है, जिसे हम स्वयं समझना और स्वीकार करना ही नहीं चाहते। सवाल है कि परिवार और संवेदना के साथ गहरे जुड़े होने की अपेक्षा पालने वाले समाज में एक दूसरे के बीच इस अदृश्य दूरी की संस्कृति कैसे और क्यों विकसित हुई?

आज का दौर सोशल मीडिया का है, जहां हर कोई दूसरों के लिए अच्छा दिखने की होड़ में लगा हुआ है। लोग समाज सेवा, इंसानियत और बड़े-बड़े बलिदानों की बातें करते हैं। यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे दूसरों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कभी-कभी वे मदद भी करते हैं, लेकिन क्या यह मदद वास्तव में सच्चे दिल से होती है? या यह केवल अपनी छवि बनाने के लिए की जाती है? यह देखकर दुख होता है कि जो लोग दूसरों के लिए स्वयं को त्यागने की बातें करते हैं, वे अपने ही घर के उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं, जो उनके सबसे करीबी होते हैं। मां-बाप, भाई-बहन, जीवन-साथी- इनके दुख, पीड़ा और संघर्ष को वे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति मदद की गुहार लगाता है, वे तुरंत उसे अपना समय, पैसा और ऊर्जा देने को तैयार हो जाते हैं। किसी के लिए कुछ किए जाने या किसी की मदद करने के बदले कुछ अपेक्षा करना या फिर इस शर्त पर किसी की मदद करना क्या मदद की गरिमा को कम नहीं करता? सहायता के बदले में कोई लाभ मिलने की अपेक्षा मानवीय संवेदना की ईमानदारी को कठघरे में खड़ा करता है। इस तरह की सहायता को दरअसल सौदा कहना ज्यादा बेहतर होगा।

> **समाज सेवा और परोपकार महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन वे तब तक अधूरे हैं, जब तक हम अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से नहीं निभाते। अगर हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समर्पण नहीं दिखा सकते, तो बाहरी दुनिया के लिए किया गया हर प्रयास केवल एक छलावा बनकर रह जाता है।**

प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी प्राथमिकताएं गलत हो चुकी हैं? क्या हमारी सोच इस हद तक बदल गई है कि हमें अपने अपनों का दर्द महसूस ही नहीं होता? जो लोग दिन-रात हमारे लिए काम करते हैं, हमारे हर सुख-दुख में साथ रहते हैं, उनकी अहमियत हमें क्यों नहीं समझ में आती? मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया में व्यस्तता ने हमारे रिश्तों को गहराई से प्रभावित किया है। दिन भर स्क्रीन पर उलझे रहना, आनलाइन अपनी 'परफेक्ट इमेज' यानी मुकम्मल छवि बनाने की कोशिश और दूसरों से तारीफें पाना हमारी प्राथमिकता बन गई है। परिवार, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारे जीवन की नींव है, कहीं पीछे छूटता जा रहा है। एक पल के लिए भी याद रखना जरूरी क्यों नहीं समझते कि हम अपनी जीवन-यात्रा में आज जहां तक का भी सफर पूरा कर सके हैं, उसमें परिवार और माता-पिता की सबसे अहम भूमिका रही है?

हम अपने घर के उन रिश्तों को क्यों नहीं गले लगाते, जिन्होंने हमें हमेशा सहारा दिया है? क्यों हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बजाय उन्हें अकेला महसूस करने देते हैं? क्या यह स्वार्थ है, या समाज में अपनी छवि चमकाने की झूठी होड़? यह कहना गलत नहीं होगा कि समाज सेवा और दूसरों की मदद करना जरूरी है। यह हमारी इंसानियत का प्रतीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। वे लोग, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उनके दर्द को समझना और उनके सुख-दुख में सहभागी बनना हमारी पहली जिम्मेदारी है। हमें अपने परिवार के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। यह दिखाना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। उनके दुख के समय उन्हें गले लगाना, उनके संघर्ष में साथ देना और उन्हें यह विश्वास दिलाना कि वे हमारे लिए कितने खास हैं, यह सब हमारी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है। यह वह आधार है, जो हमें मजबूत बनाता है। यह वह जड़ है, जिससे हमारा जीवन पनपता है। अगर हम इस जड़ को ही भूल जाएंगे, तो हमारी बाकी सभी उपलब्धियां खोखली और अस्थायी सिद्ध होंगी।

समाज सेवा और परोपकार महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन वे तब तक अधूरे हैं, जब तक हम अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से नहीं निभाते। परिवार का अर्थ बहुत व्यापक है, लेकिन इसके बिना जीवन अधूरा है। अगर हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समर्पण नहीं दिखा सकते, तो बाहरी दुनिया के लिए किया गया हर प्रयास केवल एक छलावा बनकर रह जाता है। सच्चा इंसान वही है, जो अपने परिवार और समाज- दोनों के प्रति संतुलन बनाए रखता है तथा जो अपने परिवार को यह एहसास दिला सके कि वे उसके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण हैं और समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करे। यही वास्तविकता है और यही जीवन की सच्ची उपलब्धि।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

मणिपुर के जख्म

'शांति के खिलाफ' (संपादकीय, 24 जनवरी) पढ़ा। मणिपुर के चुराचांदपुर में थोड़े दिनों की शांति के बाद बीते दिनों एक युवक के अपहरण और हत्या के बाद फिर से भड़का उपद्रव इस बात का संकेत है कि यह राज्य अब भी सामाजिक-राजनैतिक संकट से बाहर नहीं निकल पाया है। पिछले दो वर्षों से अधिक समय से जारी हिंसा ने कानून व्यवस्था को केवल कमजोर ही नहीं किया, बल्कि आपसी विश्वास को भी लगभग समाप्त कर दिया है। यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं है, बल्कि उस असफल शांति प्रक्रिया पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न है, जिसके भरोसे हाल के महीनों में स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा था। अपहरण और हत्या जैसे जघन्य अपराध ये दर्शाते हैं कि हथियारबंद समूह आज भी सक्रिय हैं और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कई इलाकों में प्रभावी तरीके से कायम नहीं हो सकी है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि हर नई हिंसक घटना पुराने घावों को फिर से हरा कर देती है। प्रतिक्रिया में होने वाला उपद्रव, बंद और आगजनी मणिपुर के नागरिकों को दोबारा भय और असुरक्षा के दलदल में धकेल देते हैं। इससे विकास, शिक्षा और सामान्य जीवन लगातार बाधित हो रहा है।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

आत्मनिर्भरता के बजाय

भारतीय राजनीति में मुफ्त की रेवड़ियां एक जटिल समस्या बन चुकी हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। राजकोष का दुरुपयोग रोकना जरूरी है। लोकलुभावन योजनाएं चुनाव जीतने के लिए होती हैं। इससे निर्धन और वंचित वर्ग आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है, बल्कि उनमें अकर्मण्यता ही पैदा होती है। निर्वाचन आयोग को चुनाव घोषणापत्रों की वित्तीय विवेचना का अधिकार मिलना चाहिए। उसे ऐसी पार्टियों के चुनाव में भाग लेने पर रोक लगाना चाहिए। साथ ही नागरिकों को भी चाहिए कि ऐसी पार्टियों से सवाल करें। इस मुद्दे को उचित मंच पर उठाएं। तभी ऐसे दल हतोत्साहित होंगे। हालांकि आदमी की मानसिकता ऐसी रहती है कि बिना श्रम के पैसे आ जाएं, लेकिन ऐसी लोकलुभावन घोषणाओं को चुनाव जिताने के लिए एक तरह से रिश्वत ही मानना चाहिए। जवाबदेह पार्टियों को ऐसी घोषणाओं से दूर रह कर योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए। मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं के विरुद्ध नियम बनना चाहिए।

– भगवानदास छारिया, इंदौर

मासूमों की चुप्पी

बच्चों को डराना-धमकाना एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ताने मारने, अपमान करने, डराने, शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर करने जैसी शिकायतें मिलती रहती हैं। इससे बच्चों के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। कई बार यह समस्या इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे अवसाद, भय और आत्मग्लानि का शिकार हो जाते हैं। माता-पिता को बच्चों से नियमित संवाद बनाए रखना चाहिए। बच्चों के व्यवहार में अचानक आए बदलाव, जैसे उनकी चुप्पी, डर, स्कूल न जाने की इच्छा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्हें यह भरोसा देना जरूरी है कि उनकी बात सुनी जाएगी और दोषी ठहराने के बजाय उनका साथ दिया जाएगा। हर स्कूल में इस पर नीति होनी चाहिए, जिसे केवल कागजों में नहीं, व्यवहार में लागू किया जाए। शिकायत करने वाले बच्चों की पहचान गोपनीय रखी जाए, ताकि वे अपनी बात कह सकें। बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देना जरूरी है।

– राकेश खुडिया, श्रीगंगानगर

जीत का रास्ता

आज के दौर में संघर्ष को भी इतनी रूमानियत से भर दिया गया है कि हम अपनी छोटी-छोटी जीत को भी पहचानना भूल जाते हैं। यह सिखा दिया गया है कि भीड़ से अलग कैसे चला जाए, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि संघर्ष की जीत सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होती। असली जीत तो उस रास्ते में बिखरी हुई वे छोटी सफलताएं होती हैं, जो हमें हर दिन थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और अनुभवी बनाती हैं। यह याद रखना जरूरी है कि जहां आज हम खड़े हैं, वहां पहुंचने का सपना हमने कभी देखा था। थकान के बावजूद सुबह उठ जाना, दिन भर की अपनी प्राथमिकता में एक काम पूरा कर लेना, बिना तालियों के भी सही काम करना, ये सब भी जीत हैं। मदद मांगने की हिम्मत जुटा लेना, डर के बावजूद सच बोल देना, खुद को दोषी ठहराने से रुक जाना और उम्मीद के लिए कोई छोटा-सा कारण ढूंढ़ लेना, ये पल हमारी जीत हैं।

– खुशी जायसवाल, जम्मू

दुनिया के लिए आशा की किरण बनकर उभर रहा भारत : मोदी

राकेश शर्मा
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत दुनिया के लिए आशा की किरण बनकर उभर रहा है। साथ ही उन्होंने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का जिक्र करते हुए कहा कि यह महत्त्वाकांक्षी भारत के लिए है और देश के विनिर्माताओं को इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी क्षमताएं बढ़ानी चाहिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन मीडिया से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 'रिफार्म एक्सप्रेस' पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सुधारों के क्रियान्वयन में संसद सदस्यों के सकारात्मक योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके आलोचक भी सरकार की अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं और सुधारों की यह परंपरा अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ भी जारी रहेगी। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनसांख्यिकी दुनिया के लिए बड़ी उम्मीद प्रदान करती है। लोकतंत्र के इस मंदिर में भारत के पास शक्ति, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से लिए गए फैसलों के लिए सम्मान का संदेश देने अवसर है, संदेशों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। वर्तमान समय व्यवधान उत्पन्न करने का नहीं, बल्कि समाधान खोजने का है। यह बजट सत्र 21वीं सदी के पहले चतुर्थांश के समापन और अगले चतुर्थांश की शुरुआत का प्रतीक है।

उन्होंने कहा, 'वर्ष की शुरुआत बेहद सकारात्मक रही है और आत्मविश्वास से भरा भारत दुनिया के लिए आशा की किरण और आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के नए चतुर्थांश की शुरुआत में भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारत के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और आगे की आशाजनक दिशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा, 'यह समझौता महत्त्वाकांक्षी भारत, आकांक्षी युवाओं और आत्मनिर्भर भारत के लिए मुक्त व्यापार का प्रतीक है।' उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय विनिर्माता इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाएंगे।

नाराजगी की खबरों के बीच खरगे और राहुल से मिले थरूर, बोले

सब कुछ ठीक, हम साथ-साथ हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने नाराजगी की खबरों के बीच गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की तथा कहा कि सब कुछ ठीक है और सब एक साथ हैं। खरगे के संसद भवन स्थित कार्यालय में यह मुलाकात हुई।

थरूर ने इस मुलाकात को बहुत अच्छी, सार्थक और सकारात्मक करार दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने केरल के अपने इस वरिष्ठ नेता की नाराजगी दूर करने का प्रयास ऐसे वक्त किया है, जब कुछ महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, जो पार्टी के लिए महत्त्वपूर्ण है। केरल में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव संभावित है। पार्टी 2016 से राज्य में विपक्ष की भूमिका में है। कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात के बाद थरूर ने संवाददाताओं से कहा कि अपनी पार्टी के दो नेताओं- नेता प्रतिपक्ष (राहुल गांधी) और कांग्रेस अध्यक्ष (खरगे)- के साथ बात की।

कांग्रेस नेतृत्व ने केरल के अपने इस वरिष्ठ नेता की नाराजगी दूर करने का प्रयास ऐसे वक्त किया है, जब कुछ महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है, जो पार्टी के लिए महत्त्वपूर्ण है।

हमारी बातचीत बहुत अच्छी, सार्थक, सकारात्मक रही। सब ठीक है और हम सब एक साथ हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह खुश हैं और अब चुनाव प्रचार करेंगे तो उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है, मैंने कहां प्रचार नहीं किया है?

मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के बारे में पूछे जाने पर तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य ने कहा कि नहीं, उस बारे में कभी बात नहीं हुई। मुझे किसी भी चीज के लिए उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले से ही मैं सांसद हूं और मेरे ऊपर तिरुवनंतपुरम के अपने मतदाताओं का विश्वास है तथा मुझे संसद में उनके हितों का ध्यान रखना है, यही मेरा काम है।

बाद में थरूर ने 'एक्स' पर राहुल गांधी और खरगे के साथ एक तस्वीर साझा की और कहा कि आज कई विषयों पर गर्मजोशी से चर्चा हुई और सार्थक चर्चा के लिए खरगे जी तथा राहुल गांधी जी का धन्यवाद। भारत के लोगों की सेवा के लिए हम सब एकसाथ हैं। थरूर पिछले कुछ समय से नाराज थे और इसके चलते बीते 23 जनवरी को केरल से संबंधित बैठक में शामिल नहीं हुए थे। थरूर के करीबी सूत्रों ने कहा था कि वह बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह इस बात से 'आहत' थे कि राहुल गांधी ने हाल में कोच्चि में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर उनके मौजूद होने के बावजूद उनके नाम का उल्लेख नहीं किया और राज्य के नेताओं द्वारा बार-बार उन्हें 'दरकिनार' करने की कोशिश की जा रही है।

थरूर के बयानों और लेखों की हाल के दिनों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी आलोचना की थी। पिछले साल भारत-पाकिस्तान संघर्ष और पहलगाम हमले के बाद राजनयिक संपर्क के प्रयासों को लेकर उनकी टिप्पणियों पर विवाद खड़ा हो गया था। उनकी टिप्पणियां कांग्रेस के रुख से भिन्न थीं और पार्टी के कई नेताओं ने उनके इरादों पर सवाल उठाते हुए उन पर कटाक्ष किया था। हालांकि, थरूर ने कहा है कि विदेश नीति पर रुख में कोई भिन्नता नहीं है।

उत्तर प्रदेश में विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों का होगा पुनर्वास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास को गुरुवार को मंजूरी दे दी है। वरिष्ठ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह परिवार फिलहाल मेरठ जिले में झील की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।

मंत्रिमंडल बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अभी मेरठ की मवाना तहसील के नगला गोसाई गांव में रह रहे इन परिवारों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के पालन में दूसरी जगह बसाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुनर्वास योजना के तहत, 50 परिवारों को कानपुर देहात जिले की रसूलबाद तहसील के भैंसया गांव में पुनर्वास विभाग के नाम पर दर्ज 11.1375 हेक्टेयर (27.51 एकड़) जमीन पर बसाया जाएगा, जबकि बाकी 49 परिवारों को ताजपुर तरसौली गांव में 10.530 हेक्टेयर (26.01 एकड़) जमीन पर बसाया जाएगा। हर परिवार को 30 साल के पट्टे पर 0.50 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसे हर बार 30 साल के लिए दो बार बढ़ाया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम पट्टा अवधि 90 साल होगी। पट्टा तय प्रीमियम या पट्टा किराए के भुगतान पर दिया जाएगा। खन्ना ने कहा कि मंत्रिमंडल ने नियोजित शहरी विकास के मकसद से शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दी है। यह नीति भवन मानचित्र की मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाएगी ताकि नियमों का पालन हो सके, साथ ही संशोधित विकास शुल्क भी लागू किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने बरेली और मुरादाबाद में साइंस पार्क और तारामंडल की स्थापना को भी मंजूरी दी है।

शोक

बारामती में अपने पिता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान पार्थ व जय पवार।

राजकीय सम्मान के साथ

अजित पवार को दी गई अंतिम विदाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में शोकाकुल लोगों ने गुरुवार को अपने प्रिय नेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार को अंतिम विदाई दी। पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम विदाई के लिए आए लोगों से खचाखच भरे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पवार के बेटों पार्थ और जय ने चिता को मुखाग्नि दी।

गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नवीन समेत कई अंतिम संस्कार में हुए शामिल।

उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाईं, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और हर ओर 'अजित दादा अमर रहे' के नारे गूंज रहे थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, मुरलीधर मोहोल, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार (जो अजित पवार के चाचा हैं) और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन 66 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस दौरान बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उपस्थित थे। बारामती पवार परिवार का गृहनगर है, जो पुणे से 100 किलोमीटर दूर है।अजित पवार के अंतिम संस्कार के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए और जब उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनके गांव काटेवाडी से विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में लाया गया तो लोगों ने 'अजित दादा अमर रहे' के नारे लगाए।

सुनेत्रा पवार जब अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दे रही थीं तो बारामती से राकांपा (शरद गुट) की लोकसभा सदस्य एवं उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले अपनी चाची (सुनेत्रा पवार) के साथ खड़ी और उन्हें सांत्वना देती दिखीं। इस दौरान राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल भी उपस्थित थे। उधर, राकांपा नेताओं ने उनकी पत्नी सुनेत्रा को राज्य मंत्रिमंडल में स्थान देने की मांग उठाई है। वहीं, शरद गुट ने विलय के प्रयासों का स्वागत किया है।

अमरनाथ यात्रा से पहले जोखिम वाले क्षेत्रों की होगी पहचान

मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को दिए संवेदनशील स्थल चिह्नित करने के निर्देश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

दक्षिण कश्मीर में हिमालयी क्षेत्र में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले दोनों मार्गों पर आपदा की दृष्टि से संवेदनशील और जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और निशानदेही अमरनाथ यात्रा से पहले की जाएगी। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने एक बैठक में अनंतनाग और गांदरबल के उपायुक्तों तथा संबंधित मंडलीय प्रशासन को इन क्षेत्रों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि उच्च जोखिम वाले, आपदा की दृष्टि से संवेदनशील और कमजोर क्षेत्रों में तंबू और अस्थायी ढांचों सहित किसी भी प्रकार की सुविधाएं स्थापित न की जाएं। ये निर्देश अनंतनाग जिले के पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के 14 किलोमीटर लंबे लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाले बालटाल मार्ग पर लागू होंगे। अमरनाथ यात्रा आमतौर पर जुलाई-अगस्त में होती है, जिसमें देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बुधवार को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) की 15वीं उच्चस्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और हितधारकों से कहा कि वार्षिक यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से काफी पहले सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने अग्रिम योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर देते हुए पर्यटन विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को आगामी एक माह के भीतर सभी निविदा, खरीद और अनुबंध संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से सेवा प्रदाताओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक स्थान पर तीर्थयात्रियों और सेवा कर्मियों के लिए पर्याप्त, उपयुक्त और आवश्यक सुविधाएं मौजूद हों।

उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और उपलब्ध कार्य अवधि का सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह किया, ताकि यात्रा की निर्धारित तिथियों से पहले सभी आधारभूत ढांचे और सेवाएं पूरी तरह तैयार हो सकें। अधिकारियों के अनुसार, स्वास्थ्य तैयारियों को भी एक प्रमुख प्राथमिकता बताया गया। इसके तहत चंदनवाड़ी और बालटाल स्थित आधार शिविरों के अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सकीय स्टाफ की तैनाती और उनकी पूर्ण कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार को उखाड़ फेंकने संबंधी आरोपों को वांगचुक ने नकारा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

जोधपुर की केंद्रीय जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उन आरोपों का खंडन किया कि उन्होंने 'अरब स्प्रिंग' की तरह सरकार को उखाड़ फेंकने वाला बयान दिया था। कार्यकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें आलोचना और विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है।

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ के समक्ष यह तर्क दिया कि पुलिस ने हिरासत में भेजने वाले प्राधिकारी को गुमराह करने के लिए चुनिंदा वीडियो का सहारा लिया है। सिब्बल ने ताया कि वीडियो देखिए। पुलिस के मुताबिक, वे कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार राज्य का दर्जा नहीं देगी, तो वह अरब स्प्रिंग की तरह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वह ऐसा नहीं कह रहे हैं। मैं (वीडियो को) लिपिबद्ध कर दूंगा। अरब स्प्रिंग सरकार विरोधी प्रदर्शनों, विद्रोहों व सशस्त्र बगावत की एक शृंखला है जो 2010 व 2018 के बीच पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैल गई थी।

सिब्बल ने इस बात का भी खंडन किया कि वांगचुक ने एक साक्षात्कार में कहा था कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो लद्दाख के लोग युद्ध के दौरान भारतीय सेना की मदद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गलत, यही इस मामले की समस्या है। उन्होंने हिरासत में भेजने वाले प्राधिकारियों को गुमराह किया है।

पेज 1 का बाकी

खतरनाक प्रभाव पड़ेगा और समाज में विभाजन पैदा होगा

न्यायालय में 2019 से एक याचिका लंबित है। जिसमें 2012 के नियमों को चुनौती दी गई है, जिन्हें अब 2026 के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 2012 के नियमों की जांच करते समय हम इससे अधिक पीछे नहीं जा सकते।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि महाधिवक्ता, कृपया इस मामले की जांच के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति गठित करने के बारे में सोचें ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची ने कहा कि अनुच्छेद 15(4) राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। लेकिन हम आपकी बात समझते हैं, प्रगतिशील कानून में प्रतिगामी रुख क्यों होना चाहिए? मुझे उम्मीद है कि हम अमेरिका जैसे पृथक विद्यालयों में नहीं जाएंगे, जहां अश्वेत और श्वेत अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बिल्कुल। इस तरह की स्थिति का फायदा उठाया जा सकता है।एक वकील ने कहा कि अगर मैं सामान्य वर्ग से हूं और किसी कालेज में नया जाता हूं, वहां वरिष्ठ रैगिंग करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई उपचार नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश ने आश्चर्य जताया कि क्या सामान्य वर्ग कवर नहीं है? वकील ने कहा- बिलकुल नहीं। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि हमने नियमों के 3सी की परिभाषा को चुनौती दी है। जाति आधारित भेदभाव किया गया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भेदभाव समाज में खाई को बढ़ावा देने वाला है।प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम समानता के अधिकार पर गौर कर रहे हैं। यह नियम खरे उतरते हैं या नहीं। आप उस पर दलील दें। जैन ने कहा कि अनुच्छेद 14 में वर्गीकरण को स्पष्ट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इस पर फैसले भी हैं जिनमें स्पष्टीकरण है।

बलात्कार के मामले का आरोपी कोच बनाकर भेजा गया जार्डन

नहीं लिया है और इससे पहले उन्हें प्रतिरूपण (असली पहचान छिपाकर या झूठी पहचान बनाकर फायदा उठाना) से संबंधित एक मामले में महासंघ ने 2022-2024 तक निलंबित कर दिया था। ताजा विवाद को लेकर न तो खेल मंत्रालय और न ही महासंघ ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान दिया है। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक, सिंह ने जमानत की अपील में परिवार में एक महिला के कैंसर होने का हवाला दिया। उन्हें पहले भी कई बार जमानत मिल चुकी है।

अपील में उनका तर्क था कि महिला के माता-पिता नहीं हैं। और न ही उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो उनकी देख-रेख और इलाज करा सके। दूसरी ओर एजंसी के मुताबिक, उनके चयन पर एक जूनियर राइडर के पिता ने आपत्ति जताई और इस संबंध में विश्व संस्था आइटीपीएफ को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने बताया कि सोनीपत में तरसेम सिंह वरैच के खिलाफ दो महिलाओं द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर एफआइआर दर्ज है। उन्होंने लिखा, 'अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को देखते हुए कि संबंधित व्यक्ति जमानत पर बाहर है, खेल अधिकारी उन्हें देश से बाहर जाने और देश का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?' इस पर आइटीपीएफ ने ईएफआइ से उचित कार्रवाई करने को कहा है।

आइटीपीएफ के ईमेल में कहा गया, 'हम अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए और दी गई जानकारी की जांच के बाद उचित कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही प्रतियोगियों की सुरक्षा और खेल की गरिमा बनाए रखने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए।' सूत्रों के अनुसार आइटीपीएफ ने कुछ अन्य प्रतिभागियों की आपत्ति के बाद जार्डन स्पर्धा के साथ चल रहे जजों के कोर्स में भी तरसेम को शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।महासंघ ने पिछले हफ्ते खिलाड़ियों की सूची जारी की थी। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। महासंघ ने खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी पर भेजा है। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय टेंट पेगिंग विश्व कप क्वालीफायर में भाग लेने के लिए गए सदस्यों की सूची घुड़सवारी महासंघ से नहीं मिली। महासंघ मनमानी करता है।

इस बारे में भारतीय घुड़सवारी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष जगत सिंह का दावा है कि महासंघ ने दल भेजने से पहले मंत्रालय को ई-मेल से सूचित कर दिया था, जिसका खेल मंत्रालय के सूत्र ने खंडन किया है। खिलाड़ियों की सूची को लेकर महासंघ के महासचिव सेवानिवृत्त कर्नल जयवीर सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों के चयन के समय मुझे दूर रखा गया। मेरा इस मामले में कोई दखल नहीं है। बहरहाल, खेल मंत्रालय ने लंबे समय से चले आ रहे प्रशासनिक और नियमों के पालन में विफलताओं को लेकर ईएफआइ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। गौरतलब है कि ईएफआइ जनवरी में हुई राष्ट्रीय टेंट पेगिंग चैंपियनशिप के बाद तय चयन ट्रायल आयोजित करने में विफल रही। लगातार कई दिनों तक संभावित खिलाड़ियों की अलग-अलग और विरोधाभासी सूचियां जारी की गई, जिसके बाद चयन मानदंडों का पालन न होने को लेकर राइडरों ने आपत्ति जताई। इसके बाद ट्रायल रोक दिए गए और खिलाड़ियों को अपने घोड़ों के साथ शिविर छोड़ने को कहा गया।

ईएफआइ ने 16 जनवरी को खराब मौसम का हवाला देते हुए आइटीपीएफ को सूचित किया कि भारतीय टीम क्वालीफायर में हिस्सा नहीं ले पाएगी। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इस अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि पुष्टि के बाद हटने पर जुर्माना लगेगा और इसके बाद पेनल्टी का बिल भी भेजा गया। इसके एक दिन बाद ईएफआइ ने चार खिलाड़ियों की संशोधित सूची तरसेम सिंह के नाम के साथ आइटीपीएफ को भेजी। इसी बीच, खेल मंत्रालय ने 28 जनवरी को ईएफआइ को विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के तहत दी गई छूट की शर्तों का पालन न करने पर जवाब मांगा गया है।

ब्लैक बाक्स मिला, पता चलेगी हादसे की वजह

होती है। साथ ही, भविष्य में विमान हादसों को रोकने में भी यह कारगर सिद्ध होता है।मंत्रालय ने कहा कि वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) द्वारा इस दुर्घटना की जांच तेजी से की जा रही है। इस हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। एएआइबी को 2,250 किलोग्राम या उससे अधिक कुल भार वाले विमानों और टर्बोजेट विमानों से जुड़ी सभी दुर्घटनाओं व गंभीर घटनाओं की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। बुधवार को एएआइबी को हादसे की जांच का जिम्मा सौंपा गया था।

नागर विमानन मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हादसे की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बाक्स बरामद कर लिया गया है। दिल्ली स्थित 'वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा संचालित 'लियरजेट 45' विमान बारामती की हवाई पट्टी पर उतरने के दूसरे प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी और परिचारक, साथ ही चालक दल के सदस्य पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर और प्रथम अधिकारी शांभवी पाठक की मृत्यु हो गई थी।

मंत्रालय ने कहा कि एक पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बारामती के पास हुई इस घटना के तुरंत बाद सभी आवश्यक प्रतिक्रिया और जांच तंत्र सक्रिय कर दिए गए थे। एएआइबी के दिल्ली के तीन व नागर विमानन महानिदेशालय के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के तीन अधिकारियों ने 28 जनवरी को दुर्घटनास्थल का मुआयना किया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एएआइबी के महानिदेशक भी उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने पूरे घटनास्थल की गहन जांच पड़ताल की है। सूत्रों के मुताबिक, जांच में मौसम की स्थिति, पायलट की कोशिशें, बारामती हवाई अड्डे की सुविधाओं और अंतिम 26 मिनट के घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है।

'बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है'

घरों, संपत्तियों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर हमले शामिल हैं। भारत ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर कई अवसरों पर बांग्लादेश के अधिकारियों के समक्ष उठाया है।' उन्होंने कहा कि यह मुद्दा प्रधानमंत्री ने चार अप्रैल 2025 को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के साथ अपनी बैठक में उठाया था, जबकि विदेश मंत्री ने 16 फरवरी 2025 को विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ बैठक में इस पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि अन्य विदेशी प्रतिनिधियों के साथ प्रासंगिक वार्ताओं में भी यह विषय उठाया गया है। सिंह ने कहा, 'भारत सरकार की यह अपेक्षा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इन घटनाओं की पूरी तरह जांच करे और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हत्याओं, आगजनी और हिंसा के सभी दोषियों को बिना किसी बहाने न्याय के दायरे में लाए। बांग्लादेश में सभी नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है।' एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार द्वारा हिंदुओं पर हमलों को लेकर दिए गए हालिया बयान पर भारत के रुख के बारे में पूछा गया था। इसके जवाब में सिंह ने कहा कि अंतरिम सरकार की, अल्पसंख्यकों पर हमलों को व्यक्तिगत रंजिश, राजनीतिक मतभेद या अन्य बाहरी कारणों से जोड़ने की प्रवृत्ति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान चरमपंथियों और अपराधियों का हौसला बढ़ाते हैं और अल्पसंख्यकों के बीच भय और असुरक्षा की भावना को और गहरा करते हैं। सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी घटनाओं को लेकर भारत की चिंताओं और संवेदनशीलताओं को बांग्लादेश सरकार तक, उच्चतम राजनीतिक स्तर पर भी, स्पष्ट रूप से पहुंचाया गया है।

वैश्विक पूंजी प्रवाह में व्यवधान के संकेत

2025-26 की समीक्षा में कहा गया, 'हाल के वर्षों में नीतिगत सुधारों के प्रभाव से अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की वृद्धि क्षमता 6.5 से 6.8 फीसद से बढ़कर सात फीसद के करीब पहुंच गई है। यही कारण है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच मजबूत वृद्धि का दृष्टिकोण बना हुआ है और इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन निराशावादी होने की जरूरत नहीं है।'

चालू वर्ष के लिए 7.4 फीसद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान पिछले वर्ष की समीक्षा में अनुमानित 6.3 से 6.8 फीसद की तुलना में अधिक है। लेकिन अगले वर्ष के लिए अनुमान से साफ है कि अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला देश बना रहेगा। भारत उन कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसने अभी तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं किया है। अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाले सामान पर 50 फीसद का उच्चतम शुल्क लगाया है। श्रम-प्रधान क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले शुल्क के जवाब में केंद्र सरकार ने नीति और कर सुधारों की शुरुआत की है। इनमें जीएसटी दरों में कटौती, आयकर सीमा को बढ़ाना, कंपनियों पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन और मई, 2025 के बाद से चार मुक्त व्यापार समझौते शामिल हैं। इनमें यूरोपीय संघ के साथ एक बड़ा समझौता भी शामिल है।हालांकि महंगाई कम है, कंपनियों और परिवारों की बही-खाते बेहतर है और उपभोग मांग मजबूत बनी हुई है, पर अमेरिकी शुल्क के कारण रुपये में पिछले साल लगभग पांच फीसद की गिरावट आई है और अब यह अपनी क्षमता से निचले स्तर पर है।

समीक्षा में कहा गया, 'रुपए का मूल्यांकन मजबूत आर्थिक बुनियाद को सही रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। हालांकि, रुपए के मूल्य में गिरावट वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को कुछ हद तक कम करती है।'

आर्थिक समीक्षा में प्रति व्यक्ति मासिक आय वृद्धि का जिक्र

गरीबी में आई कमी, निचले तबके की खपत में तेज वृद्धि

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

सरकार के लक्षित कल्याणकारी उपायों से गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है और आय वितरण में व्यापक सुधार हुआ है। इससे सबसे निचली पांच से 10 फीसदी आबादी के उपभोग व्यय में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है। संसद में गुरुवार को पेश आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया। समीक्षा में सब्सिडी, पेंशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय के सकारात्मक परिणामों का जिक्र किया है। बताया गया कि इन उपायों से कमजोर वर्ग अभाव से बाहर आए हैं।

यह बात नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24 से सामने आई है। इससे पता चलता है कि उपभोग असमानता में कमी और सबसे वंचित समूह को उल्लेखनीय लाभ हुआ है। समीक्षा के अनुसार, 2022-23 और 2023-24 के बीच प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय (एमपीसीई) में सबसे बड़ी वृद्धि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे निचली पांच से 10 फीसद आबादी के बीच देखी गई। यह सरकारी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव को बताती है।

संसद में पेश आर्थिक समीक्षा के दौरान निर्मला सीतारमण (बाएं), एस जयशंकर, मनोहरलाल खट्टर।

समीक्षा के अनुसार, गरीबी के दुष्चक्र से कमजोर वर्ग को बाहर निकालने के लिए सरकार के उपायों का सकारात्मक परिणाम हुआ है, जो गरीबी कम करने के विभिन्न उपायों में प्रतिबिंबित होते हैं।

इसमें कहा गया है कि सरकारी नीतियों का आय वितरण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मुख्य रूप से सब्सिडी, पेंशन, प्रत्यक्ष अंतरण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा सहित सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के माध्यम से आय वितरण पर सकारात्मक असर दिखा है।

समीक्षा में ग्रामीण भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करते हुए स्थानीय अवसरों और नवोन्मेष के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक गति को बढ़ाने का भी आह्वान किया गया है। इसमें सबसे कमजोर वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उपभोग में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आजीविका का समर्थन करने और जीवन स्तर को बिना किसी बाधा के बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार आवश्यक है।

वृद्धि के बावजूद कृषि क्षेत्र जलवायु संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा

भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। हालांकि यह क्षेत्र हाल की वृद्धि के बावजूद स्थिरता एवं उत्पादकता संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। संसद में गुरुवार को पेश आर्थिक समीक्षा में यह बात कही गई।

समीक्षा में उर्वरक क्षेत्र में सुधार, शोध एवं विकास को प्रोत्साहन, सिंचाई प्रणालियों को मजबूत करने और फसल विविधीकरण सहित अहम सुधारों का आह्वान किया गया। इसमें कहा गया है कि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय आय में लगभग एक-पांचवां हिस्सा योगदान करती हैं लेकिन कार्यबल का 46.1 प्रतिशत हिस्सा इन गतिविधियों में संलग्न है। इस तरह यह क्षेत्र देश के समग्र वृद्धि पथ के केंद्र में है। स्थिर कीमतों पर पिछले पांच वर्षों में कृषि क्षेत्र ने औसतन 4.4 फीसद की सालाना वृद्धि दर दर्ज की है, जिसमें पशुधन एवं मत्स्य पालन का योगदान सर्वाधिक रहा है।

शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन मजबूत, सेंसेक्स 222 अंक चढ़ा

टाटा स्टील एवं लार्सन एंड टुब्रो में लिवाली आने और आर्थिक समीक्षा 2025-26 में अगले वित वर्ष के लिए 6.8-7.2 प्रतिशत का वृद्धि अनुमान जताए जाने से बृहस्पतिवार को स्थानीय शेयर बाजारों में तेजी रही। सेंसेक्स 222 अंक चढ़ गया जबकि निफ्टी में 76 अंक की बढ़त दर्ज की गई।

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स दोपहर के सत्र में बढ़ी लिवाली के दम पर 221.69 अंक यानी 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,566.37 अंक पर बंद हुआ। हालांकि, सुबह के कारोबार में यह 636.74 अंक टूटकर 81,707.94 अंक तक गिर गया था। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 76.15 अंक यानी 0.30 प्रतिशत चढ़कर 25,418.90 अंक पर बंद हुआ। सुबह के कारोबार में निफ्टी 25,159.80 अंक तक फिसल गया था। विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक बाजारों में तेजी और विदेशी कोषों के निवेश में बढ़ोतरी ने प्रमुख सूचकांकों को निचले स्तर से उबारने में मदद की।

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा

उथल-पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था, नई उम्मीद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने के बाद कहा, वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था, एक नई उम्मीद है।

लेकिन कृत्रिम मेधा और घरेलू नीतियों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए नागेश्वरन ने शेयर बाजार को बहुत महंगा होने की बात कही

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने शेयर बाजार में जारी तेजी पर चिंता जताई और आसान नकदी के दौर का यह नतीजा है कि बाजार बहुत महंगा हो गया है।

और इसे निवेशकों के लिए सतर्क रहने का संकेत बताया। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने शेयर बाजार में जारी तेजी पर चिंता जताई और आसान नकदी के दौर का यह नतीजा है कि बाजार बहुत महंगा हो गया है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब खुदरा निवेशक बाजार में भारी निवेश कर रहे हैं। उनका इशारा तरलता के दम पर बाजार में जारी तेजी की तरफ था।

उन्होंने विकास दर, भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा, अगर विनिर्माण और विकास से जुड़े सुधारों को उचित रूप में लागू किया जाता है, तो यह आंकड़ा 7.5 से 8 फीसद तक पहुंच सकता है। नागेश्वरन ने रणनीतिक स्वदेशी की वकालत करते हुए कहा कि अब व्यापार पारस्परिक नहीं रहा और बाजार तटस्थ नहीं रहे।

अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपया 91.99 प्रति डालर के स्तर पर

मुंबई, 29 जनवरी (भाषा)।

विदेशी कोषों की बिकवाली और वैश्विक बाजारों में जोखिम लेने की धारणा कमजोर होने के बीच, अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 91.99 पर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर के करीब बंद हुआ।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता और विदेशी पूंजी की निकासी के बीच रुपया, अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 92 के अपने अब तक के सबसे निचले दिन के कारोबार के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का भी रुपये पर दबाव पड़ा।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, रुपया 91.95 पर खुला और शुरुआती कारोबार में 91.82 के उच्चस्तर पर पहुंचा, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई और यह डॉलर के मुकाबले 92 के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में रुपया 91.99 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव के समान है।

मौसम

उधमपुर के मीर पंचारी में गुरुवार को ताजा बर्फबारी के बाद बर्फ से ढका क्षेत्र।

संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रपट में दी गई जानकारी

देश में हाइ स्पीड कारिडोर दस गुना और साठ फीसद बढ़ गए राजमार्ग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

देश में बीते बारह सालों में राजमार्ग व हाइ स्पीड कारिडोर तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सालों में हाइस्पीड कारिडोर में दस गुना और राजमार्ग में साठ फीसद का इजाफा हुआ है।

गुरुवार को संसद में पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रपट में यह जानकारी दी है। इस रपट में वर्ष वर्ष 2018 से लेकर 2026 की स्थिति का हवाला दिया है। रपट के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्र में साठ फीसद का इजाफा हुआ है। वर्ष 2014 में राजमार्ग के कुल किलोमीटर 91287 किलोमीटर थे, जो कि वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 146272 किलोमीटर हो गया है। इसके अतिरिक्त देश में तैयार किए जा रहे हाइ स्पीड कारिडोर का भी तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2014 में केवल 550 किलोमीटर तक ही ऐसे मार्ग थे, जो कि वर्ष 2026 में (दिसंबर) बढ़कर 5364 किलोमीटर हो गए हैं।

केंद्र सरकार ने इस श्रेणी में निवेश और अवसंरचना में पूंजीगत व्यय को 4.2 गुना तक बढ़ाया है, इस मद में वर्ष 20218 में 2.63 करोड़ रुपए का निवेश था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2026 में 11.26 लाख करोड़ रुपए किया गया है। जबकि वित्त वर्ष 2026 (बजट अनुमान) में प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 करोड़ रुपए है। जिससे इस क्षेत्र में और तेजी से काम करने का रास्ता साफ होगा। रपट के मुताबिक पूंजीगत श्रेणी में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है।

हिमाचल में भारी बर्फबारी से तीन हाईवे सहित 655 सड़कें बंद

शिमला, 29 जनवरी (ब्यूरो)।

हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के कारण प्रदेश में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कुल 655 सड़कें अभी भी बंद हैं, जिससे राज्य में सैकड़ों जगहों पर सड़क संचार प्रभावित हुआ है।

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार, लाहौल और स्पीति में राष्ट्रीय राजमार्ग लेह-मनाली और राष्ट्रीय राजमार्ग काजा-ग्राम्फू समेत 287, शिमला में 135, कुल्लू में राष्ट्रीय राजमार्ग आट-लुहरी-सैंज समेत 81, मंडी में 77, चंबा में 40, किन्नौर में 27, सिरमौर और ऊना में तीन-तीन और कांगड़ा जिले में दो सड़कें बंद हैं। इसके अलावा, राज्य में 669 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, जिससे हजारों घरों में बिजली नहीं है। इनमें कुल्लू में 216, शिमला में 214, चंबा में 104, मंडी में 94, लाहौल-स्पीति में 22, सिरमौर में 13 और किन्नौर जिले में छह ट्रांसफार्मर शामिल हैं।

किन्नौर और लाहौल और स्पीति के ऊंचे इलाकों में गुरुवार को भी हल्की बर्फबारी और बारिश हुई, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम ज्यादातर साफ रहा।

'भारत-अमेरिका में पारस्परिक लाभ वाले करार पर बातचीत'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

राज्यसभा में सरकार ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और दोनों पक्ष वर्तमान में पारस्परिक लाभ वाले बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।

विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देश राष्ट्रीय हितों पर आधारित विदेश नीतियां अपनाते हैं, जिसमें व्यापार संबंधी चंद उपायों, प्रतिबंधों से संबंधित मुद्दों और विशिष्ट क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर उनके दृष्टिकोण की झलक मिलती है।

जयशंकर ने वाशिंगटन की यात्रा से पहले अमेरिकी राजदूत से मुलाकात की

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगले सप्ताह वाशिंगटन की अपनी निर्धारित यात्रा से पहले गुरुवार को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ बातचीत की। जयशंकर और गोर के बीच इस वार्ता में व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा जैसे क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर आयोजित होने वाली पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

सिंह ने कहा, मतभेदों का समाधान उच्च स्तरीय और संस्थागत संवादों के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने यह बात अमेरिका के साथ रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग पर भारत के वर्तमान रुख और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच समान रुख व मतभेद वाले क्षेत्रों के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कही। मंत्री ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें आतंकवाद-विरोधी उपाय, रक्षा सहयोग, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला और एक स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता सहित कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर समान रुख है।

ग्रामीण संपर्क में तेजी, शार्ट वीडियो और एआइ का इस्तेमाल वजह | रपट | सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से 57 फीसद ग्रामीण भारत से हैं

भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 95 करोड़ के पार

बंगलुरु, 29 जनवरी (भाषा)।

ग्रामीण संपर्क में तेजी, शार्ट वीडियो के बढ़ते चलन और कृत्रिम मेधा (एआइ) के बढ़ते इस्तेमाल के कारण वर्ष 2025 में भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 95 करोड़ के पार पहुंच गई है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया (आइएएमएआइ) द्वारा गुरुवार को जारी रपट में यह जानकारी दी गई।

रपट के मुताबिक, सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से 57 फीसद यानी लगभग 54.8 करोड़ ग्रामीण भारत से हैं। इन रुझानों पर आधारित इंटरनेट इन इंडिया रपट 2025 को कर्नाटक सरकार के इलेक्ट्रानिक्स, आइटी/बीटी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव मंजुला एन की उपस्थिति में इंडिया डिजिटल समिट में जारी किया गया। रपट को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया (आइएएमएआइ) और कांतार ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। रपट के अनुसार, भारत में अब 95.8 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता (एआइयू) हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि है, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक के रूप में भारत की स्थिति को और पुख्ता करती है।

रपट को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया (आइएएमएआइ) और कांतार ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। रपट के अनुसार, भारत में अब 95.8 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता (एआइयू) हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि है, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक के रूप में भारत की स्थिति को और पुख्ता करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत में एआइ का उपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ा है। करीब 44 फीसद उपयोगकर्ता वायस सर्च, इमेज-आधारित सर्च, चैटबाट और एआइ फिल्टर जैसे फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ष 2025 में 61 फीसद यानी लगभग 58.8 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने शार्ट-वीडियो देखे, जिनमें ग्रामीणों की संख्या शहरी क्षेत्रों के लोगों से थोड़ी अधिक रही।

इसमें यह भी बताया गया है कि भारत में एआइ का उपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ा है। करीब 44 फीसद उपयोगकर्ता वायस सर्च, इमेज-आधारित सर्च, चैटबाट और एआइ फिल्टर जैसे फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।

रपट में कहा गया, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की इस संख्या में ग्रामीण भारत की निर्णायक भूमिका बनी हुई है, जहां अब लगभग 54.8 करोड़ सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। रपट के अनुसार, भारत के कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी अब 57 प्रतिशत से अधिक हो गई है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का विस्तार शहरी भारत की तुलना में लगभग चार गुना तेजी से हो रहा है, जो देश के डिजिटल ढांचे में एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। रपट में कहा गया है कि युवाओं (15-24 वर्ष) में एआइ का उपयोग सबसे अधिक 57 फीसद देखा गया है। इसके बाद 25 से 44 वर्ष के आयु वर्ग का स्थान है, जिसमें 52 फीसद लोगों ने पिछले एक साल के दौरान एआइ का इस्तेमाल करने की जानकारी दी है। इसी तरह, शार्ट-वीडियो मंच भी विकास के मुख्य चालक बनकर उभरे हैं।

वर्ष 2025 में 61 फीसद यानी लगभग 58.8 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने शार्ट-वीडियो देखे, जिनमें ग्रामीणों की संख्या शहरी क्षेत्रों के लोगों से थोड़ी अधिक रही। ई-कामर्स और डिजिटल आदतें रपट में बताया गया है कि पारंपरिक आनलाइन बाजारों के अलावा अब हाइपरलोकल क्विक कामर्स और ह्वासोशल कामर्स का चलन भी बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों के लगभग 23 करोड़ लोगों ने पिछले एक साल में आनलाइन खरीदारी की।

खबर कोना

बुलेट ट्रेन परियोजना : अहमदाबाद में तैयार हुआ 100 मीटर लंबा इस्पात पुल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत अहमदाबाद जिले में भूमिगत मेट्रो सुरंग के ऊपर 100 मीटर लंबा इस्पात पुल तैयार किया गया है। यह गुजरात में पूरा हुआ 13वां इस्पात पुल है। राज्य में कुल 17 इस्पात पुल तैयार होंगे। रेलवे अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद जिले में बुलेट ट्रेन वायाडक्ट का निर्माण 30 से 50 मीटर तक के स्पैन वाले स्पैन-बाय-स्पैन स्ट्रक्चर का उपयोग करके किया जा रहा है। जिस जगह पर इस्पात पुल बनाया गया है वहां पर अलाइनमेंट कालुपुर और शाहपुर मेट्रो स्टेशनों को जोड़ने वाली भूमिगत मेट्रो सुरंग के ऊपर से गुजरता है। ऐसे में बुलेट ट्रेन संरचना से कोई भी भार मेट्रो सुरंग पर नहीं पड़ेगा। इसके लिए बुलेट ट्रेन के पीलर की नींव को इससे काफी दूर रखा गया था।

आवारा कुत्तों संबंधी पूर्व के आदेश में संशोधन संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 29 जनवरी (ब्यूरो)।

उच्चतम न्यायालय ने आवारा कुत्तों के मामले में पहले दिए गए आदेशों में संशोधन का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने न्यायमित्र गौरव अग्रवाल की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अग्रवाल ने पीठ के समक्ष पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की ओर से पेश हुए अधिवक्ता की दलीलें भी सुनी, जिसमें 7 नवंबर, 2025 के उस निर्देश के अनुपालन का जिक्र था। अदालत ने प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने और सड़कों के किनारे बाड़ लगाने के निर्देश दिए थे।

आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हुई, 28 अब भी लापता

कोलकाता, 29 जनवरी (भाषा)।

दक्षिण 24 परगना जिले में मोमो बनाने की इकाई व उसके गोदाम में 26 जनवरी को लगी आग के बाद क्षतिग्रस्त इमारतों से 13 और शव बरामद किए गए और इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 28 लोग अब भी लापता हैं, जिससे आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के अन्य नेताओं के प्रस्तावित दौरे से पहले अधिकारियों ने इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना की प्रकृति और नुकसान की गंभीरता को देखते हुए, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

'विधायक वीरेंद्र व सहयोगी गैरकानूनी आनलाइन सट्टेबाजी के सरगना'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 जनवरी।

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दावा किया कि कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र और उनके सहयोगी एक राष्ट्रव्यापी 'अवैध' आनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के 'सरगना' हैं। ईडी बताया कि उसने मामले से जुड़े धनशोधन जांच के तहत और 177 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। संघीय जांच एजंसी ने कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कृषि और आवासीय भूखंडों के साथ-साथ कुछ चल संपत्तियों को कुर्क करने का अंतरिम आदेश जारी किया है। हालांकि, उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये संपत्तियां किसकी हैं। ईडी ने कर्नाटक की चित्रदुर्ग विधानसभा सीट से विधायक वीरेंद्र (51) को अगस्त 2025 में सिक्किम से गिरफ्तार किया था।

अयोध्या में दो कैदी जिला जेल से फरार, जेल अधीक्षक समेत सात निलंबित

अयोध्या, 29 जनवरी (जनसत्ता)।

अयोध्या में दो कैदी जिला जेल से फरार हो गए हैं। कैदियों के नाम गोलू अग्रहरि और शेर अली हैं। ये दोनों तन्हाई बैरक तोड़ने के बाद दीवार कूदकर फरार हुए हैं। कैदियों में गोलू अग्रहरि अमेठी और शेर अली सुल्तानपुर का रहने वाला है। इनमें से एक हत्या के प्रयास और दूसरा बलात्कार के मामले में जेल में बंद था। कैदियों की फरारी की खबर से जिले में हड़कंप मच गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए जेल के डीजी पीसी मीणा ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक उदय प्रताप मिश्रा, जेलर जेके यादव, दो जेलर मयंक त्रिपाठी समेत एक हेड जेल वार्डन और तीन जेल वार्डरों को निलंबित कर दिया है। मामले की सूचना मिलते ही जिले के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी गौरव ग्रोवर भी जिला जेल पहुंचे।

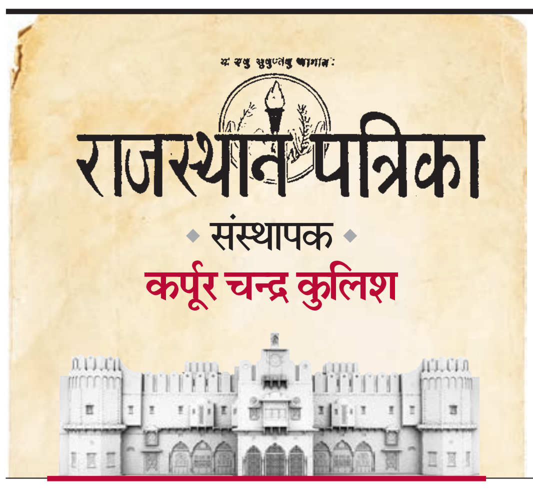

चुनौतियों को अवसर में बदल भारत ने बढ़ाई साख

संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने अभिभाषण में कहा था कि युद्ध की उथल-पुथल और अनिश्चितताओं ने स्थिरता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रखा है। इसके बावजूद भारत तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में, जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया उसमें भी विकास के नित नए पायदान चढ़ते भारत की तस्वीर सामने आई है। जाहिर है पिछले वर्षों में नीतिगत सुधारों की, जो मजबूत नींव रखी गई है उससे भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद ऊंचाइयों पर पहुंच रही है।

आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2026-2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रह सकती है। इन सुधारों का ही असर है कि भारत में मध्यम अवधि की विकास क्षमता अब 7 प्रतिशत के करीब पहुंच चुकी है। भारत की इस आर्थिक मजबूती की बड़ी वजह यह भी है कि उसने अपनी आंतरिक क्षमताओं पर भरोसा किया है। भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां सेमीकंडक्टर से लेकर हर उत्पाद का निर्माण यहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन भी तरक्की की इस रफ्तार को दिखाने वाला है। इतना ही नहीं, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाकर सप्लाई चेन में सुधार के उपायों से अर्थव्यवस्था की बुनियाद बाहरी झटकों में मजबूत बनी हुई है। राहत की बात यह भी है कि सर्वे के मुताबिक महंगाई दर आरबीआइ के चार प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास रहने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वे 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बड़ी सफलता की कहानी बताया गया है। वित्त वर्ष 2022 में सातवें स्थान पर रहने वाला यह सेक्टर वित्त वर्ष 2025 तक तीसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बन चुका है। एक तथ्य यह भी है कि खेती के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण स्तर पर मांग तो बढ़ी ही है, टैक्स सुधार और स्थिर रोजगार के चलते शहरी खपत में भी इजाफा हुआ है। सुधार उपायों के बल पर भारत न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक बाजारों में अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ा रहा है। ट्रंप टैरिफ के दबाव के बावजूद जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बरकरार रहना भारत की आर्थिक नीतियों के लचीलेपन की जीत है।

सुधारों के दम पर ही भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत के लिए यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते चुनौतियों को अवसर में बदलने वाले होंगे। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को उन चुनौतियों का भी सामना करना है, जिसमें चीन व अमरीका जैसे देश वैश्विक व्यापार को अनिश्चितता के भंवर में धकेलने में कोई कसर नहीं रख रहे। ऐसे में भारत को अपनी नीतियों को और बेहतर करने के साथ-साथ लक्ष्य प्राप्ति के ठोस प्रयास भी करने होंगे।

महाराष्ट्र की राजनीति: अजित पवार के निधन के बाद अब सत्ता महत्वाकांक्षाओं में संतुलन बैठाने की स्थिति बनेगी

पवार परिवार और पार्टी के दोनों गुट होंगे एक?

राज कुमार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
@patrika.com

2029 के चुनावों में एनसीपी के अजित गुट को जिताऊ चेहरा चाहिए होगा। शरद पवार अपनी बेटी को दिल्ली और अजित के परिवार के चुने उत्तराधिकारी को महाराष्ट्र की राजनीति सौंपकर एकता का फॉर्मूला निकाल सकते हैं।

अजित पवार के निधन से फिर जीवन का यही सच रेखांकित हुआ कि नियति के आगे इंसान बेबस है। जिस शख्स ने अपने नाम और काम से महाराष्ट्र की राजनीति में 'दादा' का संबोधन हासिल किया, विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद उसकी पहचान 'घड़ी' से करनी पड़ी। संयोगवश 'घड़ी' अजित की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का चुनाव चिह्न भी है। जीवन का दूसरा सच यह भी है कि बड़े-से-बड़े हादसे के बाद भी समय रुकता नहीं है। अब राजनीतिक गलियारों में बड़ा सवाल यह है कि क्या अजित के निधन के बाद पवार परिवार और एनसीपी के दोनों गुट एक होंगे?

हमने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते कई परिवार टूटते देखे हैं, पर राजनीतिक टकराव का असर पवार परिवार के आपसी रिश्तों पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा नजर नहीं आया। बीच-बीच में पारिवारिक मेल-मुलाकातों की खबरें भी आती रहीं, पर एकता से पहले उन सवालों से तो दो-चार होना ही पड़ेगा, जिनके चलते राजनीतिक अलगाव हुआ। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय शरद पवार द्वारा महाराष्ट्र की राजनीति अजित को सौंप देने के बाद उन्हें ही राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन बेटी सुप्रिया सुले की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता से भतीजे की महत्वाकांक्षाएं टकराने लगीं। यह टकराव पहली बार सतह पर तब आया, जब गुपचुप तरीके से 23 नवंबर 2019 को अलसुबह राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। वह सरकार लगभग 82 घंटे ही चल पाई, पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी वैकल्पिक सरकार में एनसीपी कोटे से अजित को ही उप मुख्यमंत्री बनाने से संदेश गया कि पवार परिवार की दरारें भर गई हैं। वह खुशफहमी तभी तक बरकरार रह पाई, जब तक कि शिवसेना में विभाजन से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा नई सरकार बनवाने में सफल नहीं हो गई। सरकार को विधानसभा में बहुमत प्राप्त था। फिर भी अजित पवार एनसीपी तोड़कर उसमें उप मुख्यमंत्री बन गए। उसके मूल में अजित के सत्ता-प्रेम के साथ-साथ शिंदे पर भाजपा का अविश्वास भी बड़ा कारक रहा।

2024 के चुनाव में 288 सदस्यीय विधानसभा में अकेले दम 132 सीटें जीतने के बावजूद भाजपा ने शिंदे और अजित को उप मुख्यमंत्री बनाते हुए गठबंधन सरकार बनाई। दरअसल अपेक्षाकृत विश्वसनीय अजित को भाजपा अति महत्वाकांक्षी शिंदे पर नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल करती रही।

अब जबकि अजित पवार नहीं रहे तो दूसरा बड़ा सवाल यही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार के समीकरण भी बदलेंगे? जाहिर है, इन दोनों सवालों का सही जवाब पवार परिवार की राजनीति पर निर्भर करेगा। पवार परिवार और उसकी राजनीति को जानने वाले मानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में मराठा राजनीति जिस तरह हाशिये पर खिसक गई है, उसके मद्देनजर खोया हुआ रुतबा पाने के लिए एनसीपी के दोनों गुटों के समक्ष एकता के अलावा कोई विकल्प नहीं। बेशक, बेहतर पारिवारिक समझदारी इसमें मददगार होगी, लेकिन राजनीतिक सत्ता का बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। आखिर विधानसभा चुनाव में चाचा पर भारी पड़े भतीजे का परिवार राजनीतिक सत्ता में अपना हिस्सा क्यों नहीं चाहेगा? भाजपा को स्वाभाविक ही अजित की पत्नी सुनेत्रा या दोनों बेटों- पार्थ और जय में से एक को उप मुख्यमंत्री बनाने में भी कोई रणनीतिक समस्या नहीं होगी, लेकिन बिना करिश्माई नेतृत्व के वह व्यवस्था कितनी लंबी चल पाएगी? बेशक प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता हैं, पर 2029 में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे तो एनसीपी के अजित गुट को चुनाव जिताऊ चेहरा चाहिए होगा।

ऐसे में जीवन के संध्याकाल में खड़े शरद पवार को परिवार की सत्ता महत्वाकांक्षाओं में न्यायपूर्ण तर्कसम्मत संतुलन बैठाना होगा। सबसे अहम होगा एकजुट एनसीपी का नेतृत्व। खुद मार्गदर्शक की भूमिका स्वीकारते हुए शरद पवार अपनी बेटी को दिल्ली और अजित के परिवार द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी को महाराष्ट्र की राजनीति सौंपकर एकता का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन एकजुट एनसीपी की राजनीतिक राह चुनना दूसरी बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव के लिए बना विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' विधानसभा चुनावों में बिखरता गया है। महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में तो वह दिखा ही नहीं। राष्ट्र और महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य बताता है कि निकट भविष्य में तो सत्ता समीकरण बदलने वाले नहीं। तब क्या बुजुर्ग पवार अपने भतीजे के परिवार और बेटी को सत्ता राजनीति में स्थापित करने के लिए विपक्षी गठबंधन का मोह त्याग कर राजग में शामिल होंगे?

तीसरे मोर्चे से लेकर कांग्रेसनीत गठबंधन तक की राजनीति करने वाले शरद पवार के भाजपा से राजनीतिक रिश्ते नहीं रहे, लेकिन 2014 में शिवसेना से तनातनी के बीच फडणवीस सरकार ने एनसीपी की मदद से ही विधानसभा में बहुमत साबित किया था। वैसे भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में शायद ही कोई ऐसा हो, जिससे पवार का सीधा संपर्क और संवाद न हो। पवार तो कहे भी 'पॉवर प्लेयर' जाते हैं। अगर एकजुट एनसीपी राजग में शामिल होती है तो न सिर्फ महाराष्ट्र में सत्ता के माहिर सौदेबाज एकनाथ शिंदे पर भाजपा की निर्भरता समाप्त हो जाएगी, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश के दूसरे बड़े राज्य से ज्यादातर सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल करना भी आसान हो जाएगा। अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के टकराव के चलते एनसीपी के दोनों गुट एक नहीं हो पाए तो ज्यादा संभावना देर-सवेर अजित गुट के भाजपा में विलय की रहेगी, क्योंकि उसके 41 विधायक अगले चुनाव में भी जीतकर विधानसभा में लौटना चाहेंगे, जिसके लिए बड़े दल या नेता का नाम चाहिए।

फैक्ट फ्रंट

यूरेशियन हूपो

यूरेशियन हूपो अपनी अनोखी कलगी, सुंदर रंगों और खास आवाज के कारण लोगों का ध्यान तुरंत खींच लेता है। इसे हिंदी में आमतौर पर हुदहुद कहा जाता है। यह पक्षी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्से में पाया जाता है और भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। हूपो की खास पहचान इसके सिर पर लगी पंखों की कलगी है, जिसे यह खतरे या उत्साह की स्थिति में पंखे की तरह फैला लेता है। इसका शरीर हल्के भूरे रंग का होता है, जबकि पंखों और पूंछ पर काले और सफेद रंग की धारियां साफ दिखाई देती हैं। इसकी चोंच लंबी, पतली और थोड़ी मुड़ी हुई होती है, जो जमीन से कीड़े निकालने में बहुत उपयोगी होती है। यह पक्षी आमतौर पर खुले मैदानों, खेतों, बगीचों और गांवों के आसपास पाया जाता है। यूरेशियन हूपो का मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े, दीमक, केंचुए और छोटे कीट होते हैं। यह जमीन पर चलकर अपनी चोंच से मिट्टी कुरेदता है और भोजन खोजता है। यह पक्षी पर्यावरण के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह खेतों में हानिकारक कीटों की संख्या कम करता है। हूपो अभी संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन वनों की कटाई, कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग व प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से इसके सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं।

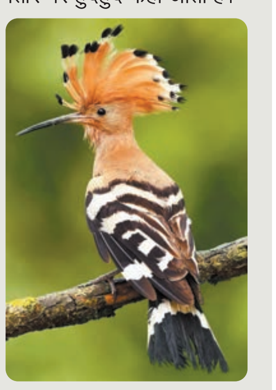

दृष्टिकोण

जान पर भारी पड़ते लाइक व व्यूज

रील बनाने के चक्कर में केरल में हुई दुखद घटना ने सभी का ध्यान खींचा है। सवाल यह कि क्या रील बनाने वालों का इतना नैतिक पतन हो गया है कि लाइक और व्यूज के लिए किसी की जान से खेल जाएं? दरअसल केरल के कोझीकोड की रहने वाली एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शिमजीता ने चलती बस में चुपचाप एक वीडियो शूट किया। उसने 41 वर्षीय दीपक पर बैड टच करने का आरोप लगाते हुए रील बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जो तेजी से वायरल हो गई। कुछ समय में ही उसे 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए। दीपक ऑफिस जाने के लिए कन्नूर से बस में सवार हुए थे। बस में काफी भीड़ थी। शिमजीता उसके पीछे खड़ी होकर वीडियो बनाने लगी, जिससे दीपक अनजान था। बस ठसाठस भरी थी और झटके भी लग रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि दीपक को पता ही नहीं चला कि कब उसका हाथ शिमजिता से टच हो गया, हुआ भी या नहीं या केवल कैमरे का कमाल था? लेकिन कथित बैड टच के बाद भी लड़की पूरी सहज और मुस्कुराते हुए अलग-अलग फ्रेम में वीडियो बना पोस्ट कर देती है। यदि वाकई बैड टच था तो वहीं बस में आपत्ति करनी थी। घटना से बेखबर दीपक के पास दूसरे दिन दोस्तों के फोन और वह वीडियो आने लगे। दीपक के होश उड़ गए। उसे याद भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। सार्वजनिक अपमान से दीपक इतना आहत हुआ कि दो दिन बाद अपने कमरे में फंदा लगा लिया। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की को गिरफ्तार कर लिया।

ऋतुपर्ण दवे
स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार
@patrika.com

दरअसल, आजकल शॉर्टकट से पैसे कमाने की चाहत में लोग कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि लाइक और व्यूज से किसी के मान-सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। वे नैतिकता, सुरक्षा व्यवस्था और कानून-कायदों का भी ध्यान नहीं रखते। हालांकि अब तक सेल्फी के चक्कर में जान जाने की घटनाओं को लेकर सामाजिक तौर पर चिंता जाहिर की जाती थी, लेकिन अब ऐसे वीडियो जो किसी की भावनाओं को आहत करे और यहां तक कि किसी की जान पर बन आए, हैरान करते हैं। भय और भगदड़ पैदा करने वाले एआइ जेनरेटेड वीडियो पोस्ट करना अपराध है लेकिन लाइक, व्यूज, झूठी शान और शॉर्टकट से पैसे कमाने की चाहत ने सोशल मीडिया को एक बार फिर कठघरे में खड़ा कर दिया है।

फ्लेमिंग स्प्रिंग: प्रकृति का चमत्कार, जहां आग और पानी साथ-साथ

चीन के शिनजियांग में बाइचेंग काउंटी का 'फ्लेमिंग स्प्रिंग' प्रकृति के चमत्कारों में से एक है। इस अनोखे झरने की पहचान है- आग और पानी का साथ-साथ होना। साफ़, पारदर्शी जलधारा के बीच से उठती लपटें ऐसा दृश्य रचती हैं मानो प्रकृति स्वयं अपने नियमों को चुनौती दे रही हो। यहां आग पर पानी डालने से भी लपटें बुझती नहीं हैं और निरंतर जलती आग के बावजूद झरना कभी सूखता नहीं। स्थानीय मान्यताओं और वैज्ञानिक जिज्ञासा- दोनों का केंद्र बना यह स्थल प्राकृतिक गैस के रिसाव और जलस्रोत के अनूठे मेल का परिणाम माना जाता है। दिन के उजाले में लपटें पानी पर नृत्य करती प्रतीत होती हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा रियल टाइम मॉनिटरिंग व डायनेमिक असेसमेंट जैसे पद्धतियां अपनाने की जरूरत

बड़ी लाइनें, छोटे नतीजे: स्वच्छ ऊर्जा प्रवाह में क्या बाधाएं

देश में बिजली की आवश्यकता विकास के साथ हर साल बढ़ रही है। खेतों की सिंचाई, उद्योग धंधे और घरों की रोशनी में बिजली बढ़ती खपत के कारण पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित ऊर्जा पर जोर देना जरूरी है। भारत तेजी से सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र (प्लांट) लगा रहा है, जिनसे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलने की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं, लेकिन एक छिपी हुई समस्या बिल को कम नहीं होने दे रही है।

इन संयंत्रों द्वारा आगे बिजली प्रवाह में और घरों से जोड़ने वाली पावर लाइनों में असंतुलन के कारण बहुत सारी हरित ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पा रहा और यह व्यर्थ जा रही है। इसका यह भी मतलब है कि दो बार खर्च करना पड़ रहा हैं: एक बार महंगी बिजली लाइनें बनाने के लिए और दूसरी बार तब, जब सस्ती सौर ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाती और उसकी कमी को पूरा करने लिए मंहगे विकल्पों का सहारा लिया जाता है।

राजस्थान में ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्र बनकर तैयार हैं जिनमें लाखों घरों को रोशन करने की क्षमता है लेकिन चिलचिलाती धूप के दौरान-ठीक उसी समय जब इन संयंत्रों को अधिकतम बिजली पैदा करनी चाहिए, एक तकनीकी समस्या 'कर्टेलमेंट' के कारण इन संयंत्रों को चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनें इन्हें नहीं ले पातीं और काफी बिजली बेकार हो जाती है। राजस्थान में चार हजार मेगावाट से अधिक की सौर क्षमता बेकार पड़ी रहती है। ट्रांसमिशन लाइनों में असंतुलन के कारण इस सस्ती और स्वच्छ बिजली को आगे प्रवाहित नहीं किया जा सकता। इस समस्या को हल करने के लिए भारी लागत पर खेतड़ी-नरेला कॉरिडोर नामक एक विशाल बिजली लाइन बनाई गई थी लेकिन इससे उपयोग की जाने वाली क्षमता में केवल 600 मेगावाट की वृद्धि हुई-जो उम्मीद से कहीं कम थी। आज राजस्थान में 23 हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) क्षमता तैयार है, लेकिन ग्रिड केवल 18,900 मेगावाट ही निकाल सकता है, जिससे 4,300 मेगावाट क्षमता अप्रयुक्त रह जाती है। उच्च क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनें दशकों पहले कोयला और पनबिजली संयंत्रों के लिए डिजाइन की गई थी जो लगातार चलती थीं। अब स्वच्छ ऊर्जा में सौर और पवन ऊर्जा दिनभर मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। बिजली के प्रवाह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता को इनकी जरूरत के मुताबिक लचीला बनाया जाना चाहिए। ग्रिड ऑपरेटरों का मूल्यांकन उपभोक्ता-पोषित बुनियादी ढांचे के प्रभावी उपयोग के आधार पर किया जाना चाहिए।

धनेन्द्र कुमार
विश्व बैंक के बोर्ड पर भारत के पूर्व कार्यकारी निदेशक
@patrika.com

रियल-टाइम मॉनिटरिंग, डायनेमिक असेसमेंट और स्मार्ट कंट्रोल जैसी पद्धतियां अपनानी चाहिए। नवीकरणीय क्षमता का भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। बिजली बिल भरने वाले आम आदमी के लिए यह देखना है कि सौर ऊर्जा के सस्ता होने के बावजूद बिल कम क्यों नहीं हो रहे। बिजली लाइनें बनी हुई हैं, सोलर प्लांट तैयार है और सूरज चमक रहा है। ऐसे में हमें बस बिजली को प्रवाहित होने देने की जरूरत है।

प्रसंगवश

कानून की घड़ी अफसरों की कलाई से चले तो बदइंतजामी होना तय

चिंता यह भी है कि शराब दुकानों को लेकर फैसले दबाव में होने लगेंगे

राजस्थान में आबकारी नीति में शराब दुकानों के 'संचालन समय का अधिकार' सीधे आबकारी आयुक्त या विभागीय अधिकारियों को देने का प्रस्ताव है। पहली नजर में इसे प्रशासनिक प्रक्रिया का लचीलापन कहा जा सकता है, लेकिन गहराई से देखें तो यह निर्णय विवेकाधीन सत्ता की ओर बढ़ता कदम है। अब तक शराब दुकानों का समय स्पष्ट और सार्वजनिक नियम के तहत संचालित होता था। आम नागरिक, दुकानदार और प्रशासन- तीनों के लिए यह तय था कि दुकान कब खुलेगी और कब बंद होगी। नई व्यवस्था में यह स्पष्टता टूटती है और उसकी जगह जांच, संतोष और विवेक जैसे शब्द ले लेते हैं, जो कागज पर भले सुशासन लगें, जमीनी हकीकत में अक्सर भेदभाव और मनमर्जी का रास्ता खोलते हैं। जब संचालन समय किसी अधिकारी के निर्णय पर निर्भर होगा तो जाहिर है कि हर क्षेत्र में अलग-अलग नियम बनाए जाएंगे। इसे नीति नहीं कहा जा सकता। यह तो अफसर तय करेंगे कि कहां दुकान रात 8 बजे बंद होगी और कहां 10 या 11 बजे तक खुलेगी। एक देश, एक चुनाव की ओर बढ़ते देश में एक राज्य एक नियम की भावना आखिर कमजोर क्यों की जा रही है? कानून की घड़ी अफसर की कलाई से चले तो इसे व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। जाहिर है जहां 'अनुमति' होगी, वहां 'लेन-देन' का जोखिम भी होगा। दुकान का समय बढ़वाने या बनाए रखने के लिए दबाव, सिफारिश और सौदेबाजी की गुंजाइश पैदा होगी। शराब कारोबार पहले ही संवेदनशील क्षेत्र है- ऐसे में यह निर्णय भ्रष्टाचार के लिए नया दरवाजा खोल सकता है। शराब दुकानों के देर रात तक खुले रहने से सामाजिक समरसता के भंग होने के आसार रहेंगे जिसका असर कानून-व्यवस्था पर भी होना तय है। घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटना और सार्वजनिक शांतिभंग होने जैसी समस्याएं तो कम होने के बजाय बढ़ने वाली ही होंगी। चिंता यह भी है कि शराब दुकानों को लेकर फैसले तथ्यों से अधिक प्रभाव के आधार पर होने लगेंगे। यदि सरकार का उद्देश्य अवैध बिक्री रोकना और राजस्व बढ़ाना है, तो इसका समाधान स्पष्ट, समान और सार्वजनिक नियमों में है- न कि ऐसे प्रावधानों में, जो भविष्य में विवाद, असंतोष और भ्रष्टाचार को जन्म दें। याद रखना होगा कि सुशासन नियमों से ही चलता है।

- राजीव जैन
rajiv.jain@in.patrika.com

आपकी बात

खुलकर अपनी बात कहें

रिश्तों में आई भावनात्मक दूरियों को कम करने के लिए खुलकर बातचीत करनी चाहिए। सहानुभूति दिखाएं और साथ में क्वालिटी समय बिताएं। एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, गलतफहमियों को शांति से सुलझाना और सक्रिय रूप से सुनना आवश्यक है। छोटे-छोटे सकारात्मक प्रयासों, विश्वास और माफी के माध्यम से प्रेम को फिर से जीवंत किया जा सकता है। - **दीपू पाटीदार,** झालावाड़

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'रिश्तों में आई भावनात्मक दूरियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/wjr1n

समसामयिक विषयों पर पाठकों के विचार आमंत्रित हैं। चुनिंदा विचार प्रकाशित किए जाएंगे।
ईमेल करें: edit@epatrika.com

भू-राजनीति और व्यापार दोनों देशों का अमरीका पर निर्भरता कम करने की दिशा में माना जा रहा अहम कदम

भारत-यूरोप के लिए गेमचेंजर साबित होगी 'मदर ऑफ ऑल डील्स'

डॉ. एन.के. सोमानी
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
@patrika.com

सात दशकों की लंबी अवधि और वार्ताओं के जटिल दौर के बाद अंततः भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद दोनों देशों का व्यापार 200 अरब डॉलर की नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अमरीका की संरक्षणवाद की नीति और ट्रंप टैरिफ टेरर के बीच भारत-ईयू के इस करार को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है।

यह समझौता अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। यही वजह है कि समझौते पर मुहर से ठीक पहले उन्होंने ईयू को चेताया कि यूरोप खुद के खिलाफ जंग को फंड कर रहा है। ट्रंप का आरोप है कि यूक्रेन युद्ध में भारत रूस की मदद कर रहा है। वैश्विक जीडीपी और करीब दो अरब लोगों को जोड़ने वाला यह बड़ा व्यापार समझौता है। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से आपसी व्यापार वाली 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम या समाप्त किया जा सकेगा। इससे भारत का माल यूरोप के 27 देशों के बड़े और संपन्न बाजारों तक पहुंच सकेगा।

भारत के कपड़ा, दवा, पेट्रोलियम उत्पाद, इस्पात और मशीनरी उद्योग को फायदा होगा। हालांकि डेयरी और फार्म इंडस्ट्री पर अभी स्थिति साफ नहीं है। डेयरी और कृषि सेक्टर को लेकर दोनों पक्ष किस रूप में आगे बढ़ेंगे है यह भविष्य के गर्भ में है। भारत यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों के बीच 136.53 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 डॉलर था। समझौते के बाद भारत का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ सकेगा। यूरोप भारत के लिए सेवाओं के निर्यात का एक बड़ा संभावित बाजार भी है। यह समझौता भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों, एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र के लिए बड़े अवसर खोलने के साथ-साथ इंजीनियरिंग निर्यात का भी विस्तार करता है। ईयू भारत का बड़ा निवेशक भी है। कहा जा रहा है कि भारत-ईयू व्यापार समझौता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीए) में भी मददगार होगा।

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते की नींव साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान रखी गई थी। जून 2007 में भारत और ईयू के बीच ब्रॉड-बेस्ट बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बीटीआइए पर बातचीत शुरू हुई। 2013 तक 15 दौरों की वार्ता के बावजूद ऑटोमोबाइल, स्पिरिट्स, डेटा सिक्योरिटी, वीजा नियमों और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। करीब आठ वर्षों तक वार्ता की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में पड़ी रही। साल 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वार्ता का दौर फिर से शुरू हुआ। इसके बाद बदलते वर्ल्ड ऑर्डर, वैश्विक तनावों और ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण भारत-ईयू की मुश्किलें बढ़ रही थीं। भारत अमरीका का 50 फीसदी टैरिफ झेल रहा है। भारत का अमरीका के साथ व्यापार सरप्लस है। 50 प्रतिशत टैरिफ के कारण भारत को भारी नुकसान हो रहा है।

नुकसान की भरपाई के लिए भारत अमरीका जैसे बड़े मार्केट की तलाश में था। अब उसे यूरोप जैसा बड़ा बाजार (20 ट्रिलियन डॉलर) मिल गया है। वहीं, यूरोप भी ट्रंप की नीतियों के कारण दबाव में है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने वाले देशों पर दस प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यूरोप भी अमरीकी बाजार का विकल्प तलाश रहा था। एफटीए के बाद दोनों की अमरीका पर निर्भरता कम हो जाएगी। भारत अब तक 17 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंटस या फिर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंटस पर साइन कर चुका हैं। इसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। जल्द ही कनाडा के साथ बातचीत शुरू होने वाली है। व्यापार समझौतों के परिणाम संतोषजनक रहे हैं। पिछले दिनों ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता(सीईपीए) किया। इसके बाद ओमान में भारत का 99 प्रतिशत से ज्यादा निर्यात टैरिफ मुक्त हो जाएगा। दिसंबर की शुरुआत में पुतिन की भारत यात्रा के दौरान मॉस्को और नई दिल्ली के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर सहमति बनी।

'मदर ऑफ ऑल डील्स' दोनों क्षेत्रों के लोगों, व्यवसायों और निवेशकों के लिए बड़े अवसर पैदा करेगी ऐसी उम्मीद है।

छत्तीसगढ़

विधानसभा का बजट सत्र 23 से 20 मार्च तक, 15 बैठकें

पत्रिका ब्यूरो @रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। 20 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। माना जा रहा है कि 27 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 का मुख्य बजट पेश कर सकते हैं। वहीं 23 फरवरी को सत्र की शुरुआत राजयपाल रमेन डेका के अभिभाषण से होगी। इसमें वे सरकार के विजन, योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी पेश करेंगे। इसके अलावा जनहित से जुड़े मुद्दों, नए विधेयकों और अनुपूरक बजट को लेकर भी सदन में तीखी बहस होने की संभावना है।

हादसा

देर रात युवक पर तीन भालुओं का हमला, हालत गंभीर

पत्रिका ब्यूरो @अंबिकापुर. बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवदांड़ में बुधवार रात एक युवक पर तीन भालुओं ने हमला कर दिया। उसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।जानकारी के अनुसार विरेंद्र यादव (22) बुधवार रात करीब 11 बजे शौच के लिए घर से बाहर खेत की ओर गया था। शौच कर वापस लौटते समय झाड़ियों में छिपे तीन भालुओं ने अचानक उस पर हमला कर दिया। भालुओं ने उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हमले के दौरान युवक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे मृत समझकर भालू वहां से चले गए। लगभग 45 मिनट बाद जब युवक को होश आया तो वह किसी तरह उठकर घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

भारत माला प्रोजेक्ट

मुआवजा न मिलने से निराश किसान ने की आत्महत्या की कोशिश

पत्रिका ब्यूरो @जांजगीर. भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन का मुआवजा न मिलने से परेशान अकलतरा थाना क्षेत्र के सांकर गांव के किसान अनुराग सिंह ने गुरुवार को फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। पहले उसे अकलतरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। फिर उसे बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया। अनुराग सिंह के मुताबिक उसे भारतमाला प्रोजेक्ट में उसकी जमीन निकली है उसका उसे मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा उसे धान खरीदी के लिए उसका टोकन अब तक नहीं कटा इसलिए उसने खुदकुशी की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि उसकी इस निर्णय से गांव के सभी किसानों का टोकन कट गया।

नई पहल

धान खरीदी में एआई का उपयोग, गड़बड़ी रोकने में मददगार

रायपुर@पत्रिका. धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के लिए मार्कफेड ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सीसीटीवी निगरानी और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) का उपयोग किया जा रहा है। अब राज्य के 2,739 खरीदी केंद्रों पर धान की रीयल-टाइम निगरानी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली है, जो किसानों के हितों की सुरक्षा करते हुए सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

डेटा डिकोडेड | केंद्र सरकार के बजट से पहले पत्रिका का खास सर्वे

मध्यम वर्ग चाहे महंगाई से राहत, युवा नौकरी और महिला स्व-रोजगार

बजट 2026-27

केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ के लोगों की अपेक्षा, रखे विचार

केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत उम्मीद है। इसे जानने के लिए पत्रिका ने प्रदेशभर में ऑनलाइन सर्वे किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। अलग-अलग वर्ग के लोगों की बजट से अलग-अलग उम्मीदें हैं।

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

रायपुर. केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपनी सरकार का मुख्य बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जेन जी से लेकर मध्यम वर्गीय परिवार, महिलाओं और किसानों को कई उम्मीद की किरण नजर आ रही है।

मध्यम वर्गीय परिवार को केंद्र के बजट से टैक्स और महंगाई का बोझ कम करने की उम्मीद है। वहीं युवाओं का मानना है कि उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले, जिससे कि वे भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकें। महिलाओं का मत है कि उन्हें स्व-रोजगार के अवसर मिले। ऐसे में बजट से पहले पत्रिका ने एक सर्वे किया। इसमें युवा, महिला, किसान, व्यापारी, प्राइवेट व सरकारी नौकरी पेशा के साथ प्रोफेशनल वर्ग के लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया और केंद्रीय बजट को लेकर अपनी सोच पत्रिका के साथ साझा की।

लोगों का मानना- संसाधनों के अनुपात में नहीं मिलता बजट में हिस्सा

1. क्या आपको लगता है कि केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को उसके संसाधनों के अनुपात में पर्याप्त हिस्सा मिलता है?

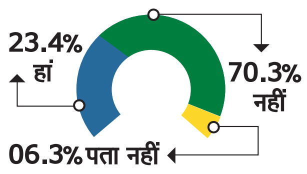

2. युवाओं के लिए बजट में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए?

1. सरकारी नौकरियां
2. निजी क्षेत्र रोजगार
3. स्टार्टअप फंड
4. स्किल ट्रेनिंग
5. स्थानीय उद्योग
6. आईटी हब

3. कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट में कौन-सा कदम सबसे जरूरी है?

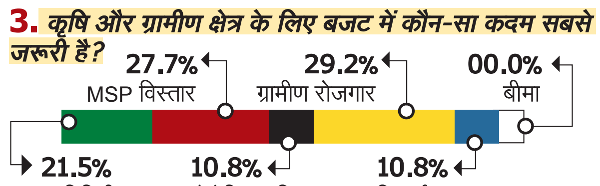

4. छत्तीसगढ़ के लिए बजट 2026 में सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए?

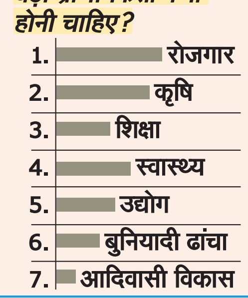

5. खनन और पर्यावरण संतुलन के लिए क्या सुझाव हैं?

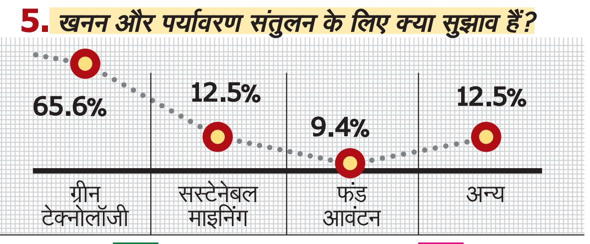

6. आदिवासी कल्याण के लिए बजट में किस स्कीम की जरूरत है?

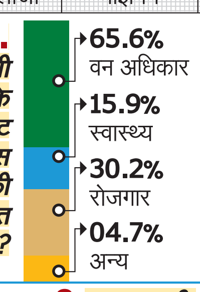

7. महिला सशक्तिकरण के लिए क्या नई स्कीम्स जरूरी हैं?

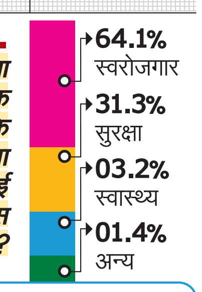

8. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य के लिए विशिष्ट निवेश क्या होना चाहिए?

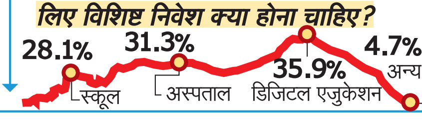

9. क्या शहरी मध्यम वर्ग पर टैक्स और महंगाई का दबाव बढ़ा है?

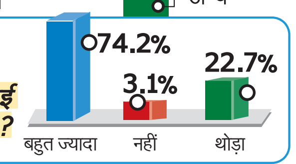

बेरोकटोक: ओडिशा सीमा से तस्करी खुलेआम, पुलिस मुखबिरों के भरोसे

नशे का कॉरिडोर महासमुंद रूट

04 चेक पोस्ट पर नजर, बाकी रास्ते बेधड़क तस्करी

ग्राउंड रिपोर्ट

जितेन्द्र सतपथी
patrika.com

लाइव पड़ताल... जांच चौकियां सिर्फ कागजों पर ही

महासमुंद. छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर स्थित महासमुंद जिला अब नशे की तस्करी के सुरक्षित कॉरिडोर की पहचान बनता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ओडिशा से गांजा तस्करी बेखौफ, बेधड़क और बेरोकटोक जारी है, जबकि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस व्यवस्था मुखबिर की सूचना मिले तो कार्रवाई, नहीं मिले तो चुप्पी की नीति पर चलती नजर आ रही है। जमीनी हकीकत यह है कि जिले में मौजूद चार स्थायी चेकिंग प्वाइंट को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा से जुड़े अधिकांश रास्ते तस्करों के लिए खुले हाईवे बने हुए हैं। इन रास्तों पर न नियमित पुलिस गश्त है, न वाहनों की जांच और न ही मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की कोई ठोस रणनीति। पत्रिका ने हकीकत जानने के लिए विभिन्न नाकों का मुआयना किया तो चौंकाने वाले हालात सामने आए। जिन जांच चौकियों पर गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस बल होना चाहिए, वहां अवैध धान रोकने के लिए नगर सैनिक या मंडी कर्मचारी तैनात मिले। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने साफ कहा कि पुलिस यहां कभी-कभार ही आती है। इस ढीली व्यवस्था का सीधा फायदा तस्कर उठा रहे हैं। महासमुंद जिले की सीमा से जुड़े रेहटीखोल, सिरपुर, राजाडीह, साल्हेझरिया, पलसापाली, कुदारीबाहरा, लारीपुर, टेमरी और नर्रा जैसे कई गांव ओडिशा सीमा से महज आधा से एक किलोमीटर की दूरी पर हैं। नाले पार करते ही राज्य बदल जाता है और यही नजदीकी तस्करों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता बन गई है। चार स्थाई प्वाइंट के दायें-बायें में शार्टकट रास्ते भी हैं, यहां से पुलिस की निगाह है, लेकिन इस रास्ते पर कोई चेकिंग नहीं होती। सूचना मिलने पर पुलिस सक्रिय होकर चेकिंग प्वाइंट लगाती है।

साल्हेझरिया: सूचना मिले तो ही कार्रवाई : बसना से 14 किमी दूर साल्हेझरिया जांच नाका है। यहां पुलिस केवल मुखबिर की सूचना मिलने पर ही सक्रिय होती है। जब इस जांच नाका का मुआयना किया तो लोग बेरोकटोक आवाजाही करते दिखे। पिकअप के अलावा बड़े वाहन भी आसानी से पार हो रहे थे। जांच करने वाला कोई नहीं था। नाका से 500 मीटर बाद ओडिशा सीमा शुरू हो जाती है।

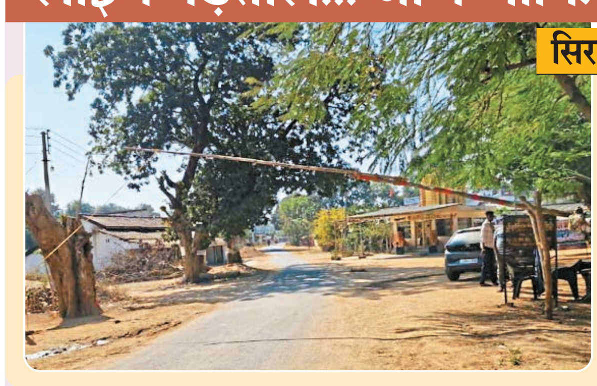

सिरपुर सिर्फ नाम की चौकी

सरायपाली से 20 किमी दूर सिरपुर जांच नाका मुख्य मार्ग पर स्थित है, लेकिन यहां पुलिस की जगह मंडी कर्मचारी तैनात मिले। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस की मौजूदगी कभी-कभार होती है, जिससे तस्कर बेखौफ होकर आवाजाही करते हैं। अभी तो मादक पदार्थों की तस्करी हो रही या नहीं, की जांच करने वाला भी कोई नहीं है।

पलसापाली पुलिस चौकी है, पुलिस नहीं

बसना से 17 किमी दूर पलसापाली में पुलिस चौकी तो बनी है, लेकिन गांजा तस्करी रोकने के लिए पुलिस बल नदारद है। सीमा पर दिन-रात आवाजाही होती है, लेकिन वाहनों की जांच नियमित नहीं हो रही है। पड़ताल में दो नगर सैनिक ही मौके पर मिले। वे अवैध धान की निगरानी के लिए मौजूद थे। एक-दो दिन में पुलिस पांच-दस मिनट के लिए आती है। चौकी से नाला पार करते ही ओडिशा का गांव जगदलपुर शुरू हो जाता है।

राजाडीह: 3 शॉर्टकट, कोई निगरानी नहीं

ओडिशा सीमा से मात्र 2-3 किमी दूर राजाडीह गांव से तीन शॉर्टकट रास्ते सीधे ओडिशा जाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पास के ओडिशा गांवों में शराब और नशीले पदार्थ खुलेआम बिकते हैं, लेकिन न कोई जांच होती है न पूछताछ। गांव पार करते ही धरसा रास्ता है।

कुदारीबाहरा: दो रास्ते, शून्य सुरक्षा

यहां से ओडिशा जाने के दो रास्ते हैं। दिनभर वाहनों की आवाजाही होती है। 1 किमी बाद ओडिशा सीमा शुरू हो जाती है। कुदारीबाहरा के बाद ओडिशा का पहला गांव भैंसा दरहा आता है। इस गांव से ओडिशा आने-जाने वाले रास्ते भी तस्करों के लिए महफूज हैं।

आंकड़े कर रहे हालात बयां

पिछले साल महासमुंद पुलिस ने 107 मामलों में 204 आरोपियों से 3177 किलो गांजा (कीमत करीब 5.59 करोड़ रुपए) जब्त किया। 80 वाहन भी पकड़े गए। इस साल महज 15 दिनों में 1831 किलो 610 ग्राम गांजा (अनुमानित कीमत 9.15 करोड़ रुपए) जब्त किया गया। यानी औसतन रोज 122 किलो गांजा पकड़ा गया, जो इस बात का संकेत है कि कितना माल बिना पकड़े निकल रहा होगा।

जिले में रेहटीखोल, पलसापाली, टेमरी और नर्रा में स्थायी चेकिंग प्वाइंट हैं, जहां 24 घंटे बल तैनात रहता है। अस्थायी प्वाइंट पर अचानक चेकिंग भी की जाती है। गांजा तस्करी रोकने के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है। बेरियर के आसपास के कच्चे रास्तों पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है।

-प्रतिभा तिवारी, एडिशनल एसपी, महासमुंद

शुभंकर 'गजरु' का अनावरण: सीएम का ऐलान- सरगुजा मनोयोग-उमंग के साथ आयोजन को तैयार

बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर सरगुजा में भी होगा खेलों का आयोजन

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को मंत्रालय में एक समारोह में बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले सरगुजा ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह शुभंकर "गजरु" का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, अब बस्तर की भांति सरगुजा की खेल प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का सशक्त मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री ने 12 खेल विधाओं में लगभग 3 लाख 50 हजार खिलाड़ियों के पंजीयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, यह संख्या सरगुजा अंचल के युवाओं के उत्साह, ऊर्जा और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने कहा, बस्तर ओलम्पिक में जनभागीदारी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान दिलाई है और अब वही उत्साह सरगुजा ओलंपिक को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पंजीयन से यह स्पष्ट है कि सरगुजा पूरे मनोयोग और उमंग के साथ इस आयोजन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने आयोजन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी लेते हुए सफल आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं।

ट्रेनिंग अकादमी में मिलेगा सीधे प्रवेश

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, इस आयोजन से सरगुजा के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का अच्छा मंच मिलेगा। इसके विजेता खिलाड़ियों को राज्य की प्रशिक्षण अकादमियों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें यूथ आइकॉन घोषित कर युवाओं व बच्चों को खेलों से जुड़ने और खेलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मौसम: नया पश्चिमी विक्षोभ 2 फरवरी से

आज से फिर बढ़ सकती है ठंड, 3 डिग्री तक गिरेगा पारा

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

रायपुर. देश के अनेक हिस्सों में जहां कोहरा और कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में उमस ने परेशान कर रखा है। शुक्रवार से इससे राहत मिलने के आसार हैं। तापमान में थोड़ा गिरावट आने की उम्मीद है। अभी राजधानी समेत मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। इसके बाद आगामी 3 दिनों में इतना ही तापमान बढ़ेगा। 2 फरवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने की उम्मीद से प्रदेश में भी इसका असर हो सकता है। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं, इस कारण वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश इससे अछूता है, हालांकि यह राहत की बात भी है। जगदलपुर प्रदेश में सबसे ज यादा गर्म रहा और यहां का तापमान 31.1 डिग्री रहा। सबसे ज यादा ठंड अंबिकापुर में रही। वहां पारा 11.9 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट भी है। इसका कारण बादल छाना है।

कुछ जगहों पर कोहरे के आसार: मौसम विज्ञान केंद्र लालपुर के मौसम विज्ञानियों के अनुसार शुक्रवार को एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

न्यूनतम तापमान

स्थान	तापमान
रायपुर	18.3
बिलासपुर	16.2
पेंड्रारोड	16.0
अम्बिकापुर	11.9
जगदलपुर	13.7
दुर्ग	13.4

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

ऑपरेशन: बीजापुर के जंगल में फोर्स से मुठभेड़

फोर्स ने 7 सात लाख के दो इनामी नक्सली मारे गिराए

पत्रिका ब्यूरो @बीजापुर. दक्षिण बीजापुर क्षेत्र के पामेड़ थाना अंतर्गत कावरगट्टा-गुंडराजगुड़ेम जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो इनामी नक्सली मारे गए। पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि पामेड़ एरिया कमेटी से जुड़े सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना पर बुधवार की शाम डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। अभियान के दौरान गुरुवार की सुबह करीब 7 बजे मुठभेड़ के बाद दो वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए।

प्रदीप उर्फ जोगा

एके-47 और विस्फोटक बरामद

मुठभेड़ स्थल से दोनों के शवों के साथ एक एके-47 रायफल, 9 एमएम पिस्टल, भारी मात्रा में गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली सामान बरामद किया गया है।

फैसला: 12 वीं बोर्ड परीक्षा में 97 फीसदी अंक हासिल कर सुर्खियों में रही

पोरा बाई नकल प्रकरण में 4 को 5-5 साल की सजा, 2008 में बनी थी 12 वीं टॉपर

पत्रिका ब्यूरो @जांजगीर-चांपा. माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2008 की बोर्ड परीक्षा के कक्षा बारहवीं में नकल के माध्यम से टॉपर आने वाली पोरा बाई सहित 4 आरोपियों को कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को आखिरकार 18 साल बाद फैसला देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।

इस मामले में पोरा बाई ने कक्षा बारहवीं की परीक्षा में 500 अंकों में 484 अंक लाकर लगभग 97 फीसदी अंक प्राप्त की थी। जिससे वह सुर्खियों में आई थी। आखिरकार मामले की शिकायत के बाद जांच की गई। जांच में बोर्ड परीक्षा से जुड़े सवालों की जांच पड़ताल में उसकी हैंडराइटिंग मिस मैच होने से आखिरकार मामला नकल का होना स्पष्ट हो गया। केंद्राध्यक्ष सहित अन्य तीन शिक्षकों ने नकल कराने में उसकी मदद की थी। इसके चलते उन्हें भी सजा हुई है। मामले में कुल 9 आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी शिक्षक की मौत हो चुकी है। साथ ही चार अन्य को नकल से जुड़े होने का साक्ष्य नहीं मिलने से उन्हें बरी कर दिया गया है।

जज ने टिप्पणी में कहा

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गणेश राम पटेल ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि आरोपियों ने केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल के विरूद्ध अपराध नहीं किया बल्कि उन छात्रों के विरुद्ध भी अपराध किया है, जो अपनी भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।

कवायद | पर्यटन विभाग का उद्देश्य चित्रकोट को वैश्विक स्तर पर पुनर्विकसित करना

'चित्रकोट' के सौंदर्य को ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी

संतराम साहू
patrika.com

रायपुर. अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध बस्तर का प्रमुख जलप्रपात चित्रकोट ग्लोबल पर्यटन सूची में शामिल करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने चित्रकोट को ग्लोबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए एक मसौदा तैयार रहा है। जिसे पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि चित्रकोट को ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल किया जाता है, इसका पुनर्विकसित किया जाएगा। इसके लिए विभाग को 250 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा राज्य सरकार भी चित्रकोट के विकास के लिए इतनी ही राशि फंडिंग कर सकती है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, चित्रकोट इंडिजिनस नेचर रिट्रीट नामक एक व्यापक प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

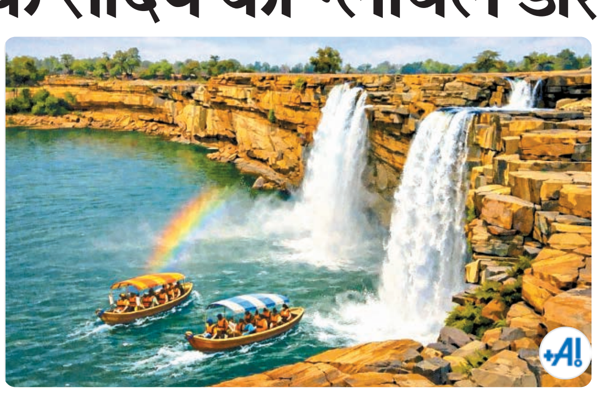

चित्रकोट में बनाई जाएगी टेंट सिटी

विभाग के अधिकारियों के अनुसार चित्रकोट में टेंट सिटी के विकास की योजना है, जिसके तहत चित्रकोट जल प्रपात के पास साहसिक गतिविधियों के साथ कम से कम 50 लग्जरी टेंट लगाए जाएंगे। फिक्की के सहयोग से छत्तीसगढ़ ट्रैवल मार्ट नामक एक वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा। यह आयोजन बीटूबी पर्यटन को बढ़ावा देने पर केन्द्रित होगा, जिसके तहत भारतीय राज्यों के 200 से अधिक टूर ऑपरेटरों को आकर्षित करने की योजना है।

भारत का नियाग्रा है चित्रकोट

चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह इंद्रावती नदी पर बना सबसे प्रमुख जलप्रपात है। जो 90 फीट की ऊंचाई और घोड़े की नाल के आकार में गिरता है। यह जगदलपुर से लगभग 38-40 किमी दूर इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज़्यादा जल की मात्रा वाला झरना है। यह वर्षा ऋतु जुलाई से अक्टूबर में सबसे अधिक आकर्षक होता है।

फर्जीवाड़ा: जांच के लिए छानबीन समिति से की शिकायत

जाति की छानबीन करने वाली समिति के अफसर पर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

रायपुर. जाति की छानबीन करने वाली समिति के अधिकारी पर ही फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप लगा है। इस मामले में अधिकारी केके कटारे की शिकायत की गई है। उच्चस्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के साथ ही अधिवक्ता विजय मिश्रा ने यह शिकायत की है। इसमें बताया गया है कि कटारे मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विकास आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर/सिविल लाइन में पदस्थ हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र तुमसर जिला भंडारा में हुआ। इनकी नियुक्ति 1994 में अविभाजित मध्यप्रदेश में लोकसेवा आयोग के माध्यम से विशेष भर्ती अभियान के तहत अनुसूचित जाति वर्ग में सहायक यंत्री के पद पर हुआ था। इसके बाद लगातार पदोन्नत होते हुए मुख्य अभियंता के पद पर पहुंच चुके हैं और इन पदों पर आरक्षित पदों का लाभ लेते हुए प्रभारी प्रमुख अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। महाराष्ट्र में जन्म लेने के कारण छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में आज अनुसूचित जाति वर्ग का (आरक्षित वर्ग) का लाभ देय नहीं होगा।

कई बार हुई जांच

इतने सालों तक नौकरी करने के दौरान जाति प्रमाण-पत्र की कई स्तरों पर जांच हो चुकी है। जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं मिलने के बाद यह प्रमाणित होता है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। जब भी किसी तरह का टेंडर जारी होता है उसके बाद ही इस तरह का शिकायतें होती हैं।

-केके कटारे, प्रमुख अभियंता, पंचायत-ग्रामीण विकास विभाग

कोर्ट ने पूछा-

डिप्लोमाधारियों को एवीएफओ के रिक्त पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं?

जबलपुर @ पत्रिका. मप्र हाईकोर्ट ने सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, एवीएफओ के रिक्त पदों पर नियुक्ति से डिप्लोमाधारियों को वंचित किए जाने के रवैये को चुनौती पर जवाब-तलब किया। जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की सिंगल बेंच ने इसके लिए राज्य शासन को 10 दिन का समय दिया है। अगली सुनवाई नौ फरवरी को तय की गई है। याचिकाकर्ता रीवा के रवि कुमार यादव सहित प्रदेश के अन्य की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता विनायक शाह ने दलील दी कि विभाग ने कुल 550 पदों के 499 अभ्यर्थियों को ही दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया। इनमें से 321 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए। बाकी डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया। बाद में वेटिंग में शामिल केवल 70 को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। इसमें से केवल 38 अभ्यर्थी पात्र पाए गए। इस तरह वर्तमान में 191 पद खाली होते हुए भी याचिकाकर्ताओं को वेटिंग लिस्ट तक में शामिल नहीं किया गया। जबकि, वे डिप्लोमाधारी होते हुए एवीएफओ के पद नियुक्त होने के लिए पात्र हैं।

न्यूज विंडो

महिला फेडरेशन का राज्य सम्मेलन आज राजधानी में

भोपाल @ पत्रिका. भारतीय महिला फेडरेशन मप्र का राज्य सम्मेलन शुक्रवार को राजधानी के हिन्दी भवन में होगा। इस अवसर पर संगठन का पुनर्गठन कर महिलाओं के अधिकार , समानता, स्वतंत्रता, बेहतर आर्थिक स्थिति के मुद्दों पर विचार विमर्श कर आगामी कार्यक्रमों और आंदोलन के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। सेवा निवृत्त एडीजीपी, गांधीवादी चिंतक अनुराधा शंकर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। राज्य सम्मेलन का उदघाटन भारतीय महिला फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव निशा सिद्धू करेंगी। राष्ट्रीय सचिव अरुणा सिन्हा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी।

'प्रतिभा खोज' से कांग्रेस तलाशेगी हुनरमंद कार्यकर्ता

भोपाल @ पत्रिका. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय एवं रचनात्मक बनाने के लिए प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है। यह अभियान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर महामंत्री डॉ. संजय कामले के मार्गदर्शन में संचालित किया जाएगा। कामले ने बताया, इसके तहत ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा जो चुनावी प्रक्रिया से इतर रहकर संगठन के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने के इच्छुक हैं तथा जिला व प्रदेश स्तर पर संगठन को समय दे सकते हैं। इसमें साहित्यिक एवं रचनात्मक विधाओं से जुड़े गायक, वाद्य यंत्र बजाने वाले, लेखक, कवि, शायर या कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन करने वालों को कांग्रेस के साथ जुड़कर कार्य करने के लिए आमंत्रित करेंगे।

असमाजिक तत्वों को प्रदेश में भाजपा का संरक्षण: सपा

भोपाल @ पत्रिका. कानून व्यवस्था के मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मनोज यादव ने प्रेसवार्ता कर पुलिसिंग पर सवाल खड़े किए। यादव ने कहा कि असामाजिक तत्वों को सत्ता का खुला संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रीवा के मनगवां भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति पर हमले का प्रयास लोकतंत्र पर आघात है। इसी के साथ यादव ने सतना जिले में भाजपा पार्षद पति पर महिला से दुष्कर्म के आरोप और नागौद में भाजपा मंडल अध्यक्ष पर महिला से बर्बरता पर चिंता व्यक्त की है।

यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस: समीक्षा रिपोर्ट देने वाली संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं राज्यसभा सांसद सिंह

दिग्विजय की सफाई, कहा- यूजीसी ने नहीं मानी सभी सिफारिशें, अब समाधान भी उसी पर निर्भर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. यूजीसी के नए नियमों पर देशभर में शुरू हुए विवाद और सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के विरोध के बाद इस पर सिफारिशें देने वाली संसदीय समिति भी घेरे में आ गई है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हैं। लगातार बढ़ रहे विरोध के बीच दिग्विजय सिंह ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि समिति की सभी सिफारिशें यूजीसी ने नहीं मानी हैं। उन्होंने कहा कि झूठे मामलों पर सजा हटाने का फैसला यूजीसी का था, इसका संसदीय समिति से कोई संबंध नहीं है। सामान्य वर्ग को सूची से बाहर रखने पर भी समिति ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि यदि यूजीसी ने भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा और उदाहरण तय कर दिए होते, तो इससे न केवल वंचित वर्गों को सुरक्षा मिलती बल्कि फर्जी मामलों की आशंका भी काफी कम हो जाती। यही बात संसदीय समिति ने कही, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की पहल और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार और यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए ड्राफ्ट इक्विटी रेगुलेशंस जारी किए थे। इसका उद्देश्य कैंपस में जाति, सामाजिक और अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को रोकना था। समिति ने माना कि नियम सही दिशा में हैं, लेकिन उन्हें सख्त व स्पष्ट बनाए जाने की जरूरत है।

यूजीसी ने तीन सिफारिशें ही मानीं: दिग्विजय

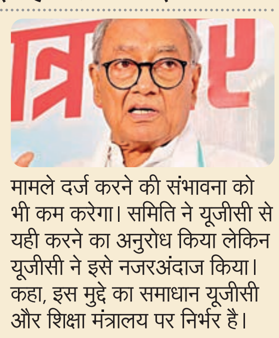

दिग्विजय के अनुसार, यूजीसी ने तीन सिफारिशें को स्वीकार किया लेकिन, इक्विटी कमेटी में एससी-एसटी-ओबीसी प्रतिनिधित्व बढ़ाने और भेदभाव की विस्तृत परिभाषा तय करने जैसी सिफारिशें को नजरअंदाज कर दिया। सिंह ने कहा कि वास्तव में, यह स्पष्ट करना कि किन कृत्यों और मामलों को भेदभाव माना जाएगा, न केवल छात्रों के लिए सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि विनियमों का दुरुपयोग करके फर्जी मामले दर्ज करने की संभावना को भी कम करेगा। समिति ने यूजीसी से यही करने का अनुरोध किया लेकिन यूजीसी ने इसे नजरअंदाज किया। कहा, इस मुद्दे का समाधान यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय पर निर्भर है।

समिति ने की थी यह पांच सिफारिशें

1. ओबीसी छात्रों और अन्य के उत्पीड़न को भी जाति-आधारित भेदभाव में शामिल किया जाए।
2. दिव्यांगता को भी भेदभाव के आधार के रूप में मान्य किया जाए।
3. इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक हो और निर्णय निष्पक्ष हों।
4. भेदभाव की स्पष्ट पहचान और उदाहरण नियमों में लिखे जाएं।
5. जातिगत भेदभाव को सार्वजनिक कर, प्रशिक्षण और छात्रों के लिए स्वास्थ्य सहायता व कानूनी मदद दें।

पीएमओ तैयार करवा रहा समेकित पोर्टल

पानी पिलाने का जिम्मा पंचायतों का, केंद्र करेगा सिर्फ निगरानी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. अब केंद्र मध्यप्रदेश समेत दूसरे राज्यों के ग्रामीण इलाकों में पानी की आपूर्ति को लेकर अलग-अलग विभागों की टाला-मटोली को पूरी तरह खत्म करने जा रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद गांव वालों को भरपूर पानी देने का जिम्मा पूरी तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का होगा। इससे ना-नुकुर करने वाले अधिकारी, कर्मचारी नपेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों की पंचायतों में पानी आपूर्ति की पूरी व्यवस्था को केंद्र समेकित पोर्टल पर ऑनलाइन करने जा रहा है। यह काम केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को दिया है। अभी मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों की पंचायतों में पानी से जुड़े प्रकरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसे दूसरे विभागों के बीच अटक जाते हैं, लोगों को परेशान होना पड़ता है। पानी नहीं मिलता, जिसकी शिकायतें राज्यों के अलावा केंद्र तक पहुंच रही है।

पंचायतों के पास आएगा मेंटेनेंस का काम: मंत्री पटेल पंचायतों को पानीदार बनाना होगा, ताकि गर्मी में पानी की किल्लत न हो। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कई बातें साफ कर दी है। इससे राज्यों में सुधार के कामों को गति मिलेगी। अब पानी की टंकियों और पाइप लाइनों की जियो टैगिंग करनी होंगी, भविष्य में मेंटेनेंस का काम भी विभाग के पास ही आएगा।

कोर्ट ने दो हफ्ते में निर्णय को कहा- 10 दिन बीते, अब भी संशय बरकरार

सुप्रीम आदेश के बाद मंत्री शाह में अटकी सरकार, 'बचाव पर संकट'

- मुख्यमंत्री से मंत्री शाह ने की दो मुलाकात, बचाव को लेकर रखे पक्ष
- कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेशर्म टिप्पणी के बाद शाह की बढ़ी मुश्किलें

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं वे भोपाल, दिल्ली और जबलपुर की दौड़ लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी दो बार मुलाकात कर चुके हैं लेकिन अब तक बचने और बचाव का कोई रास्ता नहीं निकला है। उधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री शाह के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति को लेकर निर्णय लिए जाने का जो आदेश दिया था, उसे 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। तीन दिन बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई दो हफ्ते की अवधि भी पूरी हो रही है।

असल में मंत्री शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंदौर के रायकुंडा में कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेशर्म टिप्पणी कर दी थी। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआइआर करनी पड़ी। जिसे मंत्री शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी जहां राहत मिलना तो दूर उनके खिलाफ जांच के लिए एसआइटी गठित करने के आदेश हुए। जांच पूरी हो चुकी है लेकिन सरकार अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे रही है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए अभियोजन पर निर्णय लेने की अवधि तय की है।

सरकार के पास ये दो विकल्प

1. अभियोजन की स्वीकृति दे दी जाए: कानून मामलों के जानकार के अनुसार, सरकार स्वीकृति देती तो मुकदमा चलता रहेगा। ऐसे में सरकार पर निर्भर करेगा कि वह मंत्री को हटाती है या नहीं।

असर: अभियोजन की स्वीकृति देने का मतलब होगा कि सत्ता व संगठन भी मंत्री के बयान को गलत और सेना और कर्नल के खिलाफ मान रहे हैं। नैतिकता के आधार पर मंत्री पर इस्तीफे का दबाव बढ़ेगा। विपक्ष हावी होगा, इसे मुद्दा बनाएगा। आम लोगों की नजरों में भी सरकार की किरकिरी होगी। सुनवाई में यदि आरोप सिद्ध हो गए तो सजा हो सकती है, तब और किरकिरी होगी।

2. अभियोजन की स्वीकृति से मना कर दे: सरकार चाहे तो अभियोजन की स्वीकृति से मना कर सकती है। पूर्व में कुछ आइएएस, जनप्रतिनिधियों के मामले में ऐसा किया था। हालांकि मंत्रियों के मामले में ऐसा नहीं हुआ।

असर: ऐसा किया तो राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जा सकता है कि सत्ता व संगठन मंत्री शाह का बचाव कर रहे हैं। विपक्ष इसे सेना के अपमान से जोड़कर आने वाले चुनावों में भुना सकता है। देश सेवा के प्रति समर्पित आमजन भी असहज महसूस कर सकते हैं।

एक्सपर्ट व्यू

यह विषय बहुत ही गंभीर है। जरूरी नहीं कि यदि सरकार अभियोजन की स्वीकृति से मना करे तो उस निर्णय से सुप्रीम कोर्ट सहमत हो। स्वीकृति नहीं दिए जाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कारण पूछ सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है।

– **वरुण ठाकुर,** अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट

मामले में अब तक

- **11 मई 2025:** मंत्री ने इंदौर के रायकुंडा में ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया, जो अगले ही दिन वायरल हुआ और लोगों ने इसकी निंदा की।
- **13 मई:** मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल हुए, मुख्यमंत्री व तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने तलब किया।
- **14 मई:** हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और आदेश पर देर रात ही इंदौर के मानपुर थाने में केस दर्ज।
- **15 मई:** मंत्री शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां कोर्ट ने भी फटकार लगाई।
- **19 मई:** सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी गठित कर जांच के आदेश दिए। हालांकि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
- **19 जनवरी 2026:** सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अभियोजन की स्वीकृति के लिए दो हफ्ते का समय दिया।

दिल्ली से होगा निर्णय: माना जा रहा है कि मंत्री शाह को लेकर लिए जाने वाला निर्णय दिल्ली से होना है। सत्ता व संगठन द्वारा पूरे मामले में दिल्ली से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है।

पुलिस खोलेगी ड्रोन स्कूल, 50 पुलिसकर्मी बनेंगे मास्टर ट्रेनर

सिंहस्थ मेला में देश की सबसे हाईटेक निगरानी, फिक्स्ड विंग ड्रोन रखेंगे नजर

रूपेश मिश्रा
patrika.com

भोपाल. सिंहस्थ-2028 को दृष्टिगत रखते हुए मप्र पुलिस अभी से युद्ध स्तरीय तैयारियों में जुट गई है। इस बार पुलिस का पूरा फोकस कानून-व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी नवाचारों की मदद लेना है। लिहाजा इसी क्रम में सिंहस्थ मेला परिसर की निगरानी के लिए देश के सबसे तीन हाईटेक फिक्स्ड विंग ड्रोन को मप्र पुलिस ने खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इस ड्रोन की क्षमता ऐसी है कि यह लगातार 6 घंटे तक 100 किमी तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पुलिस ड्रोन के जरिए कई जिलों को कवर कर आसमानी निगाह से भीड़ की निगरानी कर सकती है।

ड्रोन से हो सकेगी लाइव मॉनिटरिंग

एसएसपी रेडियो रियाज इकबाल ने बताया, नए ड्रोन विंग सेटअप तैयार कर रहे हैं। इंदौर में ड्रोन स्कूल बनाया जा रहा है। जहां से मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे। तीन हाईटेक ड्रोन भी वहीं रखे जाएंगे। इनकी खूबी यह है कि यह लंबे समय, लंबी दूरी के साथ दिन और रात दोनों समय उड़ानभर सकेंगे। जिसकी लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। यह हमारे लिए कई क्षेत्रों में उपयोगी होगा।

स्मार्ट पुलिसिंग में मिलेगी मदद

- अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर रियल टाइम निगरानी।
- सिंहस्थ मेला मैदान में भीड़ नियंत्रण और वीआइपी मूवमेंट में मदद होगी।
- आपदा, दंगे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से तेज कार्रवाई।
- ड्रोन के दुरुपयोग से निपटने के लिए एंटी-ड्रोन तकनीक भी होगी।

ऐसे काम करेगा फिक्स्ड विंग ड्रोन

- फिक्स्ड विंग ड्रोन में विमान की तरह बड़े-बड़े पंखे होते हैं। ये मल्टी-रोटर ड्रोन की तुलना में ज्यादा दूरी तय करता है।
- लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं और कम बैटरी खपत में बड़े इलाके की निगरानी कर सकते है।
- यही वजह है कि इन्हें खासकर बॉर्डर पेट्रोलिंग, बड़े सर्च ऑपरेशन और लंबी दूरी की निगरानी में उपयोग करते हैं।

ऐसे तैयार होंगे ड्रोन ऑपरेशन के मास्टर ट्रेनर

ड्रोन विंग को मजबूत करने के लिए इंदौर स्थित पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल (पीआरटीएस) में ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत की जा रही है। इसे प्रदेश का नोडल ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। यहां से प्रदेशभर के लिए ड्रोन पायलट और पे-लोड ऑपरेटर (को-पायलट) तैयार किए जाएंगे। शुरुआती चरण में तकनीकी रूप से दक्ष 50 पुलिसकर्मियों को ड्रोन उड़ाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन्हें सिर्फ ड्रोन ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक की भी जानकारी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के पूरी होने के बाद यही 50 पुलिसकर्मी मास्टर ट्रेनर के रूप में जिलों में पदस्थ किए जाएंगे। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत कुल 7 ड्रोन सेंटर स्थापित किए जाने हैं, जहां से पुलिस ड्रोन संचालन किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी शिकायत

निर्वाचन में लगे आउटसोर्स कर्मियों को नहीं मिला एरियर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. जिले में निर्वाचन जैसे अहम कार्य को जमीन पर संभालने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की मेहनत का अब तक उचित मूल्य नहीं मिल पाया है। 40 कर्मचारियों का करीब 11 महीने का वेतन एरियर लंबित है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) जैसे बड़े अभियान में दिन-रात काम करने के बावजूद कर्मचारियों को न तो समय पर वेतन मिला और न अतिरिक्त कार्य का भुगतान।

कर्मचारियों के अनुसार, एसआइआर के दौरान फील्ड से आने वाले डाटा का सत्यापन, रात में सर्वर पर अपलोडिंग, त्रुटियों का सुधार और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन, यही उनकी दिनचर्या रही। 28 अक्टूबर 2025 के बाद से शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश में भी लगातार काम कराया गया, लेकिन ओवरटाइम या मानदेय का भुगतान नहीं हुआ।

प्रदेश में 11 सौ कर्मी आउटसोर्स पर

प्रदेशभर में निर्वाचन कार्य में 1100 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी सालों से सेवाएं दे रहे हैं। कई कर्मचारी 2016-17 से लगातार निर्वाचन विभाग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें न्यूनतम सुरक्षा और समय पर वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। इंदौर के आउटसोर्स कर्मचारियों ने समस्याओं को लेकर कलेक्टर को पत्र सौंपने के बाद भोपाल जाकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के सामने भी अपनी बात रखी।

निर्वाचन सदन में सौंपा ज्ञापन, एक ही व्यक्ति के नाम 50-50 आपत्तियां

कांग्रेस का आरोप- SIR में आदिवासी, अल्पसंख्यक और विशेष वर्गों पर निशाना

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. एसआइआर में आदिवासी, अल्पसंख्यक और विशेष वर्गों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। खासतौर पर इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी और मुस्लिम नामों पर चुन-चुनकर आपत्तियां डाली गईं। एक ही व्यक्ति के नाम पर 50 से अधिक आपत्तियां, एक ही मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी से 30-50 मतदाताओं के नाम कटवाने के प्रयास किए गए। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 23 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच प्रदेश में हजारों की संख्या में ऑनलाइन और ऑफलाइन आपत्तियां दर्ज की गईं, लेकिन उनका न तो निष्पक्ष निराकरण किया गया। कई जिलों में एक ही दिन में बीएलओ द्वारा 50-50 फॉर्म भरवाए गए। वर्मा ने कहा, एक ही पैटर्न और हैंडराइटिंग में बड़ी संख्या में आपत्तियां डाली गई हैं। अकेले भोपाल के नरेला क्षेत्र में 4,882 आपत्तियां इसी तरीके से दर्ज की गईं, जो इस पूरे प्रकरण को संदेहास्पद बनाती हैं। इस मामले पर निर्वाचन सदन में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन भी सौंपा और जांच कराते हुए निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग की।

एसआइआर की प्रक्रिया में आपत्तियों को लेकर ज्ञापन सौंपता कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल।

यह मांगें रखीं

- फॉर्म-7 के माध्यम से की गई सभी आपत्तियों पर एफआइआर दर्ज हो।
- समूह में डाली गई सभी आपत्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए।
- ऑनलाइन-ऑफलाइन आपत्तियों का जिलेवार विवरण सार्वजनिक करें।
- चुनाव आयोग इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराए।

ईडी ने कारोबारी मनोज परमार का चालान पेश किया

फर्जी दस्तावेज से योजनाओं के नाम 6.20 करोड़ के 18 लोन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. सीहोर के आष्टा के कारोबारी मनोज परमार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ईडी की स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया है। ईडी के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परमार सहित पियूष करारी और चार अन्य लोगों के खिलाफ अभियोग दायर किया है। जिसमें ईडी की जांच में पता चला कि मनोज परमार ने पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक की मदद से पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम और सीएम युवा उद्यमी योजना में फर्जीवाड़ा कर लोन लिया। फर्जी आवेदकों, जाली दस्तावेजों और कोटेशन तैयार कर साल 2016 में कुल 18 ऋण स्वीकृत हुए, जिनकी कुल राशि 6.20 करोड़ रुपए थी, जिनमें से 6.01 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। बता दें सीबीआइ द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद ईड द्वारा इस मामले की जांच शुरू की गई थी।

भारत जोड़ो यात्रा से सुर्खियों में आए थे

कारोबारी मनोज परमार उस वक्त सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ों यात्रा के दौरान छोटे- छोटे बच्चों के साथ राहुल गांधी को गुल्ल के जरिए राशि भेंट की थी। इसके बाद राहुल ने सोशल मीडिया में मनोज परमार और छोटे बच्चों को धन्यवाद देते हुए कहा था कि उन्हें गुल्लक की राशि से माध्यम से अपार प्रेम मिला है। इसके बाद मामले में सीबीआइ और फिर ईडी ने जांच कर कई खुलासे किए।

ट्रेंडिंग न्यूज

पीटीआरआइ

पुलिस चालकों को दिया प्रशिक्षण

भोपाल @ पत्रिका. सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पुलिस आरक्षक चालकों को सुरक्षित वाहन चालन कोर्स के जरिए दो दिनों का प्रशिक्षण पीटीआरआई द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र पर उप पुलिस महानिरीक्षक पीटीआरआई टीके विद्यार्थी द्वारा 4-ई के प्रमुख सूत्र की जानकारी दी गई।

कार्रवाई

एमपीसीए को नोटिस, दे टिकट का ब्योरा

इंदौर @ पत्रिका. होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए क्रिकेट मैच के टिकटों की बिक्री को लेकर उठे सवालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 20 जनवरी को जनसुनवाई में दर्ज शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने एमपीसीए को नोटिस देकर तीन दिन में जवाब मांगा है। भाजपा के पूर्व पार्षद संजय कटारिया ने कलेक्टर शिवम वर्मा से शिकायत की है।

घोषणा

नर्मदा लोक बनाने सीएम को लिखा पत्र

अनूपपुर @ पत्रिका. अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर अमरकंटक में मां नर्मदा लोक का निर्माण कराए जाने के लिए स्मरण पत्र लिखते हुए ध्यान आकृष्ट कराया है। अमरकंटक में भव्य नर्मदा लोक कॉरिडोर का निर्माण करने की घोषणा अगस्त 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक में की थी।

परेशानी | पीएचक्यू ने अब महिला एवं बाल अपराधों की जांच पर जारी किया नया फरमान

प्रदेश के 1173 थानों में सिर्फ 281 महिला एसआइ, 47% पद रिक्त; एक अफसर के भरोसे 15 से अधिक मामलों की जांच

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. प्रदेश में गंभीर महिला और बाल अपराधों से जुड़े मामलों की समय से जांच पूरी करने की राह में महिला पुलिस अधिकारियों की कमी बड़ा रोड़ा बनी है। प्रदेश के 1173 थानों में केवल 831 महिला सब इंस्पेक्टर्स ही पदस्थ हैं। यदि 33 प्रतिशत आरक्षण की बात की जाए तो प्रदेश में अभी 2090 महिला सब इंस्पेक्टर्स और चाहिए। इस लिहाज से प्रदेश में 47 प्रतिशत महिला सब-इंस्पेक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। पद खाली होने के कारण जांच का बोझ अन्य महिला एसआइ पर आता है। लिहाजा स्थिति ये है कि एक इंवेस्टीगेशन ऑफिसर के पास महिला अपराध की 15-15 जांचें हैं। कई अफसर तो 60 जांच तक कर रहे हैं।

फाइल फोटो

महिला अफसरों का ऐसा संकट

- **281** इंस्पेक्टर
- **831** एसआइ
- **47%** पद रिक्त
- **1173** थाने मप्र में
- **2090** एसआइ की प्रदेश में कमी
- **978** नए पदों मांग

बोझ कम करने पीएचक्यू ने किया ये बदलाव

महिला आइओ के ऊपर से जांचों का बोझ कम करने के लिए अब कई अहम अपराधों में केवल महिला सब इंस्पेक्टर (एसआइ) द्वारा ही विवेचना की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। उनके बजाय योग्य एएसआइ को भी विवेचना का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही थाना प्रभारी को महीने में कम से कम एक लैंगिक अपराध की विवेचना जरूर करनी होगी। बता दें कि नए कानूनों के तहत महिला एवं बाल अपराधों की विवेचना के लिए सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर स्तर की महिला अफसर को ही पात्र माना गया था। स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा अनिल कुमार ने महिला अपराधों की विवेचना से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं। इससे जांच प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज हो सकेगी।

उच्च शिक्षा विभाग का आदेश, पाठ्यक्रम में जोड़ी जाएंगी विदेशी भाषाएं

कॉलेजों को शुरू करने होंगे भारतीय और विदेशी भाषाओं के सर्टिफिकेट कोर्स

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

इंदौर. प्रदेश के शासकीय और स्वशासी कॉलेजों में विद्यार्थियों को भाषाई कौशल से जोड़ने के लिए जल्द ही भारतीय और विदेशी भाषाओं के सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। पहले चरण में भारतीय भाषाओं के पाठ्यक्रम लागू होंगे, जिनकी रूपरेखा और संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है।

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों को अलग-अलग भारतीय भाषाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

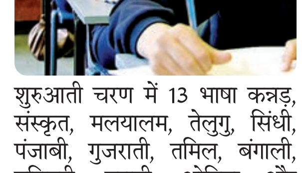

शुरुआती चरण में 13 भाषा कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, बंगाली, मणिपुरी, मराठी, ओड़िया और असमिया के सर्टिफिकेट कोर्स संचालित होंगे। योजना सफल होने पर प्रदेश के सभी कॉलेजों में इनका विस्तार किया जाएगा। आगे चलकर विदेशी भाषाएं भी जोड़ी जाएंगी।

500 रुपए शुल्क

हर सर्टिफिकेट कोर्स 4 क्रेडिट का होगा, जिसकी अवधि 60 घंटे तय की गई है। 6 माह के कोर्स में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। सिलेबस मानक संस्थाओं के अनुरूप बनेगा, जिसके लिए विषय विशेषज्ञों की समितियां गठित की जाएंगी। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से 500 रुपए शुल्क लिया जाएगा। फिलहाल छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है। इसके शुरुआती चरण में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन नोडल स्वशासी कॉलेजों के माध्यम से किया जाएगा।

Last Day to join Private Channel, I am closing it now.

✅ I Give My Earliest Newspapers updates from 5 AM in Private channel with All Editions

♦ Indian Newspaper

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ International Newspapers channel

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ Magazine Channel

National & International
[Genaral & Exam related]

♦ English Editorials

[National + International Editorials]

Click Here